नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, बिहार से प्रसारित

सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number : F.2 (P-2)
Press/2023

www.newsparivahan.com

# परिवहन विशेष

वर्ष 04, अंक 218, नई दिल्ली, गुरुवार 12 नवम्बर 2026, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

नसीबों को कोसने से क्या फायदा, हुनर पाने के लिए हाथ की लकीरें घिसनी पड़ती हैं।

● 03 दुबई में दीवाली पर सोने की रंगोली - भारतीय परंपरा का स्वर्णिम सम्मान
● 06 गद्दारी कर देश से मेरे - कायर दुश्मन को कविता से करारा जवाब
● 08 12 नवंबर 2026 - देशव्यापी स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन

परिवहन विशेष समाचार पत्र को जिस तरह आप लोगों के सहयोग लगातार पिछले 3 वर्षों से प्राप्त हुआ और दिन प्रतिदिन आपकी आवाज को आगे पहुंचाने में आपका सहयोगी बना उसको देखते हुए परिवहन विशेष समाचार पत्र के प्रबंधक मंडल और ट्रांसपोर्ट विशेष न्यूज लिमिटेड कंपनी द्वारा जनहित, जनकल्याण जनसूचना और जानकारी को और तेजी से भारत सरकार और राज्य सरकारों के साथ सभी राजनीतिक संगठनों को सबसे पहले पहुंचाने के उद्देश्य से अक्टूबर माह से जनता की आवाज का अपना चैनल "परिवहन विशेष न्यूज दूरदर्शन" शुरू करने का निर्णय लिया है।

जल्द आपके बीच में....

परिवहन विशेष न्यूज दूरदर्शन

बड़ी खुशखबरी! अब आपकी आवाज गूंजेगी पूरी दुनिया में
परिवहन विशेष समाचार पत्र के सफल 3 वर्षों के बाद अब नई क्रांति

आशा करते हैं जैसे आपने आज के इस दौर मे "परिवहन विशेष समाचार पत्रों" को इतना आगे ले कर जाने में सहयोग दिया उसी प्रकार हमारे द्वारा आपकी आवाज बनने के लिए शुरू किए जा रहे "परिवहन विशेष न्यूज दूरदर्शन" को विश्व का सबसे बड़ा चैनल बनवाएंगे।

संजय बाठला
मुख्य संपादक

# 15 साल से जनता पर सख्ती, फिर भी दिल्ली की हवा क्यों नहीं सुधरी? - गुनाहगार जनता है या व्यवस्था?

## चालान से प्रदूषण खत्म नहीं होगा - पहले सरकार और सरकारी विभागों के आला अधिकारियों को सुधारना होगा - संजय कुमार बाठला

लेखक : संजय कुमार बाठला

**>संपादकीय स्पष्टीकरण:** यह लेख लेखक के मत / विचार के रूप में प्रस्तुत है। इसमें प्रशासनिक व्यवस्था पर उठाए गए सवाल लेखक के आरोप / अनुभव पर आधारित हैं, इन्हें किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध सिद्ध तथ्य न माना जाए। जहाँ न्यायालय, संविधान और कानून का उल्लेख है, वह सत्यापित कानूनी ढांचे पर आधारित है।

**मुख्य तथ्य - एक नज़र में**

**- प्रश्न:** 15 साल से अधिक से दिल्ली की जनता और वाहनों पर सख्ती बरतने के बाद भी क्या दिल्ली की वायु गुणवत्ता सही हो गई?

**- लेखक का उत्तर:** नहीं, हर सर्दी में वायु गुणवत्ता फिर गंभीर श्रेणी में पहुंच जाती है

**- नवंबर 2026 में:** सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान CAQM की रिपोर्ट में वाहन प्रदूषण को दिल्ली-NCR में सबसे बड़ा योगदानकर्ता बताया गया, सर्दी में लगभग 23% और गर्मी में लगभग 19%

**- पराली का योगदान:** सुनवाई में 5 नवंबर को लगभग 14% बताया गया

**- AQI:** सुनवाई के दौरान दिल्ली का AQI लगभग 391-400 के आसपास बताया गया

**- लेखक की मांग:** कार्रवाई जनता पर नहीं, पहले सरकार और सरकारी विभागों के आला अधिकारियों पर हो, अतिक्रमण, अवैध पार्किंग, अवैध कब्जा, धूल-मिट्टी पर रोक लगे

**1. 15 साल की सख्ती का हिसाब कौन देगा? दिल्ली की जनता ने क्या नहीं सहा?**

- वाहन बंद हुए
- चालान कटे
- PUC, परमिट, फिटनेस के नाम पर जांच बढ़ी
- ऑड-ईवन, GRAP, निर्माण पर रोक, स्कूलों पर रोक

फिर भी हर साल वही तस्वीर - धुंध, खांसी, आंखों में जलन, अस्पतालों में भीड़।

लेखक का सवाल सीधा है - अगर जनता ही गुनाहगार थी, तो 15 साल की सख्ती के बाद दिल्ली की हवा साफ हो जानी चाहिए थी। नहीं हुई, तो मतलब गुनाहगार कहीं और है।

सिर्फ चालान से प्रदूषण खत्म नहीं होगा। अरबों-खरबों रुपये चालान और गलती के नाम पर बटोर लेने से हवा साफ नहीं होती, व्यवस्था साफ करनी पड़ती है।

2. संविधान क्या कहता है? - साफ हवा मूल अधिकार है यह कोई दया नहीं, संविधान का अधिकार है।

अनुच्छेद 21 - जीवन का अधिकार: सर्वोच्च न्यायालय ने बार-बार कहा है कि अनुच्छेद 21 में जीवन का अर्थ सिर्फ सांस लेना नहीं, गरिमा के साथ जीना है। इसमें प्रदूषण-मुक्त हवा और पानी का अधिकार शामिल है।

Subhash Kumar बनाम बिहार राज्य (1991): न्यायालय ने कहा - जीवन के अधिकार में प्रदूषण-मुक्त हवा और पानी का आनंद लेना शामिल है।

M.C. Mehta बनाम भारत संघ (1986 से आगे): दिल्ली प्रदूषण पर सबसे लंबी सुनवाई, इसी में प्रदूषण-मुक्त पर्यावरण को अनुच्छेद 21 का हिस्सा माना गया, Polluter Pays और Precautionary Principle जैसे सिद्धांत भारतीय कानून में आए।

**अनुच्छेद 48A - राज्य का कर्तव्य:**
राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार का प्रयास करेगा, वनों और वन्य जीवों की रक्षा करेगा।

अनुच्छेद 51A(g) - नागरिक का मौलिक कर्तव्य: हर नागरिक का कर्तव्य है कि वह प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करे, वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीवों के प्रति दया रखे।

अनुच्छेद 14 - समानता का अधिकार: कानून सब पर समान लागू होगा। गरीब पर एक नियम, प्रभावशाली पर दूसरा नियम - यह अनुच्छेद 14 की भावना के विरुद्ध है। यही लेखक के अतिक्रमण वाले सवाल की संवैधानिक जड़ है।

अनुच्छेद 32 और 226: मूल अधिकार के उल्लंघन पर नागरिक सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय जा सकता है।

मतलब साफ है - साफ हवा देना सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है, जनता पर एहसान नहीं।

**3. कानून क्या कहते हैं? - कानून की कमी नहीं, लागू करने की कमी है**

1. वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981: वायु प्रदूषण रोकने, प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को शक्ति देने का कानून।

2. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986: भोपाल गैस त्रासदी के बाद बना, केंद्र को पर्यावरण मानक बनाने, दिशा-निर्देश देने की व्यापक शक्ति देता है।

3. मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (संशोधित 2019): वाहनों के प्रदूषण मानक, PUC, फिटनेस, चालान, परमिट की व्यवस्था। इसी के तहत वाहनों पर कार्रवाई होती है।

4. CAQM अधिनियम, 2021 - वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग: दिल्ली-NCR में वायु गुणवत्ता के लिए विशेष आयोग, GRAP लागू करने, निर्देश देने की शक्ति।

5. GRAP - Graded Response Action Plan: AQI के अनुसार चरणबद्ध कार्रवाई - वाहन रोक, निर्माण रोक, कार्यालयों में वर्क फ्रॉम होम आदि। नवंबर 2026 में GRAP चरण-III भी लागू हुआ, जिसमें BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल चार पहिया वाहनों पर रोक लगी।

**लेखक का तर्क:** कानून, आयोग, GRAP, न्यायालय - सब हैं। फिर भी हवा नहीं सुधरी, तो कमी कानून में नहीं, लागू करने वाली व्यवस्था में है।

4. सर्वोच्च न्यायालय और एमिकस क्यूरी - क्या सच सामने आ रहा है? नवंबर 2026 में सर्वोच्च न्यायालय में दिल्ली-NCR प्रदूषण पर स्वतः संज्ञान (Suo Motu) सुनवाई हुई।

**सुनवाई में सामने आए तथ्य:**

- एमिकस क्यूरी वरिष्ठ अधिवक्ता अपराजिता सिंह ने कहा - दिल्ली की हवा में सांस लेना रोज लगभग 30 सिगरेट पीने जैसा बताया गया, पराली का योगदान 5 नवंबर को लगभग 14% था
- CAQM की रिपोर्ट में वाहन प्रदूषण को सबसे बड़ा योगदानकर्ता बताया गया
- न्यायालय ने कहा - अस्थायी रोक, वाहन बंदी, निर्माण बंदी जैसे उपाय पुराने, आजमाए हुए और असफल उपाय हैं
- न्यायालय ने दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, MCD, दिल्ली पुलिस को 2 हफ्ते में वाहनों के नियमन, PUC, ओवरएज वाहनों पर कार्रवाई का विस्तृत जवाब और समयबद्ध रोडमैप देने को कहा
- न्यायालय ने यह भी कहा - दिल्ली की सीमा पर वाहनों को रोककर इंजन चालू रखना भी प्रदूषण बढ़ाता है, टोल पर जाम नहीं होना चाहिए

**लेखक का सवाल: जब न्यायालय खुद कह रहा है कि**

अस्थायी उपाय असफल हैं, तो फिर हर साल वही अस्थायी उपाय जनता पर क्यों थोपे जाते हैं?

स्थायी व्यवस्था - सड़क, धूल, अतिक्रमण, सार्वजनिक परिवहन - पर कार्रवाई क्यों नहीं होती?

एमिकस क्यूरी न्यायालय की मित्र होती हैं, पक्षकार नहीं। उनका काम न्यायालय को तथ्य देना है।

लेखक की अपेक्षा है कि एमिकस क्यूरी और न्यायालय का ध्यान सिर्फ वाहन और पराली तक सीमित न रहे, बल्कि सड़क पर कब्जा, धूल, निर्माण मलबा, अवैध पार्किंग जैसे स्थानीय स्रोतों पर भी जाए, जो रोज की सांस को खराब करते हैं।

यह मांग न्यायालय के सम्मान के साथ है - गुनाहगार चाहे कोई हो, कार्रवाई उसी पर हो।

5. CNG वाली कहानी - क्या सच बोला गया था? लेखक का एक पुराना सवाल आज भी अनुत्तरित है।

**सत्यापित इतिहास:**

- 28 जुलाई 1998 को सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से दिल्ली में वाणिज्यिक वाहनों को CNG में बदलने की प्रक्रिया शुरू हुई
- दिसंबर 2002 तक दिल्ली की सिटी बसें डीजल से CNG में बदल गईं
- उस समय कहा गया - CNG स्वच्छ ईंधन है, दिल्ली की हवा सुधरेगी




लेखक का सवाल:

- अगर CNG प्रदूषण-मुक्त थी, तो आज दिल्ली प्रदूषित वाहनों के कारण कैसे प्रदूषित है?
- अगर CNG प्रदूषण-मुक्त नहीं थी, तो झूठ बोलकर उसे दिल्ली में लाने वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई?

**संपादकीय संतुलन:** CNG ने डीजल के मुकाबले धुआं और कण प्रदूषण कम किया, यह अध्ययन में आया। लेकिन CNG अकेली दिल्ली को प्रदूषण-मुक्त नहीं कर सकी, क्योंकि वाहनों की संख्या, धूल, निर्माण, उद्योग, पराली - सब बढ़ते गए।

इसलिए CNG को झूठ या सच में बांटने से ज्यादा जरूरी सवाल यह है - एक ईंधन बदलने से व्यवस्था नहीं बदलती। बसों की संख्या, सार्वजनिक परिवहन, सड़क की धूल - इन पर स्थायी काम नहीं हुआ।

6. असली गुनाहगार कौन? - लेखक की सूची पर विस्तृत विश्लेषण लेखक के अनुसार दिल्ली की सड़कों पर जो दिखता है, वह जनता नहीं करवाती, व्यवस्था की लापरवाही से होता है:

1. सड़कों पर अतिक्रमण: फुटपाथ पर दुकान, सड़क पर सामान, चौराहों पर कब्जा - इससे जाम लगता है, वाहन रुक-रुक कर चलते हैं, ईंधन जलता है, प्रदूषण बढ़ता है।

2. अवैध पार्किंग: जहां पार्किंग नहीं, वहां वाहन खड़े होते हैं, सड़क सिकुड़ जाती है, जाम बढ़ता है।

3. अवैध कब्जे, अवैध रेहड़ी-पटरी, खोखे, खोमचे: लेखक का आरोप है कि इनके पीछे वसूली और संरक्षण की व्यवस्था है, जिसकी जांच होनी चाहिए। गरीब रेहड़ी वाले को हटाना आसान है, लेकिन उसे जगह देने और व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी किसकी है, यह सवाल भी है।

4. अनाधिकृत वाहन: बिना परमिट, बिना PUC, बिना फिटनेस वाले वाहन सड़क पर कैसे चलते हैं? यह जांच का विषय है कि इन पर रोक क्यों नहीं लगती।

5. धूल-मिट्टी, गंदगी का अंबार: निर्माण मलबा, टूटी सड़कें, खुले कूड़े, धूल उड़ती सड़कें - यह वाहन प्रदूषण से कम खतरनाक नहीं। GRAP में निर्माण रोक तो दी जाती है, लेकिन धूल हटाने की स्थायी व्यवस्था क्यों नहीं होती?

**लेखक का निष्कर्ष:** इन सबके रहते कितना भी सही आदेश पारित हो, प्रदूषण-मुक्त दिल्ली नहीं हो सकती।

**संपादकीय टिप्पणी:** इन आरोपों की पुष्टि के लिए प्रत्येक मामले में दस्तावेज, नक्शा, अनुमति, जांच रिपोर्ट देखनी होगी। लेकिन सवाल जायज है - अतिक्रमण हटाना सिर्फ गरीब पर ही क्यों, सब पर समान क्यों नहीं?

7. जनता से अधिक राजस्व खोजने वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं? लेखक का सबसे तीखा सवाल यही है।

दिल्ली को जाम-मुक्त, हादसा-मुक्त, प्रदूषण-मुक्त करने के लिए जनता से अधिक, जनता से राजस्व बढ़ाने का रास्ता खोजने वालों पर कार्रवाई की जरूरत है।

**मतलब:**

- चालान का लक्ष्य पूरा करना सफलता नहीं है
- सड़क साफ करना सफलता है
- वाहन रोकना सफलता नहीं है
- सार्वजनिक परिवहन बढ़ाना सफलता है
- गरीब को हटाना सफलता नहीं है
- गरीब को विकल्प देना सफलता है

Polluter Pays का अर्थ यह नहीं है कि सिर्फ जनता भुगतान करे। Polluter Pays का अर्थ है कि प्रदूषण फैलाने वाला, चाहे वह व्यक्ति हो, संस्था हो, ठेकेदार हो या विभाग हो, वह जिम्मेदार होगा।

**8. जनहित में 7 मांगें - संपादकीय प्रस्ताव**

1. पहले विभाग, फिर जनता: अतिक्रमण, अवैध पार्किंग, धूल, कूड़ा - इसके लिए जिम्मेदार विभागों की जवाबदेही तय हो, अधिकारीवार रिपोर्ट सार्वजनिक हो।
2. समान कानून: गरीब की रेहड़ी और बड़े भवन के अतिक्रमण पर एक ही नियम, एक ही कार्रवाई।
3. धूल-मुक्त सड़क: हर सड़क की सफाई, धुलाई, गड्ढा भरने की समयबद्ध जिम्मेदारी, फोटो सहित रिपोर्ट।
4. सार्वजनिक परिवहन बढ़े: बसों की संख्या बढ़े, फीडर सेवा मजबूत हो, ताकि लोग निजी वाहन छोड़ सकें।
5. चालान का हिसाब सार्वजनिक हो: कितना चालान वसूला, कितना प्रदूषण घटा - दोनों का हिसाब जनता को मिले।
6. GRAP अस्थायी नहीं, स्थायी हो: सर्दी में ही नहीं, साल भर वायु गुणवत्ता सुधार की योजना हो।
7. न्यायालय को पूरी तस्वीर मिले: एमिकस क्यूरी के सामने सिर्फ वाहन-पराली नहीं, सड़क, धूल, अतिक्रमण, निर्माण मलबे की भी पूरी रिपोर्ट रखी जाए।

**9. संपादकीय निष्कर्ष** दिल्ली की हवा सिर्फ मौसम की समस्या नहीं, व्यवस्था की परीक्षा है।

15 साल से जनता पर सख्ती हुई, लेकिन व्यवस्था पर सख्ती नहीं हुई। इसलिए हवा नहीं सुधरी।

साफ हवा अनुच्छेद 21 का मूल अधिकार है। इसे चालान से नहीं, जवाबदेही से मिलेगा।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय और एमिकस क्यूरी से लेखक की विनम्र अपेक्षा है - सच्चाई की ओर ध्यान दें, गुनाहगार चाहे जनता हो या व्यवस्था, कार्रवाई उसी पर हो, लेकिन गरीब जनता को ही हर बार गुनाहगार न माना जाए।

प्रदूषण-मुक्त दिल्ली के लिए पहले सरकार और सरकारी विभागों को सुधारना होगा - यही प्रथम दृष्टि में आवश्यक है।

**- संजय कुमार बाठला,**
**प्रधान संपादक**

# बाहरी दिल्ली के नांगलोई में खुला मैनहोल निगल गया 4 साल का मासूम - कौन देगा जवाब?

**दास गार्डन कॉलोनी में खेलते-खेलते बच्चा गिरा, NDRF, फायर, पुलिस, DDMA और BSF का संयुक्त रेस्क्यू जारी - दिल्ली सरकार, MCD की लापरवाही कब तक बच्चों की जान लेती रहेगी?**

**- लेखक : संजय कुमार बाठला**
**- संपादकीय विभाग, परिवहन विशेष समाचार पत्र दैनिक नांगलोई, बाहरी दिल्ली।**

**मुख्य तथ्य - एक नज़र में**

- घटना स्थल: दास गार्डन कॉलोनी, नांगलोई / नांगली विहार इलाका, बाहरी दिल्ली
- पीड़ित: 4 वर्षीय बच्चा, खेलते-खेलते खुले मैनहोल में गिरा - रिपोर्ट के अनुसार
- रेस्क्यू में लगी एजेंसियां: NDRF, दिल्ली फायर सर्विस, दिल्ली पुलिस, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA), BSF - संयुक्त ऑपरेशन
- लेखक का सवाल: दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम की गलतियां कब तक बच्चों की जिंदगियों को खतरे में डालती रहेंगी?
- दूसरा सवाल: क्या है कोई जवाब या जिम्मेदारी?
- तीसरा सवाल: व्यापिक प्रणाली भी ऐसे अधिकारियों को सज़ा देने में क्यों चुप रहती है?

**>संपादकीय स्पष्टीकरण:** यह रिपोर्ट समाचार रिपोर्टों और मौके पर अधिकारियों के बताए अनुसार तथ्यों पर आधारित है। बच्चे की स्थिति और रेस्क्यू के अंतिम परिणाम की आधिकारिक पुष्टि संबंधित एजेंसियों से ही होगी। अधिकारियों पर लगाए गए आरोप लेखक के सवाल हैं, न्यायालय का फैसला नहीं।

**1. क्या हुआ - घटना का विवरण**

बाहरी दिल्ली के नांगलोई इलाके में दास गार्डन कॉलोनी में इस समय अफरा-तफरी मच गई जब वहां एक खुले मैनहोल में चार साल का बच्चा गिर गया।

बताया जा रहा है कि बच्चा खेलते-खेलते अचानक इस हादसे का शिकार हो गया।

मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने बताया कि बाहरी दिल्ली के नांगली विहार इलाके में दास गार्डन कॉलोनी के पास एक खुले मैनहोल में चार वर्षीय बच्चे के गिरने के बाद एक व्यापक बहु-एजेंसी खोज और बचाव अभियान शुरू किया गया है।

ठीक में मौके पर तैनात हैं और बच्चे को ढूंढने और निकालने के लिए गहन खोज अभियान चला रही हैं। अग्निशमन अधिकारियों के अनुसार, यह घटना तब हुई जब बच्चा खेल रहा था और गलती से एक खुले मैनहोल में फिसल गया।

फिलहाल मौके पर NDRF, दिल्ली फायर सर्विस, दिल्ली पुलिस, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और BSF का संयुक्त रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है।

यह सिर्फ एक हादसा नहीं है, यह व्यवस्था की खुली विफलता है।

1. मैनहोल खुला क्यों था?
2. ढक्कन कहां था?
3. चोरी हुआ था, टूटा था या लगाया ही नहीं गया था?
4. इसका जवाब कौन देगा?

**१. यह सिर्फ नांगलोई की घटना नहीं है - दिल्ली का पुराना जख्म दिल्ली में यह पहली घटना नहीं है।**

हर बारिश में, हर साल - खुला मैनहोल, खुला नाला, टूटी जाली, बिना ढक्कन का सीवर - किसी न किसी मासूम की जान लेता है। कभी मयूर विहार, कभी द्वारका, कभी रोहिणी, कभी नांगलोई।

**पैटर्न एक ही है:**

1. मैनहोल खुला रहता है
2. कोई शिकायत नहीं सुनता
3. बच्चा गिरता है
4. रेस्क्यू होता है, कैमरे आते हैं
5. जांच के आदेश होते हैं
6. फिर सब भूल जाते हैं, अगली घटना तक

सवाल यही है - दिल्ली सरकार, दिल्ली नगर निगम की गलतियां कब तक बच्चों की जिंदगियों को खतरे में डालती रहेंगी?

**३. संविधान क्या कहता है - बच्चे के मूल अधिकार**

यह घटना संविधान के सबसे बड़े अधिकार से जुड़ी है - जीने का अधिकार।

**1. अनुच्छेद 21** - प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार - किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना जीवन से वंचित नहीं किया जा सकता।

- सुप्रीम कोर्ट ने कहा है - अनुच्छेद 21 में सुरक्षित जीवन, सम्मानजनक जीवन, स्वच्छ पर्यावरण, स्वास्थ्य भी शामिल है।
- खुला मैनहोल छोड़ना, बच्चे की जान को खतरे में डालना, अनुच्छेद 21 का सीधा उल्लंघन है।

**२. अनुच्छेद 21A** - शिक्षा का अधिकार

- 6-14 वर्ष के बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा का अधिकार, लेकिन बच्चा जीवित रहेगा तभी तो पढ़ेगा।

**३. अनुच्छेद 39(e) और (f) - राज्य के नीति निर्देशक तत्व**

- राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि बच्चों की कोमल अवस्था का दुरुपयोग न हो, बच्चों को स्वस्थ विकास के अवसर मिलें, उनका शोषण न हो।
- खुला मैनहोल बच्चों के स्वस्थ विकास के खिलाफ है।

**4. अनुच्छेद 47** - पोषण, जीवन स्तर और लोक स्वास्थ्य

- राज्य का कर्तव्य है लोक स्वास्थ्य को सुधारना, लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा करना।

**5. अनुच्छेद 48A** - पर्यावरण संरक्षण

- राज्य पर्यावरण, वन और वन्य जीवों की रक्षा करेगा। साफ-सुथरी, सुरक्षित सड़क और नाली भी इसी में आती है।

**6. अनुच्छेद 51A(g)** - नागरिकों का मूल कर्तव्य

- हर नागरिक का कर्तव्य है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना। लेकिन नागरिक शिकायत करे तो सुनवाई कौन करेगा?

**7. अनुच्छेद ३२ और १२६ - संवैधानिक उपचार**

- पीड़ित परिवार सुप्रीम कोर्ट (अनुच्छेद ३२) और हाईकोर्ट (अनुच्छेद १२६) में रिट दायर कर मुआवजा, जांच और कार्रवाई की मांग कर सकता है।

संविधान साफ कहता है - बच्चे की जान राज्य की जिम्मेदारी है, दया नहीं।

**4. कानून, अधिनियम, नियम - किस पर क्या जिम्मेदारी है?**

A. दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 (DMC Act) - संशोधित

- धारा 42, 43 - निगम का कर्तव्य है सड़कों, नालियों, सीवर, मैनहोल का निर्माण और रखरखाव।
- धारा 317-३२१ - खतरनाक, असुरक्षित निर्माण, खुली नाली पर कार्रवाई।
- धारा 400-402 - निगम अधिकारी की लापरवाही पर दंड, निगम पर मुआवजे का दायित्व।
- दिल्ली में MCD ही सीवर, नाली, मैनहोल ढक्कन का मुख्य रखरखावकर्ता है।

B. दिल्ली जल बोर्ड अधिनियम, 1998

- दिल्ली जल बोर्ड को सीवर लाइन, मैनहोल, जल आपूर्ति का रखरखाव करना है।
- अगर मैनहोल DJB का है तो जिम्मेदारी DJB की, अगर MCD का है तो MCD की - लेकिन जनता को यह नहीं पता, उसे तो सुरक्षित सड़क चाहिए।

C. आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005

- धारा 6, 18, २१ - NDMA, SDMA, DDMA का कर्तव्य है आपदा से पहले तैयारी, रोकथाम और बाद में रेस्क्यू।
- DDMA, दिल्ली का कर्तव्य है ऐसे खतरनाक स्थानों की पहचान कर पहले ही बंद करवाना।
- इस घटना में DDMA रेस्क्यू में है, लेकिन रोकथाम में क्यों नहीं थी?

D. भारतीय न्याय संहिता, २०२३ (BNS) - पहले IPC

- धारा 106 - लापरवाही से मृत्यु - 5 वर्ष तक कारावास, जुर्माना
- धारा 125 - दूसरों के जीवन को खतरे में डालने वाला कार्य - जानबूझकर लापरवाही
- धारा 125(a), 125(b) - लापरवाही से चोट पहुंचाना
- धारा 198, 197 - लोक सेवक द्वारा कर्तव्य में लापरवाही, नियम विरुद्ध कार्य
- अगर जांच में पता चलता है कि अधिकारी को पता था मैनहोल खुला है और उसने कार्रवाई नहीं की, तो यह आपराधिक लापरवाही है।

**E. सिविल दायित्व - टॉर्ट कानून**

- सरकारी विभाग की लापरवाही से मौत/चोट होने पर परिवार को मुआवजा मिलता है। सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में निगम को मुआवजा देने का आदेश दिया है।

**F. बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम, २००5**

- राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) और दिल्ली बाल अधिकार आयोग (DCPCR) बच्चे के अधिकारों की रक्षा के लिए जांच कर सकते हैं, सरकार से रिपोर्ट मांग सकते हैं।

G. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 और NGT अधिनियम, 2010

- असुरक्षित सीवर, खुले मैनहोल से पर्यावरण और जन स्वास्थ्य को खतरा - NGT भी संज्ञान ले सकता है।

**5. न्यायिक आदेश - सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट पहले ही कह चुके हैं**

1. एम. सी. मेहता बनाम भारत संघ - सुप्रीम कोर्ट




- दिल्ली में प्रदूषण, सीवर, सफाई, सुरक्षित सड़क पर कई आदेश। कोर्ट ने कहा - नगर निगम और सरकार की जिम्मेदारी है कि वह जनता को सुरक्षित वातावरण दे।

२. दिल्ली हाईकोर्ट - खुले मैनहोल पर आदेश

- दिल्ली हाईकोर्ट ने कई बार MCD और DJB को आदेश दिया है - सभी मैनहोल के ढक्कन लगाएं, GPS मैपिंग करें, हेल्पलाइन बनाएं, हर 15 दिन में निरीक्षण करें।
- कोर्ट ने कहा है - खुला मैनहोल छोड़ना आपराधिक लापरवाही है।

**३. सुप्रीम कोर्ट - मैनुअल स्कैवेंजिंग / सीवर मृत्यु पर आदेश**

- सीवर में मौत पर 10 लाख रुपये न्यूनतम मुआवजा और अधिकारी पर कार्रवाई का आदेश।
- २०२३ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा - सीवर मौत रोकना राज्य का संवैधानिक कर्तव्य है, सिर्फ मुआवजा देना काफी नहीं।

4. दिल्ली हाईकोर्ट - नांगलोई, द्वारका, रोहिणी मामलों में

- खुले नाले में बच्चे की मौत पर कोर्ट ने MCD को मुआवजा देने और अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच का आदेश दिया था।
- कोर्ट ने कहा - "एक बच्चे की मौत भी व्यवस्था की हार है।"

**5. राजपत्रित अधिसूचनाएं / सरकारी आदेश**

- स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) २.0 - राजपत्र अधिसूचना, २०२१ - सभी शहरों में मैनहोल, सीवर का सुरक्षित रखरखाव, ढक्कन अनिवार्य।
- दिल्ली सरकार - आपदा प्रबंधन अधिसूचना - DDMA को मानसून से पहले सभी खतरनाक मैनहोल, नालों की सूची बनानी है।
- CPWD मैनुअल और IS 1726:1991 - मैनहोल ढक्कन का भारतीय मानक - ढक्कन की मजबूती, भार क्षमता, लॉकिंग अनिवार्य।
- दिल्ली नगर निगम - सीवर रखरखाव SOP - हर मैनहोल पर ढक्कन, चेतावनी बोर्ड, रात में रिफ्लेक्टर अनिवार्य।

**फिर भी खुला मैनहोल क्यों? आदेश तो हैं, पालन क्यों नहीं?**

6. व्यापिक प्रणाली चुप क्यों रहती है? - लेखक का बड़ा सवाल - आखिर व्यापिक प्रणाली भी क्यों रहती है चुप ऐसे अधिकारियों को सज़ा देने में?

**संपादकीय विश्लेषण - 4 कारण:**

1. जिम्मेदारी तय नहीं होती: MCD कहता है DJB का है, DJB कहता है PWD का है, PWD कहता है ठेकेदार का है। फाइल घूमती रहती है, बच्चा चला जाता है।
२. विभागीय जांच में देरी: FIR होती है, लेकिन विभागीय जांच २-३ साल चलती है, अधिकारी रिटायर हो जाता है, सज़ा नहीं होती।
3. मुआवजा ही सज़ा बन जाता है: सरकार मुआवजा देकर मामला बंद कर देती है, अधिकारी पर आपराधिक कार्रवाई नहीं होती। मुआवजा व्याय नहीं है, व्याय है सज़ा और सुधार।
4. स्वत: संज्ञान कम: हाईकोर्ट कई बार स्वत: संज्ञान लेता है, लेकिन हर घटना पर स्वत: संज्ञान नहीं हो पाता। पीड़ित परिवार गरीब होता है, वकील नहीं कर पाता। लेकिन व्यापिक प्रणाली पूरी तरह चुप नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कई बार अधिकारियों को फटकार लगाई है। कमी पालन में है, आदेश में नहीं।

**7. जिम्मेदारी किसकी - साफ जवाब**

**प्राथमिक जिम्मेदारी:**

- दिल्ली नगर निगम (MCD) - सड़क, नाली, मैनहोल ढक्कन का रखरखाव
- दिल्ली जल बोर्ड (DJB) - सीवर लाइन, सीवर मैनहोल
- PWD, दिल्ली - बड़ी सड़कों पर मैनहोल
- ठेकेदार - जिसने काम किया, ढक्कन लगाया या नहीं लगाया
- दिल्ली सरकार - निगरानी, बजट, जवाबदेही
- DDMA - आपदा से पहले रोकथाम, खतरनाक स्थानों की पहचान

अगर मैनहोल खुला था, तो जिम्मेदारी सामूहिक है, लेकिन सज़ा किसी एक को भी नहीं - यही सबसे बड़ी विफलता है।

**8. जनहित में 10 मांग - परिवहन विशेष की ओर से**

1. तत्काल FIR और जांच: BNS धारा 106, 125 के तहत FIR, 30 दिन में चार्जशीट, अधिकारी और ठेकेदार दोनों पर कार्रवाई।
२. मैनहोल ऑडिट: 15 दिन में दिल्ली के सभी मैनहोल की GPS मैपिंग, फोटो के साथ सूची सार्वजनिक हो, वाहन पोर्टल की तरह मैनहोल पोर्टल बने।
३. ढक्कन की चोरी रोकें: ढक्कन पर QR कोड, RFID, लॉकिंग सिस्टम - चोरी होने पर तुरंत अलर्ट।
4. हेल्पलाइन और ऐप: खुला मैनहोल दिखे तो १५५३०३, MCD ऐप पर फोटो भेजें, २4 घंटे में बंद होना अनिवार्य, नहीं तो अधिकारी पर जुर्माना।
5. मुआवजा नहीं, न्याय: पीड़ित परिवार को तत्काल २5 लाख रुपये सहायता, बच्चे की शिक्षा, परिवार की सुरक्षा - लेकिन साथ में अधिकारी पर आपराधिक कार्रवाई भी।
6. विभागीय कार्रवाई में समय सीमा: जांच 90 दिन में पूरी हो, अधिकारी को निलंबित किया जाए, रिटायरमेंट से सज़ा न बचे।
7. DDMA की रोकथाम: मानसून से पहले हर साल मैनहोल, नालों का सुरक्षा ऑडिट, रिपोर्ट हाईकोर्ट में जमा हो।
8. बाल अधिकार आयोग की जांच: DCPCR और NCPCR इस घटना की स्वतंत्र जांच करें।
9. जनता की भागीदारी: हर कॉलोनी में RWA को मैनहोल की निगरानी का अधिकार, शिकायत पर कार्रवाई न हो तो RWA सीधे हाईकोर्ट जा सके।
10. सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन: मैनुअल स्कैवेंजिंग, सीवर स

# कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण : हृदय को स्वस्थ रखने के लिए सही आहार, व्यायाम और जीवनशैली!

पिंकी कुंडू सामाजिक परामर्शदाता

स्वस्थ हृदय, स्वस्थ जीवन !

* कोलेस्ट्रॉल क्या है ?
* इसके बढ़ने से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ते हैं ? और
* इसे प्राकृतिक तरीके से नियंत्रित रखने के लिए क्या करना चाहिए ?

इन सभी बातों की सही जानकारी होना बेहद जरूरी है।

कोलेस्ट्रॉल क्या है ? कोलेस्ट्रॉल शरीर के लिए आवश्यक वसा जैसा पदार्थ है। यह शरीर की कोशिकाओं के निर्माण, कुछ हार्मोन बनाने और विटामिन D के निर्माण में मदद करता है। लेकिन जब रक्त में इसका स्तर असंतुलित हो जाता है, तो हृदय रोग और स्ट्रोक का खतरा बढ़ सकता है।

LDL – बैड कोलेस्ट्रॉलः इसका स्तर अधिक होने पर रक्त वाहिकाओं की दीवारों में वसा की परत जमा हो सकती है।

HDL – गुड कोलेस्ट्रॉलः यह अतिरिक्त कोलेस्ट्रॉल को वापस लिवर तक पहुंचाने में मदद करता है।

ट्राइग्लिसराइड्सः यह रक्त में पाई जाने वाली वसा का एक अन्य महत्वपूर्ण प्रकार है। इसका स्तर बढ़ना भी स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकता है।

1. कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए सही आहर फाइबर युक्त खाद्य पदार्थों को शामिल करें।

1. ओट्स, अलसी, दालें और अंकुरित अनाज।

2. हरी पत्तेदार सब्जियां, फल और साबुत अनाज।

3. रागी, ज्वार और अन्य फाइबर युक्त अनाज।

घुलनशील फाइबर आंतों में कोलेस्ट्रॉल के अवशोषण को कम करने में मदद करता है।

सूखे मेवे सीमित मात्रा में खाएं। बादाम, अखरोट और बिना नमक या चीनी वाले अन्य सूखे मेवे उचित मात्रा में खाने से हृदय के स्वास्थ्य को लाभ मिल सकता है।

अच्छे प्रकार की वसा का चुनाव करें। मूंगफली, सरसों, सूरजमुखी या अन्य असंतृप्त वसा वाले तेलों का सीमित उपयोग करें। तेल की मात्रा भी महत्वपूर्ण है। किसी भी तेल का अधिक सेवन उचित नहीं है।

इन खाद्य पदार्थों का सेवन कम करें।

1. वनस्पति घी और ट्रांस फैट वाले पदार्थ।

2. बार-बार तले हुए खाद्य पदार्थ, नमकीन और फास्ट फूड।

3. अधिक मलाई वाले डेयरी उत्पाद और मक्खन।

4. प्रोसेस्ड मीट और अधिक वसा वाला लाल मांस।

5. अधिक चीनी वाले खाद्य पदार्थ, मीठे पेय और मैदे से बनी चीजें।

**2. घरेलू उपायों की सच्चाई**

1. लहसुनः भोजन में लहसुन शामिल किया जा सकता है, लेकिन यह कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवाओं का विकल्प नहीं है।

2. मेथी दानाः सीमित मात्रा में आहार में शामिल किया जा सकता है। कोलेस्ट्रॉल पर इसका प्रभाव सीमित हो सकता है। डायबिटीज की दवाएं लेने वाले लोगों को विशेष सावधानी रखनी चाहिए।

3. अलसी के बीजः इनमें फाइबर और वनस्पति आधारित ओमेगा-3 पाया जाता है। संतुलित आहार में इनका सेवन उपयोगी हो सकता है।

4. अर्जुन की छालः आयुर्वेद में इसका पारंपरिक उपयोग हृदय स्वास्थ्य के लिए किया जाता है। हालांकि, कोलेस्ट्रॉल कम करने में इसकी प्रभावशीलता के वैज्ञानिक प्रमाण सीमित हैं। डॉक्टर की सलाह के बिना इसे दवा के रूप में न लें।

5. गुनगुना पानीः पानी पीना शरीर के लिए आवश्यक है, लेकिन गुनगुना पानी सीधे कोलेस्ट्रॉल को पिघला देता है या रक्त वाहिकाओं की रुकावट दूर करता है, इसका कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।

**3. जीवनशैली में करें ये महत्वपूर्ण बदलाव**

1. हर सप्ताह कम से कम 150 मिनट मध्यम तीव्रता वाला व्यायाम करें। उदाहरण के लिए, सप्ताह में पांच दिन रोजाना 30 मिनट तेज चलें।

2. वजन अधिक है तो धीरे-धीरे और स्वस्थ तरीके से वजन कम करें।

3. धूम्रपान और तंबाकू से दूर रहें। शराब का सेवन न करना अधिक सुरक्षित विकल्प है।

4. नियमित नींद लें और तनाव कम करने के लिए योग, ध्यान और श्वास संबंधी व्यायाम करें।

4. कोलेस्ट्रॉल की जांच क्यों जरूरी है ? कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर भी कई बार शरीर में कोई लक्षण दिखाई नहीं देते। इसलिए लिपिड प्रोफाइल ब्लड टेस्ट करवाकर LDL, HDL और ट्राइग्लिसराइड्स का स्तर जांचना महत्वपूर्ण है।

कोलेस्ट्रॉल का सही लक्ष्य स्तर प्रत्येक व्यक्ति की उम्र, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, पहले हुए हृदय रोग और हृदय रोग के कुल जोखिम पर निर्भर करता है।

दवाओं के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना यदि डॉक्टर ने स्टैटिन या कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली अन्य दवाएं दी हैं, तो उन्हें अपनी मर्जी से बंद न करें और न ही उनकी खुराक बदलें।

कुछ लोगों के लिए केवल खान-पान और व्यायाम पर्याप्त नहीं होते। ऐसे में हृदय रोग का खतरा कम करने के लिए दवाएं बेहद महत्वपूर्ण हो सकती हैं।

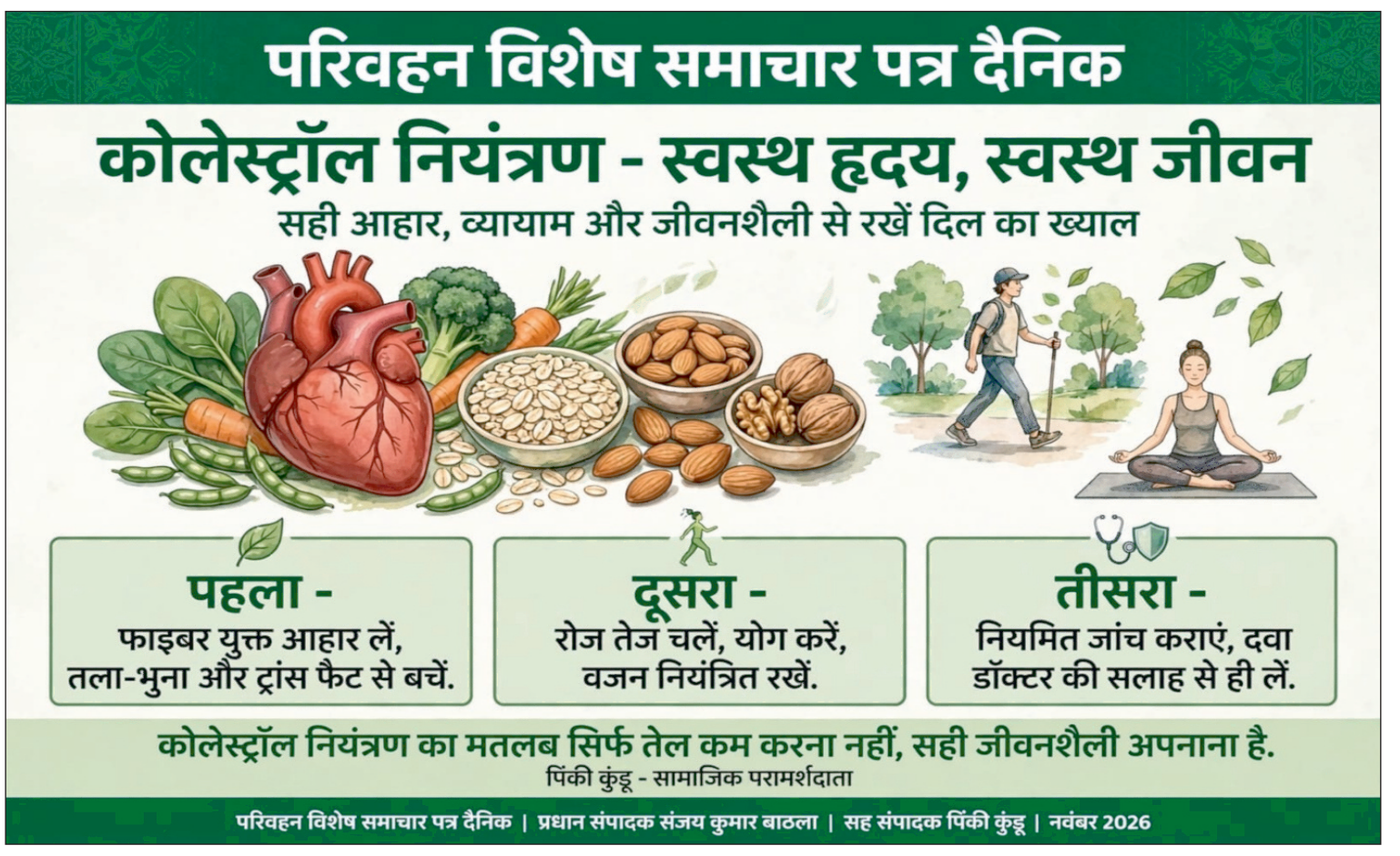
आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान का संतुलन आयुर्वेद में बताई गई दिनचर्या, संतुलित आहार, नियमित शारीरिक गतिविधि और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी अच्छी आदतें स्वस्थ जीवनशैली अपनाने में मदद कर सकती हैं।

हालांकि, रक्त में कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखने के लिए वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित आहार परिवर्तन, व्यायाम, आवश्यक जांच और डॉक्टर द्वारा सुझाए गए उपचार को प्राथमिकता देनी चाहिए।

हमेशा याद रखें : कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण का मतलब सिर्फ तेल कम करना नहीं है - सही खान-पान, नियमित व्यायाम, वजन पर नियंत्रण और समय पर उचित चिकित्सा उपचार अपनाना ही स्वस्थ हृदय की असली कुंजी है !

आज ही संकल्प लें — स्वस्थ आहार अपनाएं, नियमित व्यायाम करें और अपने दिल का विशेष ख्याल रखें !

**स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपने हृदय का ख्याल रखें!**




# नेता बूढ़े नहीं होते ! राजनीतिः लंबी उम्र का नुस्खा, बुढ़ापे की रामबाण दवा !

रिटायर हो गए ? घर मत बैठिए – राजनीति में कूद पड़िए। नारे लगाइए, भीड़ जुटाइए, भाषण दीजिए और लंबी उम्र का लुत्फ उठाइए। न जिम का खर्च, न महंगे सप्लीमेंट !

भूपेंद्र सारस्वत 'सारथी'



लंबी उम्र का राज क्या है ? योग, प्राणायाम, सुबह की सैर, हरी सब्जियां या महंगे हेल्थ सप्लीमेंट ? अरे भाई, एक नुस्खा और है, जिस पर अभी तक डॉक्टरों का ध्यान नहीं गया। वह हैः राजनीति !

जी हां, राजनीति ! इसे बुढ़ापे का सबसे सस्ता, दिलचस्प और असरदार टॉनिक कहा जा सकता है। इसमें मनोरंजन है, रोमांच है, सामाजिक मेलजोल है, भाषण देने का मौका है और अपनी अहमियत जताने के अनगिनत अवसर हैं। सबसे बड़ी बात; यहां रिटायरमेंट की कोई उम्र नहीं होती।

जरा दुनिया के बुजुर्ग नेताओं पर नजर डालिए। मलेशिया के महाथिर मोहम्मद 92 साल की उम्र में फिर प्रधानमंत्री बन गए और आज भी सौ से ऊपर की उम्र में सक्रिय हैं। कैमरून के पॉल बिया नब्बे के पार भी राष्ट्रपति बने हुए हैं। जिम्बाब्वे के रॉबर्ट मुगाबे 93 साल तक सत्ता में रहे और 95 तक जिए। क्यूबा के फिडेल कास्त्रो नब्बे के दशक में भी प्रभावशाली बने रहे। अमेरिका के स्ट्रॉम थर्मंड सौ साल की उम्र तक सीनेटर रहे।

भारत के मोरारजी देसाई 81 साल में प्रधानमंत्री बने और 99 साल तक जिए। केरल के वी.एस. अच्युतानंदन 82 साल की उम्र में मुख्यमंत्री बने और 101 साल तक सक्रिय रहे। इटली के जूलियो आंद्रेओत्ती 94 साल तक राजनीति में दबदबा बनाए रहे। नेल्सन मंडेला 95 और जिमी कार्टर 100 साल तक जिए। राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद भी कार्टर सामाजिक और राजनीतिक कामों में जुटे रहे।

भारत में अटल बिहारी वाजपेयी 93, मनमोहन सिंह 92 और एम. करुणानिधि 94 साल तक जिए। एच.डी. देवगौड़ा, फारूक अब्दुल्ला, नरसिम्हा राव, लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और पंजाब के प्रकाश सिंह बादल जैसे नेताओं ने भी साबित किया कि उम्र बढ़ने का मतलब मैदान छोड़ना नहीं है। अमेरिका के चक ग्रासली, बर्नी सैंडर्स और नैन्सी पेलोसी भी इस उम्र में राजनीति की धुरी बने रहे।

इन उदाहरणों से एक दिलचस्प सवाल जरूर उठता हैः क्या सक्रिय राजनीतिक जीवन इंसान को चुस्त-दुरुस्त और उत्साही बनाए रखने में मदद करता है ?

जरा सोचिए, राजनीति में कदम रखते ही जिंदगी कितनी बदल जाती है। सुबह बैठक, दोपहर में प्रतिनिधिमंडल, शाम को धरना और रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस। कभी जन्मदिन, कभी शोकसभा, कभी चुनावी जलसा। दिन कब गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता।

रिटायरमेंट के बाद आम आदमी सुबह अखबार पढ़ता है, फिर टीवी देखता है और पड़ोसियों से बीमारी की चर्चा करता है। राजनीति में शामिल व्यक्ति के पास इससे बेहतर काम हैं। उसे लोगों की समस्याएं सुननी हैं, अधिकारियों को ज्ञापन देना है और सरकार से जवाब मांगना है।

किसी को सड़क बनवानी है, किसी को नाली साफ करवानी है। किसी को बिजली चाहिए, किसी को पार्क में बेंच। आप अचानक समाज के लिए बेहद जरूरी आदमी बन जाते हैं।

और फिर आती हैं रैलियां ! सैकड़ों लोग झंडे लहरा रहे हैं। नारे लग रहे हैं। माइक गरज रहा है। आपका नाम पुकारा जा रहा है। इससे बढ़कर मनोबल बढ़ाने वाला नजारा क्या होगा ?

नारे लगाने से फेफड़ों को कसरत मिलती है। जुलूस में चलने से पैरों की एक्सरसाइज होती है। भाषण देने से आवाज खुलती है। लोगों से मिलने-जुलने से सामाजिक रिश्ते मजबूत होते हैं। राजनीतिक उठापटक दिमाग को व्यस्त रखती है।

सरकारी नौकरी से रिटायर हुए ? बैंक से विदा हो गए ? कॉलेज की नौकरी खत्म हो गई ? व्यापार से फुर्सत मिल गई ? अब घर बैठकर बोर होने की क्या जरूरत है ?

संसद का चुनाव लड़ना जरूरी नहीं। राजनीति तो हर जगह मौजूद है। घर से ही शुरू कीजिए !

अपनी हाउसिंग सोसायटी की कमेटी में शामिल हो जाइए। पार्किंग, सुरक्षा, सफाई और पानी के मुद्दे उठाइए। किसी क्लब की कार्यकारिणी में घुसिए। खेल संघ में पद हासिल कीजिए। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या किसी सामाजिक संस्था की व्यवस्था में हाथ बंटाइए।

कॉलेज और विश्वविद्यालयों में छात्र राजनीति है। व्यापार मंडलों में अपनी अलग सियासत है। धार्मिक संस्थाओं में भी चुनाव, गुटबाजी और नेतृत्व की भरपूर गुंजाइश है।

जहां चार लोग मिलते हैं, वहां राजनीति शुरू हो जाती है। जहां पद है, वहां प्रतिष्ठा है। जहां प्रतिष्ठा है, वहां मुकाबला है।

थोड़ा मुकाबला कीजिए। अपनी पहचान बनाइए। समर्थक जुटाइए। अपनी बात मजबूती से रखिए। और हां, थोड़ा रौब भी जमाइए। आजकल की भाषा में इसे 'मॉगिंग' कहते हैं; यानी अपनी मौजूदगी और व्यक्तित्व से दूसरों पर प्रभाव जमाना।

सबसे सस्ता शौक, सबसे बड़ा शगल !

राजनीति का एक और फायदा है। इसमें शुरुआत करने के लिए महंगे जिम, विदेशी प्रोटीन पाउडर या आलीशान क्लब की जरूरत नहीं।

एक माइक, कुछ समर्थक और कोई सार्वजनिक मुद्दा काफी है। भाषण देने के लिए आत्मविश्वास चाहिए। बड़े-बड़े वादे करने के लिए तो बस जुबान चाहिए !

आप कह सकते हैं कि छह महीने में मोहल्ले की तस्वीर बदल देंगे। सड़कें चमका देंगे। पार्क को लंदन बना देंगे। नाली को साबरमती मॉडल दे देंगे। खर्च कुछ नहीं, तालियां मुफ्त !

आखिरकार, असली राजनीति समाजसेवा है, केवल पद और प्रतिष्ठा की दौड़ नहीं।

तो बुजुर्गों, तैयार हो जाइए ! सुबह की सैर के साथ थोड़ी राजनीतिक सैर भी शुरू कीजिए। घर की चारदीवारी से बाहर निकलें। लोगों से मिलें, बहस करें, हंसें और सक्रिय रहें।

याद रखिए, जिंदगी की पारी में रिटायरमेंट कोई फुल स्टॉप नहीं है।

और अगर कोई पूछे कि लंबी उम्र का राज क्या है, तो मुस्कराकर जवाब दीजिएः

"भाई साहब, हमने राजनीति ज्वाइन कर ली है। अभी तो हमारी दूसरी पारी शुरू हुई है। कुर्सी मिले न मिले, मैदान छोड़ने वाले नहीं ! !"

# इटली के प्रतिष्ठित अस्पताल से डॉ. रवि रंजन ने पूरी की शोल्डर एवं एल्बो सर्जरी की अंतरराष्ट्रीय फेलोशिप। नालंदा और बिहार का नाम किया रोशन

परिवहन विशेष न्यूज

**नई दिल्ली, 11 नबम्बर,,** चिकित्सा के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रहे बिहार के युवा अस्थि रोग विशेषज्ञ ( ऑर्थोपेडिक सर्जन ) डॉ. रवि रंजन ने एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने इटली के प्रतिष्ठित डी. सर्वेसी हॉस्पिटल ( D. Cervesi Hospital ), कैटोलिका में शोल्डर एवं एल्बो सर्जरी ( Shoulder and Elbow Surgery ) की लगभग छह सप्ताह की विशेष क्लिनिकल फेलोशिप सफलतापूर्वक पूरी की है। यह प्रशिक्षण 12 सितंबर से 23 अक्टूबर 2026 तक आयोजित हुआ।

यह फेलोशिप अस्पताल की प्रतिष्ठित यूनिट ऑफ शोल्डर एंड एल्बो सर्जरी में संपन्न हुई, जिसके प्रमुख एवं डॉ. रवि रंजन के सुपरवाइजर विश्वप्रसिद्ध विशेषज्ञ डॉ. पाओलो पलादिनी ( Dr. Paolo Paladini ) हैं। डी. सर्वेसी हॉस्पिटल शोल्डर एवं एल्बो सर्जरी के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित केंद्र है तथा SECEC, EFORT और ISK-SAA जैसी अंतरराष्ट्रीय चिकित्सा संस्थाओं से संबद्ध एक होस्ट सेंटर है।

फेलोशिप के दौरान डॉ. रवि रंजन ने कंधे और कोहनी की आधुनिक एवं जटिल सर्जरी की विभिन्न तकनीकों का व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त किया। उन्होंने वरिष्ठ विशेषज्ञों के साथ ऑपरेशन थिएटर में सक्रिय रूप से भाग लेते हुए एडवांस्ड आर्थ्रोस्कोपी एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी का अनुभव हासिल किया। इसके साथ ही उन्होंने मरीजों की क्लिनिकल जांच, उपचार की योजना बनाने और शोध गतिविधियों में भी हिस्सा लिया।

इस प्रशिक्षण में रिवर्स शोल्डर रिप्लेसमेंट ( Reverse Shoulder Arthroplasty ), एनाटॉमिकल शोल्डर रिप्लेसमेंट, आर्थ्रोस्कोपिक रोटेटर कफ रिपेयर, कंधे के बार-बार खिसकने ( Shoulder Instability ) की सर्जरी, एसी जॉइंट ( AC Joint ) की सर्जरी, गंभीर रोटेटर कफ टियर में पैच रिपेयर एवं टेंडन ट्रांसफर जैसी आधुनिक तकनीकें शामिल रहीं।

इसके अलावा कोहनी का प्रत्यारोपण ( Elbow Arthroplasty ), एल्बो आर्थ्रोस्कोपी, टेनिस एल्बो की सर्जरी तथा अल्नर नर्व ( Ulnar Nerve ) से संबंधित जटिल सर्जिकल प्रक्रियाओं का भी विशेष अनुभव प्राप्त किया। डॉ रबि रंजन ने एम बी बी एस आनर्स गोल्ड मेडलिस्ट पटना ,एम एस,सर्जन आर्थो,, नई दिल्ली, ,सीनियर रेजिडेंस ,नई दिल्ली ,के अलाबे डी एन बी एम आर सी एस यू के, डी आई पी एस आई सी टी ओ बेल्जियम एफ एस सी अमेरिकन कालेज ऑफ सर्जन इटली से फेलोशिप जैसी कई रास्ट्रीय अंतरास्ट्रीय डिग्री हासिल की है ।बे नालन्दा जिले के तेल्हाड़ा थाने के सुल्तानपुर गाब के रहने बाले है। बर्तमान ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया केंद्रीय मेडिकल कालेज नई दिल्ली में बरिष्ठ सर्जन है। डॉक्टर रबि ने बताया उनका लक्ष्य गरीब जरूरत मन्द मरीजो की सेबा करना है। उनका यह उपलब्धी चिकित्सा क्षेत्र में उत्कृष्ठता को दर्शाता है,बलीक युबाओ के लिए प्रेरणा स्रोत है।

भारत में शोल्डर एवं एल्बो सर्जरी के क्षेत्र में विशेष रूप से प्रशिक्षित विशेषज्ञों की संख्या अभी सीमित है। ऐसे में इस अंतरराष्ट्रीय क्लिनिकल फेलोशिप को पूरा करना डॉ. रवि रंजन के चिकित्सा करियर की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस प्रशिक्षण से उन्हें कंधे और कोहनी की जटिल बीमारियों, खेल संबंधी चोटों तथा जोड़ संबंधी समस्याओं के आधुनिक उपचार में अपनी विशेषज्ञता को और विकसित करने का अवसर मिला है।

फेलोशिप पूर्ण होने पर अस्पताल की ओर से जारी प्रमाणपत्र में डॉ. रवि रंजन के कार्य के प्रति समर्पण, विषय की अच्छी जानकारी और क्लिनिकल गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी की सराहना की गई है। प्रमाणपत्र पर यूनिट प्रमुख डॉ. पाओलो पलादिनी के हस्ताक्षर हैं।

डॉ. रवि रंजन ने कहा कि चिकित्सा विज्ञान में सीखने और स्वयं को बेहतर बनाने की प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं होती। उनका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सीखी गई आधुनिक सर्जिकल तकनीकों और ज्ञान का उपयोग भारत में मरीजों के बेहतर उपचार के लिए करना है। उन्होंने संकल्प लिया कि वे भविष्य में भी ऑर्थोपेडिक्स के क्षेत्र में निरंतर सीखते और विकसित होते रहेंगे, ताकि मरीजों को विश्वस्तरीय उपचार सुविधाएं अपने देश में ही उपलब्ध करा सकें। फ़ोटो,,,,

गौरतलब है कि डॉ. रवि रंजन की इस उपलब्धि से उनके माता-पिता, परिवार, गृह जिला huनालंदा और पूरे बिहार में खुशी का माहौल है। उनकी यह सफलता कठिन परिश्रम, लगन और चिकित्सा के प्रति समर्पण का परिणाम है। उन्होंने अपनी इस अंतरराष्ट्रीय उपलब्धि से न केवल अपने माता-पिता, बल्कि नालंदा और बिहार को भी गौरवान्वित किया है.।।

झारखंड के धनबाद में लगेंगे नि शुल्क कैम्प मरीज होंगे लाभान्वित ,,,,,झारखंड मानब कल्याण सोसाइटी धनबाद के अध्यक्ष रामाशीष प्रसाद चौहान के बिशेष आग्रह पर दिसंबर माह मे डाक्टर राम मनोहर लोहिया केंद्रीय मेडिकल कालेज अस्पताल के बरिष्ठ आर्थो सर्जन डॉक्टर रबि रंजन जो की राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय डिग्रिया हासिल की है ।धनबाद में नि शुल्क शिबिर का आयेजन करेगे,जिसमे सैकड़ो मरीज लाभान्वित होंगे ।ये कार्यक्रम झारखंड मानब कल्याण सोसाइटी के अध्यक्ष रामशीष चौहान के नेतृत्व में स्वाथ्य कैम्प आयोजित किया जाएगा।

# परिवहन विशेष समाचार पत्र दैनिक - दुबई में दीवाली पर भारतीय परंपरा का स्वर्णिम सम्मान

दुबई में दीवाली पर सोने की रंगोली – भारतीय परंपरा का स्वर्णिम सम्मान
सिटी सेंटर देरा में दमास ने बनाई दुबई की पहली सोने की रंगोली, 213 गहनों से सजा 2x2 मीटर का मास्टरपीस
रिपोर्ट विशेष संवाददाता परिवहन विशेष समाचार पत्र दुबई।

दुबई ने इस बार दीवाली कुछ अलग अंदाज में मनाई। सिटी सेंटर देरा में दमास ज्वैलरी ने दुबई की पहली ऐसी रंगोली पेश की, जो पूरी तरह सोने और हीरे के गहनों से बनाई गई।

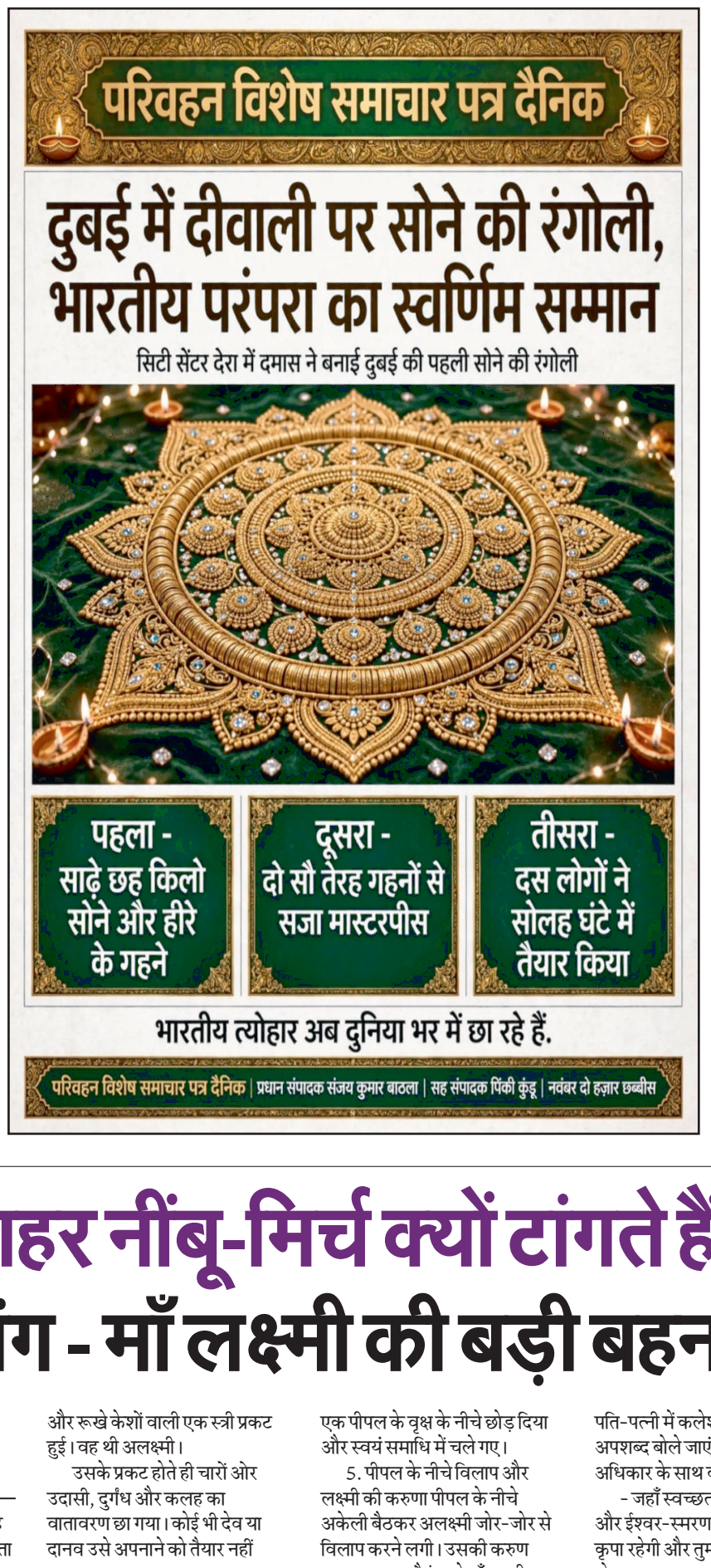
**क्या है खास ?**

- 6.5 किलो दमास के सोने और हीरे के गहनों से बनी
- 213 गहने - हार, चूड़ियां, झुमके, अंगूठियां
- 2x2 मीटर की भव्य रंगोली
- 10 लोग, 16 घंटे की मेहनत से तैयार
- हरे रंग की पृष्ठभूमि पर सोने की पारंपरिक रंगोली डिजाइन

अनावरण के समय मॉल में भारी भीड़ उमड़ी। लोग इस स्वर्णिम रंगोली को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। यह सिर्फ गहनों का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि भारतीय परंपरा, दीवाली की भावना और कारीगरी का संगम था।

**संपादकीय टिप्पणी:** जहां एक ओर रंगोली मिट्टी, फूल और रंगों से बनती है, वहीं दुबई में यह सोने से बनी - ये दिखाता है कि भारतीय त्योहार अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं, दुनिया भर में अपनी छाप छोड़ रहे हैं।

**स्थान:** सिटी सेंटर देरा, दुबई







## धन और रिश्तों का दैनिक अंक ज्योतिष भविष्यफल

*जानिए दिन की ऊर्जा • संभालिए धन • मज़बूत बनाइए रिश्ते*

**12 नवंबर 2026 | दिन का अंक: 6 — सामंजस्य, जिम्मेदारी, देखभाल और आर्थिक संतुलन**

### मूलांक 1

**धन व करियर:** दिन 6 जिम्मेदार नेतृत्व को महत्व देता है। टीम के बजट या क्लाइंट से किए वादे की समीक्षा करें और तुरंत लाभ के बजाय टिकाऊ प्रगति चुनें।
**रिश्ते:** प्यार भरोसेमंद काम से दिखाएं; पूछें कि सामने वाले को वास्तव में किस सहयोग की जरूरत है।
**सावधानी:** नेतृत्व को नियंत्रण न बनाएं और प्रभाव जमाने के लिए खर्च न करें।
**दिन बेहतर बनाएं:** एक साझा जिम्मेदारी न्यायपूर्ण तरीके से सुलझाएं।

### मूलांक 2

**धन व करियर:** आपकी सहयोगी प्रकृति दिन 6 से मेल खाती है। साझा खर्च देखें और धन से जुड़ी मौखिक सहमति को स्पष्ट शब्दों में तय करें।
**रिश्ते:** जरूरतों को अनुमान के बजाय नरमी से व्यक्त करने पर निकटता बढ़ सकती है।
**सावधानी:** अपराधबोध में उधार देने या विवाद टालने के लिए हर बात मानने से बचें।
**दिन बेहतर बनाएं:** एक सीमा विनम्रता से लेकिन दृढ़ता के साथ तय करें।

### मूलांक 3

**धन व करियर:** दिन 6 ऐसी रचनात्मकता को बढ़ावा देता है जो लोगों के काम आए। प्रस्ताव, प्रस्तुति या ग्राहक अनुभव बेहतर करें, लेकिन खर्च न बढ़ाएं।
**रिश्ते:** महंगे उपहार से अधिक सच्ची प्रशंसा असर करेगी।
**सावधानी:** महंगी योजनाओं का वादा करने और बहुत जगह ध्यान बांटने से बचें।
**दिन बेहतर बनाएं:** एक रचनात्मक पहल से किसी को खास महसूस कराएं।

### मूलांक 4

**धन व करियर:** आपकी व्यावहारिक क्षमता दिन 6 की सुरक्षा वाली ऊर्जा को घर या व्यवसाय के बेहतर खर्च प्रबंधन में बदल सकती है।
**रिश्ते:** विश्वसनीयता जरूरी है, लेकिन काम और समय-सारणी के अलावा स्नेह भी दिखाएं।
**सावधानी:** आलोचना, पूर्णता की जिद और हर जिम्मेदारी अकेले उठाने से बचें।
**दिन बेहतर बनाएं:** एक नियमित खर्च घटाएं और किसी की सराहना करें।

### मूलांक 5

**धन व करियर:** दिन 6 नए अवसर और पुराने दायित्वों में संतुलन चाहता है। नया प्रस्ताव स्वीकार करने से पहले समय और नकदी प्रवाह पर असर जांचें।
**रिश्ते:** नई रोमांचक योजना से पहले किया हुआ वादा निभाएं; निरंतरता भरोसा बढ़ाती है।
**सावधानी:** अचानक खरीदारी और बिना चर्चा प्रतिबद्धता बदलने से बचें।
**दिन बेहतर बनाएं:** एक जिम्मेदारी पूरी करके छोटा-सा सुखद बदलाव करें।

### मूलांक 6

**धन व करियर:** आपके मूलांक 6 और दिन 6 की ऊर्जा साथ है। सेवा, आराम और धन के जिम्मेदार उपयोग पर ध्यान रहेगा। क्लाइंट व परिवार के फैसलों में विलासिता के बजाय मूल्य चुनें।
**रिश्ते:** स्नेह मजबूत रहेगा; हर बात खुद संभालने के बजाय अपनों को भी योगदान करने दें।
**सावधानी:** अधिकार भावना, जरूरत से ज्यादा देना और आराम के लिए खरीदारी से सावधान रहें।
**दिन बेहतर बनाएं:** ऐसी देखभाल करें जो बजट और स्वतंत्रता दोनों का सम्मान करे।

### मूलांक 7

**धन व करियर:** दिन 6 आपकी गहरी सोच को व्यावहारिक देखभाल से जोड़ता है। बढ़ने से पहले किसी दीर्घकालिक खर्च या पेशेवर दायित्व की समीक्षा करें।
**रिश्ते:** शांति की जरूरत बताएं, लेकिन सच्ची बातचीत के लिए समय भी निकालें।
**सावधानी:** चुप्पी में दूर होने या भावनाओं को केवल विश्लेषण करने से बचें।
**दिन बेहतर बनाएं:** एक सोच-समझी योजना के साथ एक आत्मीय बातचीत करें।

### मूलांक 8

**धन व करियर:** दिन 6 आपकी महत्वाकांक्षा में लाभ के साथ लोगों का ध्यान रखने को कहता है। व्यवसाय या प्रॉपर्टी के निर्णय का परिवार और सहयोगियों पर असर देखें।
**रिश्ते:** आदेश देने के बजाय सहयोग करें; साझा जिम्मेदारी नियंत्रण से बेहतर है।
**सावधानी:** प्रतिष्ठा के लिए खर्च और काम का तनाव रिश्तों में लाने से बचें।
**दिन बेहतर बनाएं:** एक सुरक्षित आर्थिक फैसला लें और अपने व्यक्ति के लिए समय रखें।

### मूलांक 9

**धन व करियर:** दिन 6 आपकी उदारता को जिम्मेदार दिशा देता है। परिवार या समाज की जरूरत में मदद करें, लेकिन यथार्थवादी सीमा के भीतर।
**रिश्ते:** करुणा तनाव कम कर सकती है, पर क्षमा का अर्थ जरूरी सीमाएं हटाना नहीं है।
**सावधानी:** दूसरों को बचाने के लिए खर्च और उनकी हर जिम्मेदारी उठाने से बचें।
**दिन बेहतर बनाएं:** अपनी स्थिरता बनाए रखते हुए व्यावहारिक मदद करें।

कॉल / व्हाट्सऐप: 8750075550 | वेबसाइट: www.vediccodes.in | @vediccodes
*Vediccodes - Your vibrations... our solutions*

# घर के बाहर नींबू-मिर्च क्यों टांगते हैं? पद्म पुराण का वह गुप्त प्रसंग - माँ लक्ष्मी की बड़ी बहन अलक्ष्मी की कथा

**समुद्र मंथन से प्रकट हुई अलक्ष्मी, द्वार पर तीखा - खट्टा भोजन पाकर ही लौट जाती हैं**
**स्वच्छता, प्रेम और संध्या - दीप वाले घर में उनका प्रवेश वर्जित**

मूल कथा : डॉ. चंद्रशेखर शर्मा। प्रस्तुति : संजय कुमार बाठला

> **संपादकीय स्पष्टीकरण:** यह लेख पौराणिक कथा / धार्मिक मान्यता के रूप में प्रस्तुत है। इसे इतिहास का तथ्यात्मक दावा नहीं, बल्कि लोक-आस्था और पुराण-परंपरा की कथा के रूप में पढ़ें।

**मुख्य तथ्य - एक नज़र में**

**- प्रश्न:** घर और दुकान के बाहर नींबू-मिर्च क्यों टांगते हैं ?
- उत्तर - पुराण के अनुसारः अलक्ष्मी को द्वार पर ही उनका प्रिय तीखा-खट्टा भोजन मिल जाए, तो वे भीतर प्रवेश नहीं करतीं
- अलक्ष्मी कौनः माँ लक्ष्मी की ज्येष्ठ ( बड़ी ) बहन, जिन्हें 'ज्येष्ठा' या 'दरिद्रता' भी कहा जाता है
- प्रकट्यः समुद्र मंथन से माँ लक्ष्मी के निकलने से ठीक पहले
- विवाहः महर्षि उद्दालक ( दुःसह मुनि ) से
- वासः पीपल वृक्ष के नीचे, शनिवार को लक्ष्मी-विष्णु का भी वास
- भोजनः तीखा और खट्टा / कड़वा रस
- रहने का स्थानः जहाँ आलस्य, जुआ, मदिरा, कलह, गंदे बर्तन, अपशब्द हों

1. अधिकांश लोग जानते हैं आधी कथा अधिकांश लोग केवल माँ लक्ष्मी के प्राकट्य की कथा जानते हैं, परंतु बहुत कम लोगों को ज्ञात है कि समुद्र मंथन से माँ लक्ष्मी के निकलने से ठीक पहले उनकी ज्येष्ठ ( बड़ी ) बहन 'अलक्ष्मी' प्रकट हुई थीं।

यही वह कथा है जो नींबू-मिर्च के रहस्य को खोलती है।

2. समुद्र मंथन - पहले प्रकट हुईं अलक्ष्मी जब देवों और असुरों ने अमृत पाने के लिए क्षीरसागर का मंथन किया, तो हलाहल विष के पश्चात समुद्र के भीतर से काले वर्ण, लाल नेत्रों और रूखे केशों वाली एक स्त्री प्रकट हुई। वह थी अलक्ष्मी।

उसके प्रकट होते ही चारों ओर उदासी, दुर्गंध और कलह का वातावरण छा गया। कोई भी देव या दानव उसे अपनाने को तैयार नहीं हुआ।

इसके ठीक बाद, उसी सागर से स्वर्णिम कांति वाली, कमल पर आसीन माँ महालक्ष्मी प्रकट हुईं, जिन्होंने भगवान विष्णु के गले में वरमाला डाली।

एक ही सागर से दो बहनें निकलीं - एक समृद्धि की देवी, दूसरी दरिद्रता की प्रतीक।

3. बड़ी बहन का प्रश्न - मेरा क्या होगा ? जब माँ लक्ष्मी का विवाह भगवान विष्णु से हो गया, तो बड़ी बहन अलक्ष्मी रोने लगीः

> हे नारायण ! मेरी छोटी बहन का विवाह तो आपसे हो गया, परंतु मेरा क्या ? मैं बड़ी हूँ, मेरे बिना विवाह के संसार का संतुलन कैसे रहेगा ? मेरा स्वामी कौन बनेगा ?

भगवान विष्णु ने जगत के कल्याण के लिए एक कठोर तपस्वी ऋषि महर्षि उद्दालक ( दुःसह मुनि ) को समझाया और उनका विवाह अलक्ष्मी से करवा दिया।

4. आश्रम में अलक्ष्मी नहीं रह सकीं विवाह के बाद महर्षि उद्दालक अलक्ष्मी को लेकर अपने पावन आश्रम पहुँचे। परंतु आश्रम के द्वार पर कदम रखते ही अलक्ष्मी चीखने लगीः

- जहाँ वेदों की ऋचाएं गूँजती हैं, मैं वहाँ नहीं रह सकती !
- जहाँ हवन का धुआँ और शंख की ध्वनि होती है, वहाँ मेरे कान फटने लगते हैं !
- जहाँ अतिथि-सत्कार और स्वच्छता होती है, वहाँ मेरा दम घुटता है !

महर्षि उद्दालक समझ गए कि यह स्त्री धर्म और शांति के सर्वथा विपरीत है। तंग आकर महर्षि ने अलक्ष्मी को एक पीपल के वृक्ष के नीचे छोड़ दिया और स्वयं समाधि में चले गए।

5. पीपल के नीचे विलाप और लक्ष्मी की करुणा पीपल के नीचे अकेली बैठकर अलक्ष्मी जोर-जोर से विलाप करने लगी। उसकी करुण पुकार सुनकर वैकुंठ से माँ लक्ष्मी अपने स्वामी श्रीहरि के साथ वहाँ पहुँचीं।

अलक्ष्मी ने रोते हुए कहाः

> हे बहन ! न मेरे पास रहने का कोई घर है, न कोई मुझे आदर देता है, और न मेरे भोजन की कोई व्यवस्था है। मैं इस संसार में कैसे जिऊँ ?

माँ लक्ष्मी ने अपनी बड़ी बहन के प्रति करुणा दिखाते हुए उसे तीन वरदान दिए, जो आज भी हमारे दैनिक जीवन के नियम हैं:

6. तीन वरदान - जो आज भी हमारे जीवन के नियम हैं

1. पीपल पर वासः भगवान विष्णु ने कहा - ₹हे अलक्ष्मी ! प्रत्येक शनिवार को मैं और लक्ष्मी स्वयं तुम्हारे इस पीपल के वृक्ष पर वास करेंगे। इसलिए शनिवार को पीपल की पूजा करने वाले को धन-धान्य मिलेगा, परंतु अन्य दिनों में तुम्हारा ही प्रभाव रहेगा।₹

यही कारण है कि शनिवार को पीपल की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है।

2. अलक्ष्मी का भोजन - तीखा और खट्टाः माँ लक्ष्मी ने कहा - ₹मेरा प्रिय भोजन मिष्ठान्न ( खीर, बताशे, फल ) है। तुम्हारा प्रिय भोजन 'तीखा और खट्टा' ( कड़वा रस ) होगा।₹

यही कारण है कि लोग अपने घर और व्यापार के मुख्य द्वार पर नींबू और हरी मिर्च टांगते हैं। अलक्ष्मी द्वार पर आकर अपना प्रिय तीखा-खट्टा भोजन ग्रहण करके तृप्त हो जाती हैं और वहीं से बाहर लौट जाती हैं, घर के भीतर प्रवेश नहीं करतीं।

3. अलक्ष्मी के रहने का स्थानः माँ लक्ष्मी ने स्पष्ट आदेश दिया -

- जहाँ आलस्य, जुआ, मदिरा, पति-पत्नी में कलेश, गंदे बर्तन, और अपशब्द बोले जाएंगे, वहाँ तुम पूरे अधिकार के साथ वास करना।
- जहाँ स्वच्छता, प्रेम, संध्या-दीप और ईश्वर-स्मरण होगा, वहाँ मेरी कृपा रहेगी और तुम्हारा प्रवेश वर्जित होगा।

7. नींबू-मिर्च का असली संदेश - सिर्फ टोटका नहीं यह कथा सिर्फ नींबू-मिर्च टांगने की बात नहीं बताती, यह जीवन का नियम बताती हैः

1. द्वार पर ही रोक दोः बुरी आदतों को घर के बाहर ही रोकना है, अंदर आने नहीं देना है।
2. स्वच्छता ही लक्ष्मी हैः गंदे बर्तन, गंदा घर, गंदी भाषा - यही अलक्ष्मी का निमंत्रण है।
3. कलह ही दरिद्रता हैः जहाँ पति-पत्नी में कलह है, वहाँ धन टिकता नहीं।
4. आलस्य ही दरिद्रता हैः आलसी व्यक्ति के पास लक्ष्मी नहीं ठहरती।
5. संध्या-दीप ही सुरक्षा हैः शाम को दीपक, ईश्वर-स्मरण, प्रेम और अतिथि-सत्कार - यही लक्ष्मी का वास है।

नींबू-मिर्च टांगना प्रतीक है। असली नींबू-मिर्च तो आपकी स्वच्छता, आपका प्रेम और आपकी दिनचर्या है।

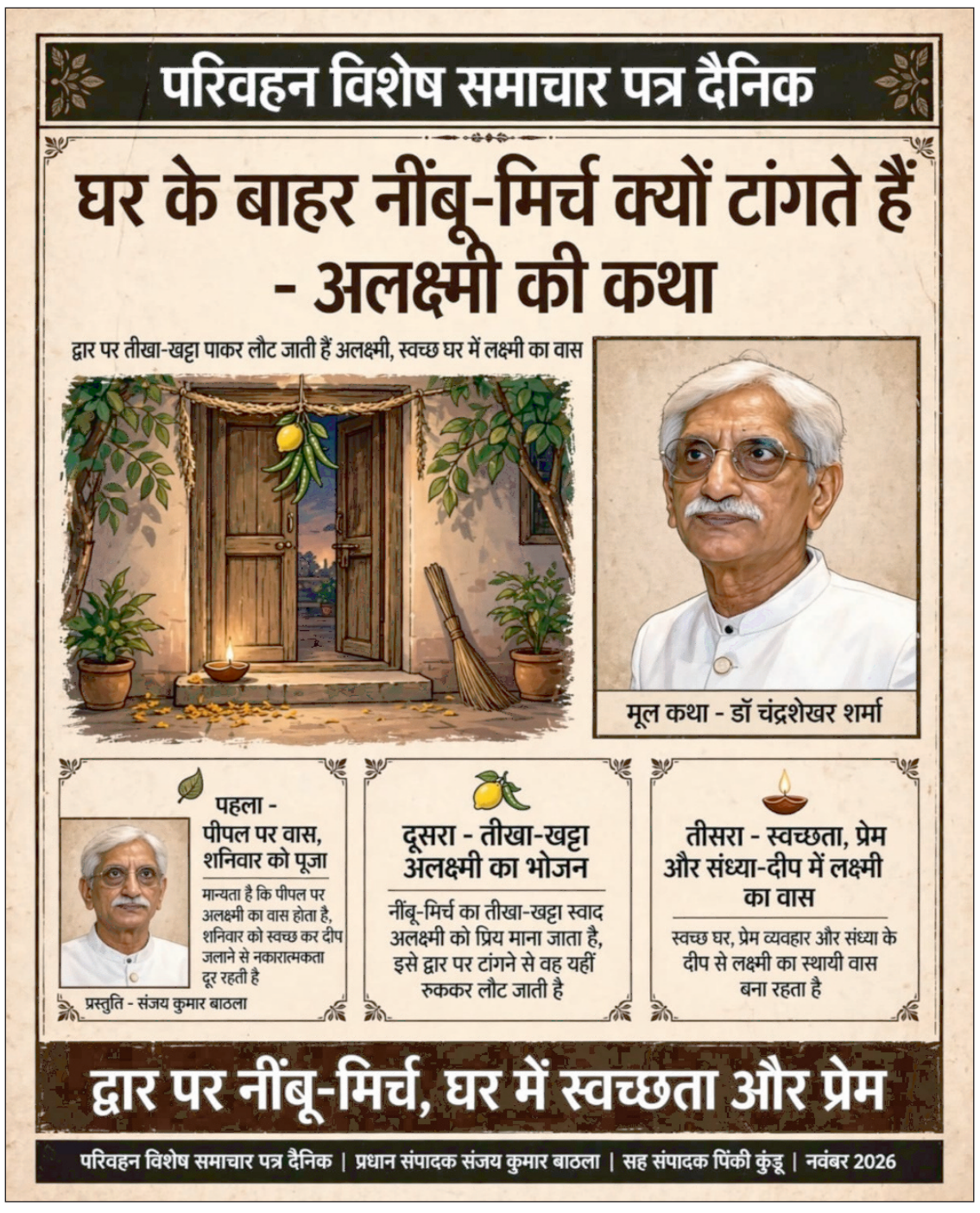
**8. संपादकीय निष्कर्ष** लक्ष्मी और अलक्ष्मी दो बहनें हैं - एक ही घर में, एक ही मन में, दोनों रहना चाहती हैं।

आप किसे बुलाएंगे, यह आपके व्यवहार पर निर्भर करता है। अगर आप द्वार पर नींबू-मिर्च टांगकर सोचते हैं कि काम हो गया, तो यह अधूरा है।

द्वार पर नींबू-मिर्च के साथ-साथ घर के अंदर स्वच्छता, प्रेम, मधुर वाणी और संध्या-दीप भी होना चाहिए।

तभी लक्ष्मी भीतर आएंगी और अलक्ष्मी द्वार से ही लौट जाएंगी।

**- संजय कुमार बाठला, प्रधान संपादक**



# बिना सेफ्टी किट के कोई भी सफाई कर्मचारी सीवर लाइन में न उतरे : डीसी

## डीसी वर्षा खांगवाल ने कहा-सीवरेज व सेफ्टी टैंक की सफाई के दौरान सुरक्षा मानकों की पालना अनिवार्य

परिवहन विशेष न्यूज

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा-निर्देश

डीसी ने संबंधित विभागों को प्रभावी क्रियान्वयन के दिए निर्देश

**झज्जर, 11 नवंबर**

सीवरेज और सेफ्टी टैंक की सफाई के दौरान सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। किसी भी सफाई कर्मचारी को बिना पर्याप्त सुरक्षा उपकरणों और सेफ्टी किट के सीवर लाइन या सेफ्टी टैंक में प्रवेश न करने दिया जाए। सफाई कार्य के दौरान निर्धारित सुरक्षा मानकों की सख्ती से पालना सुनिश्चित की जाए, ताकि किसी भी कर्मचारी के साथ कोई अप्रिय घटना न हो। यह निर्देश डीसी वर्षा खांगवाल ने संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में दिए। बैठक से पहले राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों को सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण से जुड़े आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुरूप डीसी वर्षा खांगवाल ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने और सुरक्षा प्रबंधों को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए।

डीसी ने कहा कि सीवरेज और सेफ्टी टैंक की सफाई अत्यंत संवेदनशील कार्य है। इसमें थोड़ी सी लापरवाही भी सफाई कर्मचारियों के लिए गंभीर जोखिम पैदा कर सकती है। इसलिए संबंधित विभाग यह सुनिश्चित करें कि सफाई कार्य में लगे प्रत्येक कर्मचारी को आवश्यक सुरक्षा उपकरण उपलब्ध करवाए जाएं। बिना सेफ्टी किट, आवश्यक सुरक्षा प्रबंध और निर्धारित प्रक्रिया के किसी भी कर्मचारी को सीवर लाइन में न उतारा जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सफाई कार्य की निगरानी भी प्रभावी ढंग से की जाए और सुरक्षा व्यवस्था में किसी प्रकार की कमी न रहने दी जाए।




**सफाई कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने के निर्देश**

डीसी ने कहा कि सफाई कर्मचारियों का स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रशासन की जिम्मेदारी है। इसी उद्देश्य से प्रशासन की ओर से निरंतर स्वास्थ्य जांच शिविर भी आयोजित किए जा रहे हैं, ताकि सफाई कर्मचारियों के स्वास्थ्य की नियमित जांच हो सके और जरूरत पड़ने पर उन्हें समय पर उचित चिकित्सा सहायता उपलब्ध करवाई जा सके। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्वास्थ्य जांच शिविरों का आयोजन निरंतर जारी रखा जाए और प्रत्येक पात्र सफाई कर्मचारी तक इनका लाभ पहुंचाया जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी सफाई कर्मचारी को कार्य के दौरान परेशानी आने या किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता होने पर संबंधित विभाग तुरंत संज्ञान लें।

डीसी ने कहा कि जरूरतमंद सफाई कर्मचारियों की हर संभव मदद की जाए और उनकी समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाए। साथ ही राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के दिशा-निर्देशों की पालना भी सम्बंधित विभाग सुनिश्चित करें। डीसी ने स्पष्ट किया कि सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा के मामले में किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें और यह सुनिश्चित करें कि सीवरेज व सेफ्टी टैंक की सफाई के दौरान निर्धारित सुरक्षा प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन हो। प्रशासन का उद्देश्य सफाई कर्मचारियों को सुरक्षित कार्य वातावरण उपलब्ध करवाना, उनके स्वास्थ्य की देखभाल करना तथा उनके हितों की रक्षा सुनिश्चित करना है।

इस अवसर पर एडीसी जगनिवास, एसडीएम बहादुरगढ़ अभिनव सिवाच, एसीपी रमेश गुलिया, जिला कल्याण अधिकारी सीमा रानी-सहित अन्य संबंधित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।

# एएसडीडी सूची में शामिल मतदाताओं का होगा भौतिक सत्यापन, बीएलओ दोबारा घर-घर जाकर करेंगे सत्यापन : डीसी

*एसडीडी मतदाताओं के भौतिक सत्यापन कार्य में सहयोग करने के लिए डीसी ने की सभी राजनीतिक दलों से अपील*

## *जिला के एएसडीडी सूची में शामिल 1 लाख 46 हजार 879 मतदाताओं को दोबारा वितरित किए जाएंगे एन्यूमरेशन फार्म*

*एसआईआर को लेकर डीसी वर्षा खांगवाल ने बुधवार को लघु सचिवालय में की सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक*

*ईसीआईनेट पोर्टल पर छूटे हुए मतदाता कर सकते हैं अपडेट*





***झज्जर, 11 नवंबर***

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत जिला में अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत एवं दोहरी प्रविष्टि (एएसडीडी) मतदाताओं को मतदाता सूची में नाम शामिल करवाने का एक और अवसर प्रदान किया जा रहा है। इसी कड़ी में बुधवार को लघु सचिवालय कार्यालय में डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी वर्षा खांगवाल ने विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर विशेष पुनरीक्षण प्रक्रिया के संबंध में विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बताया कि झज्जर जिला में एएसडीडी श्रेणी में शामिल 1 लाख 46 हजार 879 मतदाताओं को दोबारा एन्यूमरेशन फार्म (गणना प्रपत्र) वितरित किए जाएंगे। प्रत्येक पात्र मतदाता तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए बूथ स्तर अधिकारी (बीएलओ) दोबारा घर-घर जाकर भौतिक सत्यापन करेंगे। वहीं ईसीआईनेट पोर्टल पर छूटे हुए मतदाता भी कर सकते हैं स्वयं का डाटा अपडेट।

डीसी वर्षा खांगवाल ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र मतदाता मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने से वंचित न रहे। इसके लिए एएसडीडी श्रेणी में शामिल मतदाताओं की पहचान कर उनका दोबारा सत्यापन किया जाएगा। उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से अपील की कि वे अपने बूथ स्तर एजेंट के माध्यम से ऐसे मतदाताओं को तलाशने में बीएलओ का सहयोग करें, ताकि पात्र मतदाताओं से संपर्क स्थापित कर उन्हें निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार गणना प्रपत्र उपलब्ध करवाए जा सकें।

डीसी ने बताया कि एएसडीडी श्रेणी में शामिल मतदाताओं की सूचियां सीईओ हरियाणा की वेबसाइट और सभी मतदान केंद्रों पर चस्पा की जा चुकी हैं। इसके बावजूद यदि किसी मतदाता को सूची में शामिल किसी नाम को लेकर कोई आपत्ति है, तो वह संबंधित बीएलओ के समक्ष अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से कहा कि वे इस महत्वपूर्ण कार्य में प्रशासन का पूरा सहयोग करें और अपने स्तर पर मतदाताओं को जागरूक करें। उन्होंने अधिकारियों एवं बीएलओ को निर्देश दिए कि वे घर-घर जाकर संपर्क स्थापित करें और प्रत्येक पात्र मतदाता को निर्धारित प्रक्रिया की जानकारी देते हुए आवश्यक सहायता उपलब्ध करवाएं। उन्होंने कहा कि प्रशासन का प्रयास है कि पारदर्शी एवं व्यवस्थित तरीके से पुनरीक्षण कार्य पूरा हो और कोई भी पात्र नागरिक मताधिकार से वंचित न रहे।

***दोबारा उपलब्ध करवाए जाएंगे गणना प्रपत्र***

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि एएसडीडी श्रेणी के मतदाताओं के गणना प्रपत्र सभी बूथ स्तर अधिकारियों को उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। इसके बाद बीएलओ संबंधित मतदाताओं तक प्रपत्र पहुंचाने और उन्हें भरने में आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए उनके घर जाएंगे। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से भी आग्रह किया गया है कि वे अपने बूथ स्तर अभिकर्ताओं के माध्यम से ऐसे मतदाताओं की पहचान करवाने में सहयोग करें।

***दूसरे जिले में स्थायी रूप से स्थानांतरित मतदाता भी करवा सकेंगे प्रक्रिया पूरी***

डीसी ने बताया कि यदि कोई मतदाता स्थायी रूप से किसी अन्य जिले में स्थानांतरित हो चुका है, तो वह अपने गणना प्रपत्र को उस विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक पंजीयन अधिकारी के पास निर्धारित परिशिष्ट-सी के साथ जमा करवा सकता है, जहां वह वर्तमान में निवास कर रहा है। ऐसे मतदाताओं तक प्रपत्र पहुंचाने में भी बीएलओ को सहयोग करने के निर्देश दिए गए हैं। मतदाताओं को प्रपत्र व्हाट्सऐप, ई-मेल अथवा भौतिक रूप से उपलब्ध करवाने में भी सहायता की जाएगी।

***स्वयं या परिवार के सदस्य के माध्यम से जमा करवा सकेंगे गणना प्रपत्र***

डीसी ने कहा कि एएसडीडी सूची में शामिल मतदाता अपना विधिवत भरा हुआ गणना प्रपत्र संबंधित निर्वाचक पंजीयन अधिकारी, सहायक निर्वाचक पंजीयन अधिकारी अथवा बूथ स्तर अधिकारी के पास स्वयं या परिवार के किसी सदस्य के माध्यम से भौतिक रूप से जमा करवा सकते हैं। इसके अतिरिक्त निर्वाचन आयोग के ईसीआईनेट वेबसाईट माध्यम पर ई-हस्ताक्षर की सुविधा उपलब्ध होने पर प्रपत्र ऑनलाइन भी जमा करवाया जा सकेगा।

इस अवसर पर एसडीएम बहादुरगढ अभिनव सिवाच, एसडीएम बादली विशाल कुमार, एसडीएम बेरी रेणुका नांदल, सीटीएम ऋतु व निर्वाचन उप तहसीलदार कुलदीप सहित राजनीतिक दलों के प्रतिनिधिगण मौजूद रहे।

# समस्याओं का निराकरण ही प्रशासन की प्राथमिकता : डीसी





डीसी वर्षा खांगवाल ने कैम्प कार्यालय में की जनसुनवाई, लोगों की समस्याओं का मौके पर किया समाधान

शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों से पहुंचे नागरिकों ने रखी अपनी समस्याएं, डीसी ने संबंधित अधिकारियों को दिए त्वरित कार्रवाई के निर्देश

डीसी ने विगत जनसुनवाई के दौरान संबंधित अधिकारियों से समाधान की प्रगति की समीक्षा की

परिवहन विशेष न्यूज

**बहादुरगढ़, 11 नवंबर**

बहादुरगढ़ उपमंडल के लोगों की सार्वजनिक व व्यक्तिगत समस्याएं सुनकर उनका निदान सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिकता है। इसी सार्थक उद्देश्य के साथ डीसी वर्षा खांगवाल विभागीय अधिकारियों के साथ प्रत्येक बुधवार को लघु सचिवालय स्थित अपने कैम्प कार्यालय में जनसुनवाई करते हुए शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों से आए लोगों की समस्याओं और शिकायतों को गंभीरता से सुनकर समाधान सुनिश्चित कर रही हैं।

बुधवार को डीसी के समक्ष बहादुरगढ शहरी व ग्रामीण क्षेत्र से पहुंचे नागरिकों ने अपनी व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक समस्याएं रखी। डीसी ने प्रत्येक शिकायत को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को उनके शीघ्र एवं प्रभावी समाधान के निर्देश दिए। डीसी ने विगत जनसुनवाई के दौरान संबंधित अधिकारियों से समाधान की प्रगति की भी समीक्षा की।

जनसुनवाई के दौरान लोगों ने विभिन्न विभागों से जुड़ी समस्याओं, विकास कार्यों, मूलभूत सुविधाओं तथा प्रशासनिक कार्यों से संबंधित शिकायतें रखी। डीसी ने शिकायतकर्ताओं की बात ध्यानपूर्वक सुनी और संबंधित अधिकारियों से समस्याओं के समाधान को लेकर जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि आमजन की शिकायतों को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए और प्रत्येक शिकायत का प्राथमिकता के आधार पर निपटारा सुनिश्चित किया जाए।

**उपमंडल के नागरिकों को राहत देने के लिए हो रही बहादुरगढ़ में जनसुनवाई**

डीसी वर्षा खांगवाल ने कहा कि जिला प्रशासन का मुख्य उद्देश्य आमजन को पारदर्शी, जवाबदेह और समयबद्ध प्रशासनिक सेवाएं उपलब्ध करवाना है। जनसुनवाई प्रशासन और जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित करने का प्रभावी माध्यम है। इससे लोगों को अपनी समस्याएं सीधे प्रशासन के समक्ष रखने का अवसर मिलता है और उनके समाधान की प्रक्रिया में तेजी आती है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिकायतों के समाधान में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। प्रत्येक शिकायत पर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए उसकी प्रगति की निगरानी भी की जाए, ताकि शिकायतकर्ता को बार-बार कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।

डीसी ने कहा कि अधिकारी जनहित से जुड़े मामलों को संवेदनशीलता के साथ लें और आमजन की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर करें। प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वे नागरिकों की अपेक्षाओं पर खरा उतरते हुए जनसेवा की भावना से कार्य करें।

उन्होंने आमजन से भी अपील की कि वे अपनी समस्याओं एवं शिकायतों को प्रशासन के समक्ष रखें, ताकि उनका नियमानुसार समाधान किया जा सके। जिला प्रशासन जनता की समस्याओं के समाधान और बेहतर नागरिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है।

**डीसी ने ली अधिकारियों की बैठक**

डीसी ने जनसुनवाई उपरांत विभागीय अधिकारियों की बैठक लेते हुए सभी कार्यालय में मूमेंट रजिस्टर जरूर मेंटेन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कर्मचारी यदि फील्ड में जाता है तो उसकी एंट्री मूमेंट रजिस्टर में सुनिश्चित हो। उन्होंने पीडब्ल्यूडी व पंचायती राज विभाग के अधिकारियों को गांव में विकासात्मक कार्य करने में सजगता बनाये रखने को कहा ताकि ग्रामीणों को किसी प्रकार से परेशानी न हो। उन्होंने जनसुनवाई के दौरान आये परिवार पहचान पत्र से संबंधित मामलों में फिजिकल वेरिफिकेशन करते हुए शिकायत का समाधान करने के निर्देश सम्बंधित कर्मचारियों को दिए।

इस अवसर पर एसडीएम अभिनव सिवाच, तहसीलदार सुदेश मेहरा, नायब तहसीलदार प्रवीण, ईओ नगर परिषद संजय रोहिला, टीएम दीपक, एडीटीओ राजेश मलिक सहित भाजपा पूर्व जिलाध्यक्ष राजपाल जांगड़ा व अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।

# प्रदूषण नियंत्रण को लेकर जिला प्रशासन सख्त, विभागों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश

डीसी वर्षा खांगवाल ने ग्रैप-1, 2 और 3 के सभी प्रावधानों की प्रभावी पालना सुनिश्चित करने के दिए निर्देश

निर्माण एवं ध्वस्तीकरण गतिविधियों पर प्रतिबंध, स्टोन क्रशर व खनन गतिविधियां रहेंगी बंद

सड़कों की धूल, खुले में कचरा जलाने और पराली जलाने की घटनाओं पर रहेगी कड़ी निगरानी

परिवहन विशेष न्यूज

**झज्जर, 11 नवंबर**

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में वायु प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) द्वारा ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) के तीसरे चरण (ग्रैप-3) को प्रभावी रूप से क्रियान्वित किया जा रहा है। इसके तहत पहले से लागू ग्रैप-1 और ग्रैप-2 के उपायों के साथ ग्रैप-3 के सभी प्रावधानों की भी सख्ती से पालना सुनिश्चित की जाएगी। डीसी वर्षा खांगवाल ने जिला के सभी संबंधित विभागों एवं एजेंसियों को तत्काल प्रभाव से अपने-अपने क्षेत्र में आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

**निर्माण एवं ध्वस्तीकरण गतिविधियों पर प्रतिबंध, खनन कार्यों पर भी रहेगी रोक**

डीसी वर्षा खांगवाल ने निर्देश दिए कि ग्रैप-3 के तहत निर्माण एवं ध्वस्तीकरण से संबंधित प्रतिबंधित गतिविधियों पर पूरी तरह रोक सुनिश्चित की गई है। इसके अलावा स्टोन क्रशर और खनन गतिविधियों को बंद रखने के निर्देशों की भी प्रभावी अनुपालना करवाई जाए। संबंधित विभाग अपने-अपने क्षेत्र में नियमित निरीक्षण करें और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर तत्काल कार्रवाई करें।

**सड़कों की धूल और खुले में कचरा जलाने पर रखें विशेष निगरानी**

डीसी ने संबंधित विभागों को सड़कों पर उड़ने वाली धूल को नियंत्रित करने, खुले में कचरा एवं अन्य अपशिष्ट जलाने की घटनाओं पर रोक लगाने तथा प्रदूषण फैलाने वाले स्रोतों की पहचान कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने फील्ड स्तर पर निगरानी बढ़ाने और पर्याप्त कर्मचारियों एवं मशीनरी की तैनाती सुनिश्चित करने को कहा।

डीसी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि लागू प्रावधानों के अनुसार वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए आवश्यक जांच एवं कार्रवाई की जाए। वहीं, फसल अवशेष जलाने की घटनाओं की पुष्टि के लिए राजस्व एवं कृषि विभाग के अधिकारी फील्ड स्तर पर निगरानी रखें और उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई करें।

**रोजाना सुबह 10 बजे तक भेजनी होगी कार्रवाई रिपोर्ट**

डीसी वर्षा खांगवाल ने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए कि वे अपने विभाग से संबंधित कार्रवाई की प्रतिदिन की रिपोर्ट अगले दिन सुबह 10 बजे तक निर्धारित प्रारूप में जिला प्रशासन को भेजना सुनिश्चित करें। रिपोर्ट में किए गए निरीक्षण, पाई गई अनियमितताओं, की गई कार्रवाई तथा संबंधित फोटोग्राफ एवं अन्य साक्ष्य शामिल होने चाहिए। जहां किसी प्रकार की कार्रवाई अपेक्षित नहीं है, वहां भी निल रिपोर्ट भेजना अनिवार्य होगा।

**प्रदूषण नियंत्रण प्रशासन की प्राथमिकता, लापरवाही पर होगी कार्रवाई**

डीसी वर्षा खांगवाल ने कहा कि वायु प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए सभी विभाग आपसी समन्वय से कार्य करें और सीएक्यूएम द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की पूरी गंभीरता से पालना सुनिश्चित करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस कार्य में किसी भी स्तर पर लापरवाही या आदेशों की अवहेलना बर्दाश्त नहीं की जाएगी तथा संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी। उन्होंने आमजन से भी अपील की कि वे खुले में कचरा न जलाएं, धूल फैलाने वाली गतिविधियों से बचें और पर्यावरण संरक्षण में प्रशासन का सहयोग करें। जिला प्रशासन का प्रयास है कि प्रत्येक नागरिक को स्वच्छ एवं शुद्ध हवा उपलब्ध हो सके। इसके लिए सभी विभागों के साथ-साथ आमजन की भागीदारी भी बेहद जरूरी है।

# परिवहन विशेष समाचार पत्र दैनिक - जनहित में पर्यावरण जागरूकता

## त्योहार भी खुशियों से मनाएं - और - हवा को भी स्वच्छ रखें

परंपरा भी, पर्यावरण भी – दिवाली, दशहरा, गणेश चतुर्थी और दुर्गा पूजा की खुशी बिना धुएं और कचरे के भी मनाई जा सकती है

लेख डॉ परविंदर सिंह प्रस्तुतकर्ता प्रधान संपादक: संजय कुमार बाठला

**नई दिल्ली** - भारत के त्योहार प्रार्थना, खान-पान, संगीत, रोशनी और साझा परंपराओं के माध्यम से लोगों को एक साथ लाते हैं। ये उत्सव देश की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता को दर्शाते हैं।

लेकिन जब भारी भीड़, ट्रैफिक, आतिशबाजी और अस्थायी सजावटें एक साथ हो जाती हैं, तो वायु प्रदूषण बढ़ जाता है।

परिवहन विशेष समाचार पत्र दैनिक का स्पष्ट मत है - पर्यावरण की रक्षा करने का मतलब अपनी परंपराओं को छोड़ना नहीं है, बल्कि उन्हें समझदारी और सावधानी के साथ मनाना है।

**तथ्य एक नज़र में**

- त्योहार: दिवाली, दशहरा, गणेश चतुर्थी, दुर्गा पूजा और अन्य भारतीय उत्सव
- मुख्य समस्या: आतिशबाजी का धुआं, बारीक कण, शोर, ट्रैफिक जाम, सिंगल-यूज़ प्लास्टिक और अतिरिक्त कचरा
- सबसे ज्यादा प्रभावित: बच्चे, बुजुर्ग, बीमार लोग, पालतू जानवर
- समाधान: दीये, कम बिजली वाली लाइटें, पुनः उपयोग वाली सजावट, सार्वजनिक परिवहन, सफाई व्यवस्था

**मुख्य बिंदु**

1. आतिशबाजी से क्या नुकसान? धुआं और बारीक कण हवा की गुणवत्ता खराब करते हैं। शोर से बच्चों, बुजुर्गों, पालतू जानवरों और बीमार लोगों को परेशानी होती है।

2. ट्रैफिक और भीड़ का असर त्योहारों में अतिरिक्त वाहनों से ट्रैफिक जाम और उत्सर्जन बढ़ता है।

3. कचरा भी एक प्रदूषण है सजावट का सामान, खाने-पीने की पैकेजिंग और फेंका गया कचरा अतिरिक्त अपशिष्ट पैदा करता है।

4. छोटा बदलाव, बड़ा असर एक घर का बदलाव छोटा लगता है, लेकिन लाखों घरों का बदलाव बड़ी स्वच्छ हवा बन जाता है।

**विस्तृत विवरण**

भाग 1 - त्योहार हमारी पहचान हैं त्योहार केवल छुट्टी नहीं हैं। वे जीवन, कृतज्ञता और आपसी जुड़ाव का उत्सव हैं। हम जो हवा में सांस लेते हैं, उसकी देखभाल करना असल में एक-दूसरे की देखभाल करने जैसा ही है।

**भाग 2 – समस्या कहां है?**

1. समस्या परंपरा में नहीं, तरीके में है।

2. आतिशबाजी की जगह दीये, मोमबत्तियां या कम बिजली खपत वाली लाइटें भी उतनी ही रोशनी और खुशी दे सकती हैं।

सजावट के लिए ऐसी चीजों का इस्तेमाल किया जा सकता है जिन्हें दोबारा काम में लाया जा सके या जो प्राकृतिक हों।

**भाग 3 – क्या कर सकते हैं?**

- आतिशबाजी के बजाय दीये, मोमबत्ती, LED लाइटें
- सांस्कृतिक कार्यक्रम, संगीत और सामूहिक उत्सव - बिना आतिशबाजी के
- जुलूस और आयोजनों में डस्टबिन, सिंगल-यूज़ प्लास्टिक से बचाव, कार्यक्रम के बाद सफाई
- सार्वजनिक परिवहन, कारपूलिंग, जहां संभव हो पैदल चलना
- बच्चों को रचनात्मक, कम प्रदूषण वाले उत्सवों में शामिल करना

**भाग 4 – किसकी क्या भूमिका?**

- परिवार: घर से शुरुआत करें
- स्कूल और सामुदायिक नेता: सम्मानजनक तरीके से समझाएं, धुआं और कचरा कैसे नुकसान पहुंचाता है
- आयोजक: कचरा प्रबंधन और सफाई की व्यवस्था
- स्थानीय प्रशासन: स्पष्ट दिशा-निर्देश, कचरा संग्रहण में सुधार, नियमों का निष्पक्ष पालन

**संपादकीय टिप्पणी** स्वच्छ उत्सव मनाना किसी एक व्यक्ति पर बोझ नहीं, सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है।

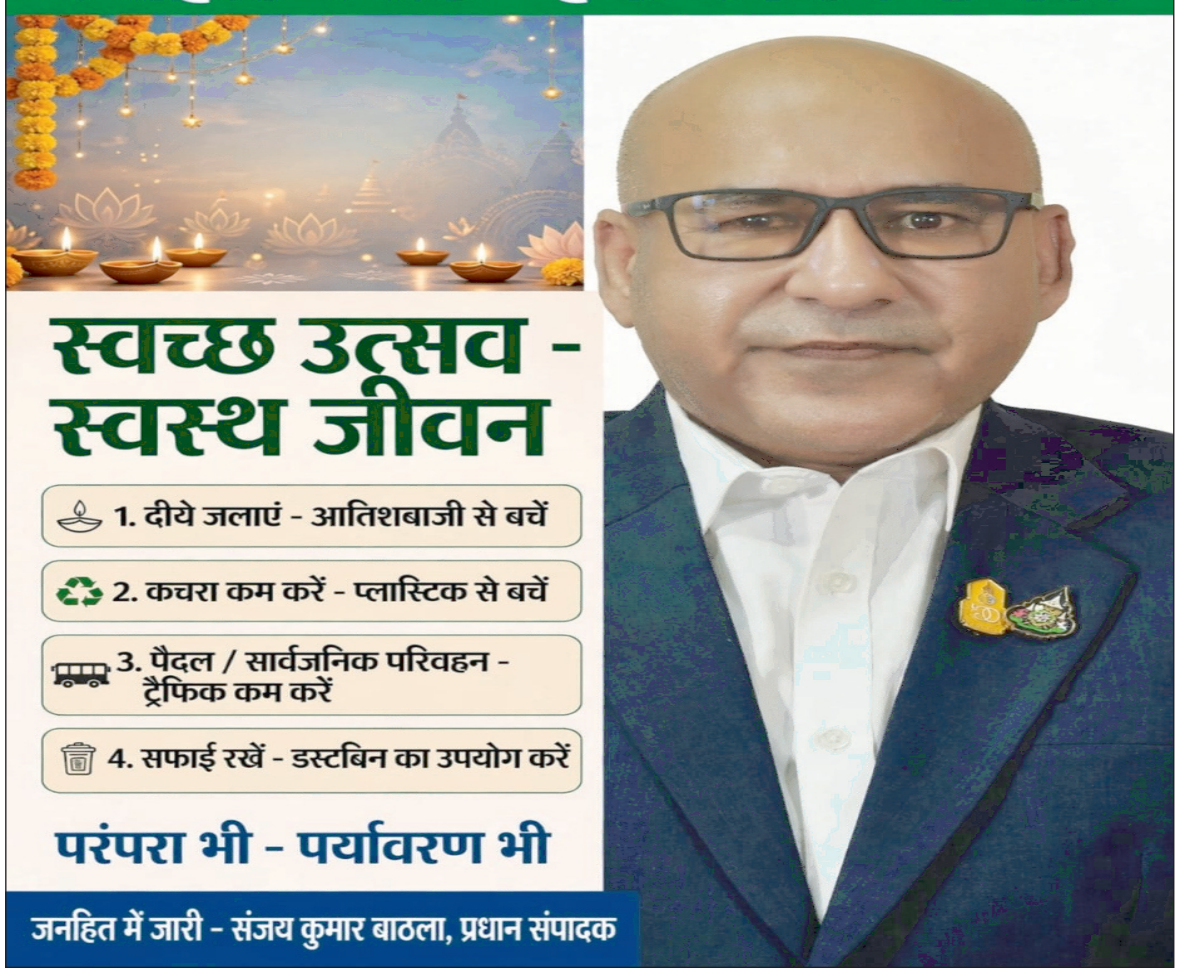
परंपराओं पर गर्व और पर्यावरण के प्रति जागरूकता को मिलाकर हम अपनी विरासत को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचा सकते हैं - और उनके लिए एक ऐसी स्वस्थ दुनिया छोड़ सकते हैं जहां वे खुशियां मना सकें।

**आज का संकल्प –**

परंपरा भी - पर्यावरण भी।

स्वच्छ उत्सव - स्वस्थ जीवन।

**– संजय कुमार बाठला, प्रधान संपादक, परिवहन विशेष समाचार पत्र दैनिक**




# टोल प्लाजा पर मनमानी और दुर्व्यवहार अब नहीं चलेगा! NHAI का बड़ा एक्शन, एजेंसी पर ₹ 15 लाख जुर्माना

बिजवासन टोल प्लाजा की घटना के बाद रिद्धि सिद्धि एसोसिएट्स पर गिरी गाज; एक महीने तक **NHAI** के टेंडर में भाग लेने पर प्रतिबंध, संचालकों को एक साल के प्रतिबंध का कारण बताओ नोटिस

रिपोर्ट डा राजकुमार यादव परिवहन विशेष समाचार पत्र

राष्ट्रीय राजमार्गों पर सफर करने वाले वाहन चालकों, ट्रक मालिकों और परिवहन कारोबारियों के लिए केंद्र सरकार की ओर से एक महत्वपूर्ण और राहत भरी खबर सामने आई है। टोल प्लाजा पर शुल्क वसूली के नाम पर यात्रियों के साथ दुर्व्यवहार, धमकी और मारपीट करने वाली एजेंसियों के खिलाफ भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने अब सख्त रुख अपना लिया है। प्राधिकरण ने स्पष्ट संकेत दिया है कि टोल वसूली का अधिकार किसी भी एजेंसी को सड़क उपयोगकर्ताओं के सम्मान और सुरक्षा से खिलवाड़ करने का लाइसेंस नहीं देता।

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा 11 नवंबर 2026 को जारी आधिकारिक सूचना के मुताबिक, दिल्ली के द्वारका एक्सप्रेसवे स्थित NH-248BB के बिजवासन टोल प्लाजा पर 5 नवंबर को सड़क उपयोगकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार और मारपीट की घटना हुई थी। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए NHAI ने टोल शुल्क संग्रहण करने वाली एजेंसी मेसर्स रिद्धि सिद्धि एसोसिएट्स पर 15 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

इतना ही नहीं, एजेंसी को NHAI के वर्तमान और भविष्य के टेंडरों में भाग लेने से एक महीने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। प्राधिकरण ने एजेंसी तथा उसके मालिकों और निदेशकों को एक साल तक भविष्य के टेंडरों से प्रतिबंधित करने के प्रस्ताव पर कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है।

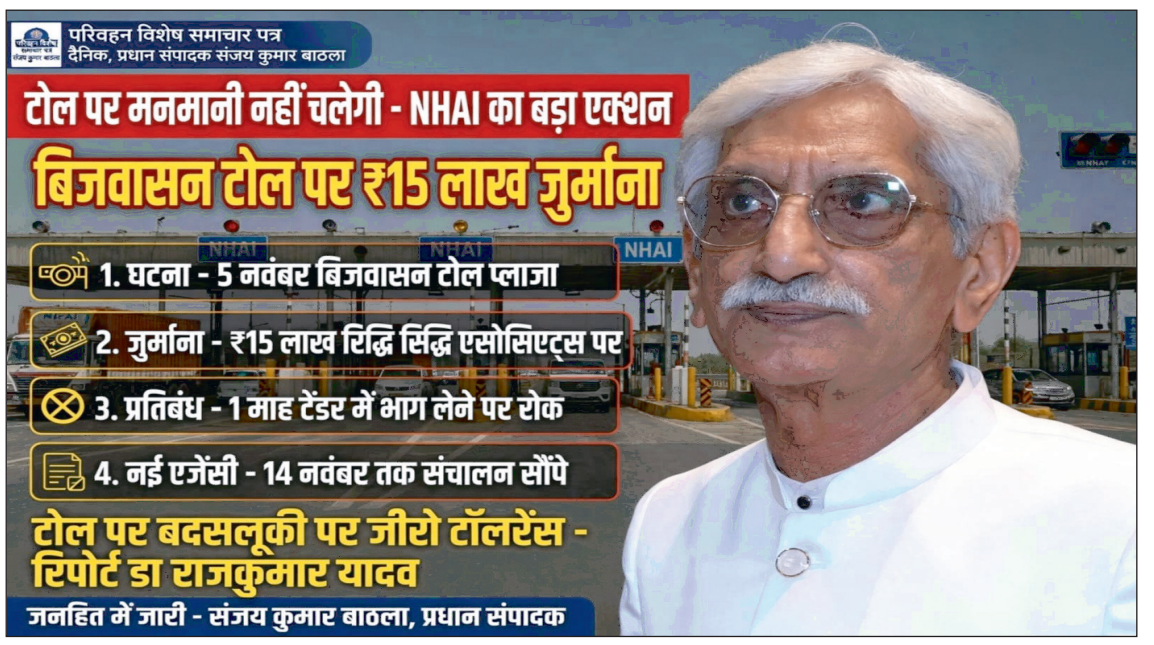
14 नवंबर तक नई एजेंसी को सौंपना होगा टोल संचालन NHAI ने मौजूदा एजेंसी को निर्देश दिया है कि वह 14 नवंबर 2026 तक बिजवासन टोल प्लाजा का संचालन नई एजेंसी को सौंप दे। यह कार्रवाई केवल आर्थिक दंड तक सीमित नहीं है, बल्कि टोल प्रबंधन में जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम है।

ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए महत्वपूर्ण संदेश इस कार्रवाई का संदेश देशभर के ट्रक मालिकों, ट्रांसपोर्टरों, बस संचालकों और निजी वाहन चालकों के लिए महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर प्रतिदिन हजारों किलोमीटर की यात्रा करने वाले वाहन चालकों को टोल प्लाजा पर सम्मानजनक व्यवहार और निर्बाध सुविधा मिलना उनका अधिकार है।

टोल कर्मचारी शुल्क भुगतान को लेकर विवाद की स्थिति में कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते। टोल एजेंसी की जिम्मेदारी है कि उसके कर्मचारी अनुशासन, शालीनता और निर्धारित नियमों के अनुरूप व्यवहार करें।

NHAI ने दोहराया है कि टोल प्लाजा पर किसी भी प्रकार की बदसलूकी, धमकी, उत्पीड़न अथवा शारीरिक हिंसा के प्रति उसकी नीति जीरो टॉलरेंस की है।

अब सवाल यह है कि क्या ऐसी जवाबदेही देश के अन्य टोल प्लाजाओं पर भी प्रभावी ढंग से लागू होगी? यदि इस कार्रवाई को पूरे देश में समान रूप से लागू किया जाता है, तो निश्चित रूप से सड़क उपयोगकर्ताओं और परिवहन उद्योग को बड़ी राहत मिल सकती है।




# DTC में बड़ा बदलाव: EPF वेतन सीमा 15,000 से बढ़कर 25,000 हुई - ठेका चालक, संवाहक और MTS को भी मिलेगा PF-पेंशन का पूरा लाभ

EPFO के नए आदेश 17 सितंबर 2026 से लागू, UAN 12 नवंबर तक अनिवार्य – चूक हुई तो अधिकारी पर होगी कार्रवाई

- लेखक : संजय कुमार बाठला

*– संपादकीय विभाग, परिवहन विशेष समाचार पत्र दैनिक*

मुख्य तथ्य - एक नज़र में

- आदेश जारीकर्ता: दिल्ली परिवहन निगम, लेखा विभाग, भविष्य निधि (मुख्यालय)
- कार्यालय आदेश संख्या: DTC/PF/2026/354
- दिनांक: 06/11/2026
- आधार: EPFO पत्र संख्या ACC/DL&UT/J&K and Ladakh/PPS/2026/1452 दिनांक 25.09.2026
- बड़ा बदलाव: EPF, EPS-95 और EDLI के लिए वैधानिक वेतन सीमा ₹15,000/- से बढ़कर ₹25,000/- प्रति माह
- लागू तिथि: 17.09.2026 से
- UAN की अंतिम तिथि: 12.11.2026 तक हर हाल में पूर्ण
- किसे लाभ: नियमित + ठेकेदारों के माध्यम से नियोजित सभी पात्र कर्मचारी
- हस्ताक्षर: (सोनम), प्रबंधक भविष्य निधि

› **संपादकीय स्पष्टीकरण:** यह लेख DTC के कार्यालय आदेश DTC/PF/2026/354 दिनांक 06/11/2026 के आधार पर है। वेतन, तिथि और प्रक्रिया की अंतिम पुष्टि संबंधित डिपो / भविष्य निधि विभाग से करें।

**1. *क्या है नया आदेश** - क्यों है इतना महत्वपूर्ण? दिल्ली परिवहन निगम ने अपने सभी डिपो, इकाई और क्षेत्रीय प्रबंधकों को एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है।

EPFO ने अनिवार्य EPF, EPS-95 और EDLI कवरेज के लिए वैधानिक वेतन सीमा ₹15,000/- से बढ़ाकर ₹25,000/- प्रति माह कर दी है। यह बदलाव 17.09.2026 से लागू है।

मतलब साफ है - अब 25,000 रुपये तक वेतन पाने वाले सभी पात्र कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा कवरेज देना अनिवार्य है। पहले जो कर्मचारी 15,000 की सीमा से ऊपर होने के कारण EPF-EPS से बाहर थे, अब वे भी अंदर आ जाएंगे।

यह आदेश DTC के हजारों ठेका कर्मचारियों के लिए जीवन बदलने वाला है। अब तक ठेका चालक, संवाहक और MTS को कई बार PF-पेंशन का पूरा लाभ नहीं मिलता था। अब उन्हें भी वही सुरक्षा मिलेगी जो नियमित कर्मचारी को मिलती है।

**2. *किस-किस को कवर करना है? Principal Employer को निर्देश है कि:**

- नियमित कर्मचारी + ठेकेदारों के माध्यम से नियोजित कर्मचारी - दोनों की व्यापक समीक्षा हो
- संशोधित सीमा में आने वाले सभी पात्र कर्मचारियों का EPF, EPS-95 और EDLI कवरेज सुनिश्चित किया जाए

मतलब: ठेकेदार कहे कि यह मेरा आदमी है, DTC कहे कि यह ठेकेदार का है - यह बहानेबाजी अब नहीं चलेगी। Principal Employer के रूप में DTC की जिम्मेदारी है कि हर पात्र कर्मचारी का कवरेज हो।

**3. *ठेका कर्मचारियों का वेतन - EPFO पोर्टल पर क्या दर्ज होगा? आदेश में ठेका कर्मचारियों के लिए वेतन स्पष्ट कर दिया गया है:**

श्रेणी - गणना - मासिक वेतन

अनुबंधित चालक एवं संवाहक 862 x 26 ₹22,412/- प्रति माह

अनुबंधित MTS 710 x 26 ₹18,460/- प्रति माह

- नियुक्ति तिथि (Date of Joining): सभी की 17.09.2026 दर्ज की जाएगी

ध्यान दें: दोनों श्रेणियों का वेतन अब 25,000 की नई सीमा के अंदर आ गया है, इसलिए दोनों को EPF, EPS-95 का लाभ मिलेगा।

**4. *UAN क्या है - और क्यों है इतना जरूरी?** UAN यानी Universal Account Number - कर्मचारी का PF खाता नंबर। इसके बिना PF जमा नहीं होगा, पेंशन नहीं बनेगी।

**आदेश के अनुसार:**

(क) *पात्र कर्मचारियों की पहचान: हर डिपो / इकाई में कर्मचारीवार समीक्षा तत्काल हो।

(ख) *UAN की जांच:

- जिनका UAN पहले से है - उनकी KYC करके EPFO पोर्टल पर DTC में IN किया जाए
- जिनका UAN नहीं है - उन्हें नोटिस बोर्ड से सूचना दी जाए कि वे Android मोबाइल में UMANG APP download करके EPFO विकल्प चुनकर UAN Allotment एवं Activation में आधार कार्ड व मोबाइल नंबर दर्ज करके UAN generate करें
- जिनके पास Android फोन नहीं है - वे किसी अन्य के फोन से UAN generate करके अपने Depot के Dealing Assistant को उपलब्ध कराएं

**संपादकीय सलाह:** UAN बनवाना सिर्फ अधिकारी का काम नहीं है, कर्मचारी का अपना हक है। अगर आपका UAN नहीं बना, तो आपका PF पैसा कहीं नहीं जाएगा। आज ही बनवाएं।

5. *गलत EPS सदस्यता का सुधार - सबसे तकनीकी लेकिन जरूरी हिस्सा कई कर्मचारियों को पहले गलती से EPS सदस्य बना दिया गया था, जबकि उन्हें नहीं बनना चाहिए था। आदेश में इसका सुधार बताया गया है:

**स्थिति 1:**

- UAN 31.07.2022 से पूर्व बना है
- कर्मचारी 31.07.2022 से पहले से DTC में है
- Payslip में Pension Status 'N' है
- तो क्या करें: EPFO Portal पर उसकी Date of Exit 31.07.2022 दर्ज करें, फिर पुनः Date of Joining 17.09.2026 दर्ज करके DTC में IN करें

**स्थिति 2:**

- UAN 31.07.2022 के बाद बना है
- Pension Status ₹N₹ है
- तो क्या करें: जिस दिन UAN बना, उसी तिथि को Date of Exit दर्ज करें, फिर पुनः Date of Joining 17.09.2026 दर्ज करके IN करें

**मतलब:** पुरानी गलती को ठीक करके 17.09.2026 से नया, सही कवरेज शुरू होगा।

**6. *समय-सीमा - 12 नवंबर 2026 - कोई बहाना नहीं चलेगा**

- सभी पात्र कर्मचारियों के UAN की उपलब्धता / जनरेशन की कार्यवाही हर हाल में दिनांक 12.11.2026 तक पूर्ण होनी अनिवार्य है
- इसके बाद कोई UAN लंबित पाया गया तो विलंब के कारणों के साथ उत्तरदायी अधिकारी / कर्मचारी का विवरण रिपोर्ट में देना होगा
- विषय में लिखा है UAN दिनांक 10.10.2026 तक बनाने के संबंध में, लेकिन आदेश के अंदर अंतिम समय-सीमा 12.11.2026 दी गई है

**संपादकीय मत:** तिथि में यह अंतर भ्रम पैदा करता है। DTC मुख्यालय को स्पष्ट करना चाहिए कि अंतिम तिथि 12.11.2026 ही मान्य है। लेकिन कर्मचारी 12 तारीख का इंतजार न करें, आज ही UAN बनवाएं।

**7. *EPF / EPS-95 अंशदान - पैसा समय पर जमा हो**

- UAN जनरेशन के बाद पात्र कर्मचारियों का EPF / EPS-95 अंशदान EPFO को समय पर जमा कराना सुनिश्चित करें, ताकि UAN के कारण अंशदान में विलंब न हो
- अक्टूबर माह का EPS-95 अंशदान EPFO कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारीवार विवरण Computer Cell, BBM Payroll एवं भविष्य निधि विभाग, DTC मुख्यालय को अविलंब भेजें

**कर्मचारी को क्या जांचना चाहिए?**

- आपकी Payslip में EPF कटौती हो रही है?
- EPFO पोर्टल / UMANG APP पर आपका PF Balance दिख रहा है?
- अगर नहीं दिख रहा, तो तुरंत Dealing Assistant को बताएं।

**8. *ठेकेदारों के कर्मचारियों के लिए - ठेकेदार की जिम्मेदारी सभी डिपो / इकाई प्रभारी ठेकेदारों को निर्देश दें कि वे:**

1. संशोधित सीमा में आने वाले सभी पात्र कर्मचारियों की पहचान करें
2. प्रत्येक का UAN उपलब्ध हो
3. EPF / EPS-95 नामांकन / सदस्यता सत्यापित करें
4. अंशदान समय पर जमा करें
5. कर्मचारीवार UAN, वेतन व अंशदान विवरण DTC को दें

ठेकेदार अनुपालन न करे तो मामला तत्काल उच्च अधिकारी के संज्ञान में लाया जाए।

**संपादकीय मत:** ठेका कर्मचारी DTC की बस चलाता है, DTC का नाम लेकर जनता की सेवा करता है। उसके PF में ठेकेदार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए।

**9. *अनुपालन रिपोर्ट - कौन, कब, किसे भेजेगा?**

- प्रत्येक क्षेत्रीय प्रबंधक / डिपो प्रबंधक / इकाई अधिकारी अपनी समेकित कर्मचारीवार अनुपालन रिपोर्ट 12.11.2026 तक अनिवार्य रूप से प्रबंधक, Computer Cell, BBM Payroll तथा भविष्य निधि विभाग, DTC मुख्यालय को भेजेंगे
- रिपोर्ट में प्रमाणित करना होगा कि संशोधित सीमा में आने वाले सभी पात्र कर्मचारियों की समीक्षा कर ली गई है और UAN उपलब्धता / जनरेशन सुनिश्चित कर दी गई है

**10. *अधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी - कागजी खानापूर्ति नहीं चलेगी**

- यह कार्यवाही केवल कागजी अनुपालन तक सीमित नहीं रहेगी
- क्षेत्रीय / डिपो / इकाई अधिकारी व्यक्तिगत रूप से निगरानी करेंगे और निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण अनुपालन के लिए उत्तरदायी होंगे
- आदेश की अवहेलना, अनावश्यक विलंब या समय पर रिपोर्ट न देने पर सेवा / प्रशासनिक / संविदात्मक एवं अन्य वैधानिक प्रावधानों के अनुसार उत्तरदायित्व निर्धारित करने की कार्रवाई हो सकती है

मतलब साफ है - अब बहाना नहीं, जिम्मेदारी तय होगी।

11. *कर्मचारी के लिए 5 तुरंत काम - जनहित में

1. आज ही UAN चेक करें - नहीं है तो UMANG APP से बनाएं
2. आधार, मोबाइल, बैंक विवरण सही कराएं - KYC अधूरी तो PF अटकेगा
3. UAN बनने के बाद तुरंत अपने Depot के Dealing Assistant को दें
4. Payslip में Pension Status चेक करें - अगर ₹N₹ है तो ऊपर वाला सुधार वाला नियम लागू होगा
5. PF Balance हर महीने चेक करें - UMANG APP पर EPF Passbook देखें

**12. *संपादकीय निष्कर्ष** DTC का यह आदेश सिर्फ एक सर्कुलर नहीं है, यह सामाजिक सुरक्षा का विस्तार है।

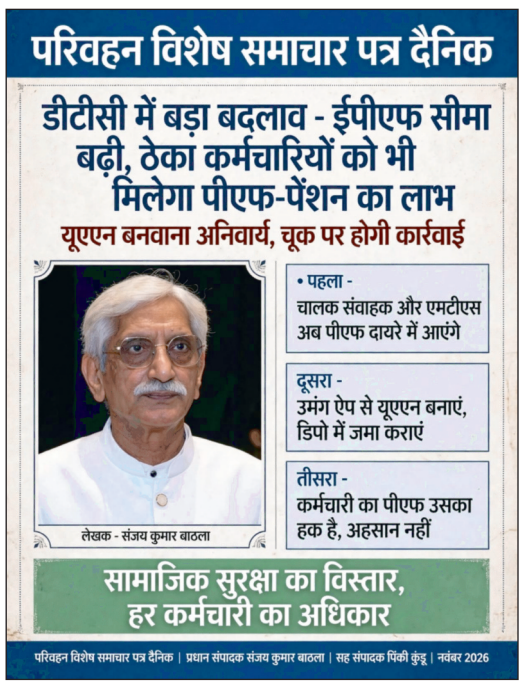
15,000 से 25,000 की सीमा बढ़ने का मतलब है - अब ज्यादा कर्मचारी PF, पेंशन और बीमा के दायरे में आएंगे। बुढ़ापे में पेंशन मिलेगी, बीमारी में PF काम आएगा, परिवार को EDLI का सुरक्षा कवच मिलेगा।

लेकिन आदेश तभी सार्थक होगा जब 12 नवंबर तक हर डिपो में हर पात्र कर्मचारी का UAN बन जाएगा, PF जमा हो जाएगा।

परिवहन विशेष समाचार पत्र दैनिक की मांग है - DTC मुख्यालय हर डिपो की दैनिक प्रगति रिपोर्ट सार्वजनिक करे, और जो ठेकेदार या अधिकारी लापरवाही करे, उस पर तत्काल कार्रवाई हो।

कर्मचारी का PF उसका हक है, अहसान नहीं।

**– संजय कुमार बाठला, प्रधान संपादक**



# 500 का नोट बंद करने से नहीं, कानूनबंदी से टूटेगा भ्रष्टाचार का साम्राज्य

रिश्वत, हवाला, कालाधन और चुनावी धनबल पर एक साथ कानूनी सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत - नोट बदलने से ज्यादा व्यवस्था बदलना जरूरी

**लेखक : एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी, गोंदिया, महाराष्ट्र परिवहन विशेष समाचार पत्र दैनिक**

**> संपादकीय स्पष्टीकरण:** यह लेख लेखक के नीतिगत प्रस्ताव / मत के रूप में प्रस्तुत है। इसमें सुझाए गए संशोधन वर्तमान कानून का वर्णन नहीं हैं, बल्कि संसद, विधि आयोग और संवैधानिक विशेषज्ञों की समीक्षा के लिए प्रस्ताव हैं। यूएपीए, बीएनएस, एनएसए और मृत्युदंड जैसे विषयों में नागरिक स्वतंत्रता, निर्दोषता की धारणा और न्यायिक प्रक्रिया की रक्षा अनिवार्य है।

**मुख्य तथ्य - एक नज़र में**

- **8 नवंबर 2016:** 500 और 1,000 रुपये के पुराने नोट चलन से बाहर किए गए - नोटबंदी
- **अब नई बहस:** आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू का सुझाव - 500 रुपये का नोट बंद करें, डिजिटल मुद्रा बढ़े
- **लेखक का मत:** भ्रष्टाचार की जड़ 500 का नोट नहीं, पूरी व्यवस्था है - रिश्वत, ठेकों में कमीशन, बेनामी संपत्ति, फर्जी कंपनियां, चुनावी धनबल, हवाला, मनी लॉन्ड्रिंग
- **कानूनी आधार:** भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, बेनामी कानून 1988 / 2016, पीएमएलए 2002, बीएनएस 2023, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, एफसीआरए 2010, लोकपाल अधिनियम 2013, व्हिसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट 2014
- **आयकर कानून:** धारा 269ST - एक व्यक्ति से एक दिन में, एक लेन-देन में 2 लाख रुपये या अधिक नकद लेने पर प्रतिबंध, अपवादों के अधीन
- लेखक की मांग: भारत को व्यापक राष्ट्रीय भ्रष्टाचार उन्मूलन नीति चाहिए, प्रधानमंत्री से निर्णायक पहल की अपील

1. नोटबंदी बनाम कानूनबंदी - असली समाधान कहां है? 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी हुई। लगभग 10 वर्ष बाद भी भ्रष्टाचार और काले धन की बहस खत्म नहीं हुई।

अब 500 रुपये का नोट बंद करने का सुझाव फिर आया है। तर्क है - बड़े मूल्य के नकद लेन-देन पर अंकुश लगेगा, डिजिटल मुद्रा बढ़ेगी, भ्रष्टाचार और वित्तीय धोखाधड़ी कम होगी। लेखक का स्पष्ट मत है - यह तर्क अधूरा है। 500 का नोट बंद करने से रिश्वत अपने आप खत्म नहीं होगी। भ्रष्ट व्यक्ति 100, 200 रुपये, विदेशी मुद्रा, सोना, जमीन, बेनामी संपत्ति, डिजिटल माध्यम, फर्जी कंपनियों या दूसरे वित्तीय रास्तों का उपयोग कर सकता है।

**दूसरी ओर, आम आदमी पर बोझ पड़ेगा:**

- किसान, छोटे दुकानदार, रेहड़ी-पटरी व्यवसायी, मजदूर, ग्रामीण - नकदी पर निर्भर हैं
- डिजिटल सुविधा से वंचित नागरिकों के दैनिक लेन-देन पर दबाव पड़ेगा
- 100 रुपये से बड़ी सभी करेंसी बंद करने और 1,000 रुपये से अधिक नकद लेन-देन पर पूर्ण प्रतिबंध का प्रस्ताव व्यावहारिकता, महंगाई और नागरिक स्वतंत्रता के दृष्टिकोण से गंभीर समीक्षा मांगता है

इसलिए लेखक कहता है - मुद्रा का स्वरूप बदलने से ज्यादा जरूरी है, अपराध करने वाले व्यक्ति, उसके सहयोगियों, वित्तीय नेटवर्क और संरक्षण देने वाली व्यवस्था पर कठोर, पारदर्शी और प्रभावी कानूनी कार्रवाई करना।

१. नकद लेन-देन पर कानून पहले से है - जरूरत लागू करने की है आयकर अधिनियम, 1961 में पहले से व्यवस्था है:

- धारा 269ST: एक व्यक्ति से एक दिन में, एक लेन-देन में अथवा एक आयोजन से संबंधित लेन-देन में 2 लाख रुपये या अधिक नकद प्राप्त करने पर प्रतिबंध, निर्धारित अपवादों के अधीन
- धारा 269SS और 269T: ऋण एवं जमा के नकद लेन-देन को नियंत्रित करती हैं
- धारा 271D, 271DA, 271E: उल्लंघन पर दंड का प्रावधान

**लेखक का तर्क:** जरूरत इन व्यवस्थाओं को प्रभावी बनाने, वास्तविक लाभार्थी की पहचान करने और बड़े संदिग्ध लेन-देन की जांच मजबूत करने की है, न कि केवल नोट का आकार बदलने की।

२. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 - सबसे पहला मोर्चा इस कानून को अधिक प्रभावी बनाने की जरूरत है:

- धारा 7: सरकारी कर्मचारी द्वारा रिश्वत लेना
- धारा 7A: प्रभाव के माध्यम से भ्रष्ट तरीके से सरकारी काम करवाना
- धारा 8: रिश्वत देना
- धारा 9: वाणिज्यिक संगठनों की रिश्वतखोरी
- धारा 13: लोकसेवक द्वारा आपराधिक कदाचार
- धारा 17A: कुछ सरकारी निर्णयों की जांच से पहले पूर्व स्वीकृति
- धारा 19: अभियोजन स्वीकृति

**लेखक के प्रस्ताव:**

- समयबद्ध स्वीकृति हो - स्वीकृति फाइल में सालों तक न अटके
- स्वतंत्र जांच हो
- सरकारी ठेकों और संपत्ति के स्रोत की जांच हो
- दोषसिद्धि पर अनुपातहीन संपत्ति जब्त हो
- गंभीर मामलों में त्वरित सुनवाई हो

**सावधानी:** ईमानदार प्रशासनिक निर्णयों को आपराधिक मुकदमे में बदलने से बचाना होगा, नहीं तो अधिकारी निर्णय लेने से डरेंगे।

4. बेनामी संपत्ति कानून - असली मालिक तक पहुंचना होगा बेनामी संपत्ति लेन-देन निषेध अधिनियम, 1988, जिसे 2016 में व्यापक संशोधन से मजबूत किया गया:

- धारा 3: बेनामी लेन-देन पर प्रतिबंध
- धारा 24: अस्थायी कुर्की
- धारा 27: संपत्ति की जब्ती
- धारा 53: बेनामी लेन-देन के लिए दंडात्मक कार्रवाई

**लेखक के प्रस्ताव:**

- रिश्वत, अवैध ठेके, हवाला और पद के दुरुपयोग से अर्जित संपत्ति के वास्तविक मालिक तक पहुंचा जाए
- संपत्ति और लाभकारी स्वामित्व के अभिलेखों का सत्यापन आधार, पैन, भूमि अभिलेख और वित्तीय सूचनाओं से हो
- सावधानी: आधार को संपत्ति का स्वतः मालिकाना प्रमाण नहीं माना जाना चाहिए

5. पीएमएलए, 2002 - मनी लॉन्ड्रिंग के नेटवर्क पर प्रहार धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002:

- धारा 3: मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध
- धारा 4: सजा
- धारा 5: संपत्ति की अस्थायी कुर्की
- धारा 8: जब्ती
- धारा 12: रिपोर्टिंग संस्थाओं के दायित्व
- धारा 45: जमानत की शर्तें




**लेखक का तर्क:** भ्रष्टाचार से अर्जित धन को अनेक कंपनियों, संपत्तियों और विदेशी खातों में घुमाकर वैध दिखाया जाता है। इस नेटवर्क पर कार्रवाई के लिए वित्तीय खुफिया इकाइयों, प्रवर्तन निदेशालय और अन्य जांच एजेंसियों के बीच सटीक समन्वय आवश्यक है।

**6. बीएनएस, 2023** - संगठित आर्थिक अपराध के लिए अलग अध्याय की मांग भारतीय न्याय संहिता, 2023 में संगठित आर्थिक अपराध और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच संबंध को अधिक स्पष्ट करने की जरूरत है:

- धारा 111: संगठित अपराध
- धारा 113: आतंकवादी कृत्य
- धारा 147: भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने या उसका प्रयास
- धारा 152: भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्य

सबसे महत्वपूर्ण कानूनी सावधानी - लेखक स्वयं कहता है:

> हर रिश्वत, हवाला या काला धन अपने आप आतंकवाद अथवा देशद्रोह नहीं बन जाता। इन धाराओं को सामान्य भ्रष्टाचार पर अंधाधुंध लागू करना उचित नहीं होगा।

**प्रस्ताव:**

- बीएनएस में अलग अध्याय हो - भ्रष्टाचार एवं संगठित आर्थिक अपराध
- इसमें उच्चस्तरीय सरकारी भ्रष्टाचार, सार्वजनिक धन की संगठित लूट, ठेकों में मिलीभगत, रिश्वत के अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क, चुनावी अवैध वित्तपोषण, सरकारी संस्थाओं को योजनाबद्ध तरीके से कमजोर करना - इनकी स्पष्ट परिभाषा हो
- धारा 111 में गंभीर और निरंतर संगठित भ्रष्ट आर्थिक अपराधों को शामिल करने पर विचार हो
- धारा 113 और 152 का इस्तेमाल केवल तभी हो, जब आतंकवादी गतिविधि या संप्रभुता को खतरे के कानूनी तत्व और आवश्यक आपराधिक मंशा प्रमाणित हों

इससे भ्रष्टाचार के विरुद्ध मजबूत सुरक्षा कवच बनेगा, लेकिन कानून का दुरुपयोग भी नहीं होगा।

**7. रुवाला, विदेशी फंडिंग और चुनावी धनबल**

एफसीआरए, 2010:

- धारा 3: विदेशी योगदान प्राप्त करने से प्रतिबंधित व्यक्ति और संस्थाएं
- धारा 7: विदेशी योगदान के हस्तांतरण पर रोक
- धारा 8: प्रशासनिक खर्च की सीमा
- धारा 35: उल्लंघन के लिए दंड

**लेखक के प्रस्ताव:**

- विदेशी फंडिंग के वास्तविक स्रोत, अंतिम लाभार्थी, शैक्षणिक संस्थाओं, गैर-सरकारी संगठनों के वित्तीय लेखा-परीक्षण को पारदर्शी बनाया जाए
- सावधानी: वैध सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक और मानवीय गतिविधियों के लिए मिलने वाले विदेशी योगदान को भ्रष्टाचार के साथ जोड़कर संदेहास्पद नहीं बनाना चाहिए
- फेमा, 1999 और COFEPOSA, 1974 की व्यवस्थाओं का समन्वित उपयोग हो
- रुवाला में वित्तीय जांच, बैंकिंग रिकॉर्ड, संदिग्ध लेन-देन की रिपोर्टिंग और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को प्राथमिकता दी जाए

चुनावी भ्रष्टाचार: लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धाराएं 77, 78, 123, 125 तथा चुनावी व्यय और रिश्वत से संबंधित प्रावधानों को अधिक प्रभावी बनाया जाए। प्रत्याशियों के चुनावी खर्च, वास्तविक चंदा देने वालों और राजनीतिक दलों के वित्तीय लेन-देन की स्वतंत्र जांच व्यवस्था विकसित हो।

**8. क्या आजीवन चुनाव प्रतिबंध और मृत्युदंड होना चाहिए? - सबसे संवेदनशील प्रश्न**

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951, धारा 8: कुछ अपराधों में दोषसिद्धि पर चुनाव लड़ने की अयोग्यता का प्रावधान है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दोषसिद्ध व्यक्ति भी इस दायरे में आते हैं।

**लेखक का प्रस्ताव - संतुलित:**

- गंभीर और जानबूझकर किए गए भ्रष्टाचार, सार्वजनिक धन की संगठित लूट और उच्चस्तरीय वित्तीय अपराधों में अंतिम दोषसिद्धि पर आजीवन चुनावी अयोग्यता पर संसद विचार कर सकती है
- लेकिन केवल एक दिन की सजा, हर प्रकार के अपराध या अपील के अधिकार को नजरअंदाज करके आजीवन प्रतिबंध लगाना न्यायसंगत नहीं होगा
- अपराध की गंभीरता, न्यायिक प्रक्रिया और संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता) तथा अनुच्छेद 21 (जीवन और स्वतंत्रता) की कसौटी पर यह व्यवस्था खरी उतरनी चाहिए

**मृत्युदंड पर लेखक का स्पष्ट मत:**

- मृत्युदंड को भ्रष्टाचार के लिए सामान्य सजा बनाना उचित नहीं है
- गंभीर भ्रष्टाचार में कठोर कारावास, अवैध संपत्ति की जब्ती और आर्थिक दंड अधिक तर्कसंगत उपाय हैं

**9. एनएसए, लोकपाल और जमीनी व्यवस्था**

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980:

- यह निवारक निरोध का कानून है, सामान्य भ्रष्टाचार का मुकदमा चलाने या सजा देने का कानून नहीं
- इसलिए भ्रष्टाचार को स्वतः राष्ट्रीय सुरक्षा अपराध घोषित करके एनएसए लागू करना उचित नहीं होगा
- गंभीर संगठित वित्तीय अपराधों और आतंकवादी वित्तपोषण के बीच प्रमाणित संबंध होने पर ही संबंधित आपराधिक कानूनों का उपयोग हो

**लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013:**

- धारा 14, 20, 23 - लोकपाल के अधिकार क्षेत्र, प्रारंभिक जांच, अभियोजन से जुड़ी व्यवस्थाएं
- केंद्र में लोकपाल, राज्यों में लोकायुक्त को पर्याप्त कर्मचारी, स्वतंत्र वित्तीय संसाधन और समयबद्ध जांच की शक्ति मिले
- महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश सहित सभी राज्यों में एक समान जवाबदेही के मानक हों

**जमीनी भ्रष्टाचार** - जहां आम आदमी रोज टकराता है: पटवारी, तहसील कार्यालय, पुलिस थाना, नगर निकाय, कलेक्टर कार्यालय, पंजीयन विभाग, सरकारी अस्पताल, मंत्रालय - यहां रिश्वत रोकने के लिए:

- सार्वजनिक सेवा गारंटी कानून
- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
- ई-गवर्नेंस व्यवस्था मजबूत हो
- हर सरकारी भुगतान, निविदा, भूमि हस्तांतरण, अनुमति और ठेके की डिजिटल निगरानी हो
- जहां नकद भुगतान की कानूनी अनुमति है, वहां भी उचित रसीद और लेखा-परीक्षण अनिवार्य हो

10. शिकायतकर्ता की सुरक्षा और फास्ट ट्रैक अदालतें भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए शिकायतकर्ता को सबसे मजबूत सुरक्षा देनी होगी।

व्हिसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट, 2014 को प्रभावी रूप से लागू किया जाए:

- शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रहे
- धमकी मिलने पर सुरक्षा मिले
- नौकरी में प्रताड़ना से बचाव हो
- दुर्भावनापूर्ण झूठी शिकायत और सद्भावना से की गई शिकायत में अंतर हो
- प्रमाणित भ्रष्टाचार की सूचना देने वालों को बरामद धन के अनुपात में पारदर्शी आर्थिक प्रोत्साहन पर विचार हो

**फास्ट ट्रैक व्यवस्था:**

- भ्रष्टाचार के मामलों के लिए विशेष जांच दल, स्वतंत्र अभियोजन अधिकारी और विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें बनें
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की तरह शिकायतकर्ता की सुरक्षा और विशेष अदालतों की व्यवस्था से प्रेरणा ली जा सकती है, लेकिन दोनों कानूनों के अलग-अलग संवैधानिक उद्देश्य और अपराधों की प्रकृति को ध्यान में रखना होगा
- गवाह संरक्षण, समयबद्ध सुनवाई और अपील की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित हो

**शिक्षा में भी बदलाव:** भ्रष्टाचार विरोधी पाठ्यक्रम, वित्तीय साक्षरता, डिजिटल भुगतान का प्रशिक्षण, नैतिक शिक्षा और नागरिक अधिकारों की जानकारी शामिल हो। केवल कानून कठोर बनाने से भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा, जब तक अगली पीढ़ी में ईमानदारी और सार्वजनिक संपत्ति के प्रति जिम्मेदारी विकसित नहीं होगी।

**11. संपादकीय निष्कर्ष** - नोट पर नहीं, नस पर वार 500 का नोट बंद करना आसान है, भ्रष्टाचार की नस पर वार करना कठिन है। नोट बदलने से भ्रष्टाचारी रास्ता बदल लेगा, कानून बदलने से भ्रष्टाचारी की हिम्मत टूटेगी।

**भारत को आज चाहिए:**

1. एक व्यापक राष्ट्रीय भ्रष्टाचार उन्मूलन नीति
२. भ्रष्टाचार निवारण, बेनामी, पीएमएलए, बीएनएस में संतुलित और प्रभावी संशोधन
3. समयबद्ध जांच, फास्ट ट्रैक अदालतें, संपत्ति जब्ती
4. शिकायतकर्ता की सुरक्षा
5. चुनावी धनबल पर पारदर्शिता
6. और सबसे ऊपर - संविधान के अनुच्छेद 14, 21 की रक्षा

भ्रष्टाचार मुक्त भारत सिर्फ नारा नहीं, कानून, नैतिकता और जवाबदेही का संकल्प होना चाहिए।

**- संजय कुमार बाठला, प्रधान संपादक**




# गद्दारी कर देश से मेरे - कायर दुश्मन को कविता से करारा जवाब

सीमा पर मुस्तैद पहरी, कण-कण में प्रताप-गोविंद

**कवयित्री - अनामिका गुप्ता - राष्ट्रभक्ति कविता**

देशभक्ति जब कविता बनकर सामने आती है, तो वह सिर्फ शब्द नहीं रहती, वह संकल्प बन जाती है। कवयित्री अनामिका गुप्ता की यह कविता ऐसे ही संकल्प की आवाज़ है - दुश्मन की कायरता पर प्रहार, सीमा के प्रहरियों पर गर्व, और गद्दारी करने वालों को खुली चेतावनी।

इस कविता को समाचार पत्र में मूल रूप में प्रकाशित किया जा रहा है। इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है, ताकि कवयित्री की भावना जैसी है, वैसी ही पाठकों तक पहुंचे।

**मुख्य तथ्य - एक नज़र में**

- कविता का नाम: गद्दारी कर देश से मेरे....
- कवयित्री: अनामिका गुप्ता
- विषय: राष्ट्रभक्ति, सीमा सुरक्षा, दुश्मन की कायरता, गद्दारी के विरुद्ध चेतावनी
- मुख्य भाव: वीरता, गर्व, चेतावनी, संकल्प
- संदर्भ: प्रताप और गोविंद - वीरता और बलिदान के प्रतीक

**कविता**

**> गद्दारी कर देश से मेरे**

> कायर है ये दुश्मन कितना
> पीछे से वार चलाता है
> गोला बारूद से खेलें जो
> उनहे गोलियों से डराता है
>
> सीमा पर मुसतैद हैं पहरी
> सीमा की सीमा जानते हैं
> जो तोडें सीमा की सीमा
> उनहे सबक सिखाकर मानते हैं
> गद्दारी कर देश से मेरे
> कया जिंदा तुम बच पाओगे
> प्रताप गोविंद कंण कण मे बसते
> बाल न बांका कर पाओगे

**> - अनामिका गुप्ता**

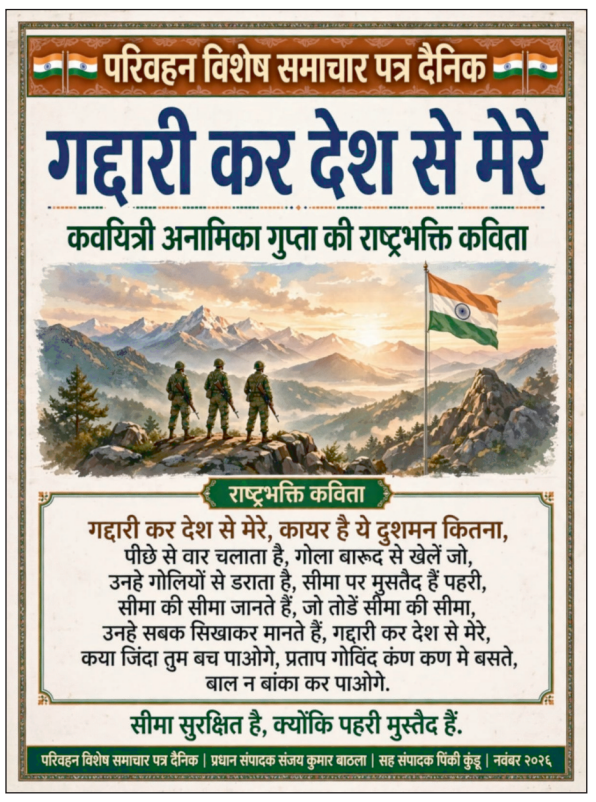
**1. पहला बंध - दुश्मन की कायरता पर प्रहार**

> कायर है ये दुशमन कितना
> पीछे से वार चलाता है
> गोला बारूद से खेलें जो
> उनहे गोलियों से डराता है

**विश्लेषण:** कवयित्री का पहला वार ही दुश्मन के चरित्र पर है।

दुश्मन सामने से नहीं लड़ता, पीछे से वार करता है - यही कायरता की पहचान है। जो सैनिक गोला-बारूद से खेलते हैं, जो मौत को रोज सामने देखते हैं, उन्हें गोलियों से डराने की कोशिश करना ही मूर्खता है।

**संदेश:** भारत का सैनिक डरता नहीं, डराता है।




२. दूसरा बंध - सीमा के प्रहरियों पर गर्व

> सीमा पर मुसतैद हैं पहरी
> सीमा की सीमा जानते हैं
> जो तोडें सीमा की सीमा
> उनहे सबक सिखाकर मानते हैं

**विश्लेषण:** यह बंध सीमा पर तैनात हमारे जवानों को सलाम है।

पहरी सिर्फ सीमा पर खड़े नहीं हैं, वे सीमा की मर्यादा जानते हैं। वे जानते हैं कब रुकना है, कब जवाब देना है, और कब सबक सिखाना है।

जो सीमा की सीमा तोड़ेगा, उसे सबक सिखाकर ही माना जाएगा - यह सिर्फ कविता नहीं, भारत की नीति भी है।

**संदेश:** सीमा सुरक्षित है, क्योंकि पहरी मुस्तैद हैं।

**3. तीसरा बंध - गद्दारों को खुली चेतावनी**

> गद्दारी कर देश से मेरे
> कया जिंदा तुम बच पाओगे
> प्रताप गोविंद कंण कण मे बसते
> बाल न बांका कर पाओगे

**विश्लेषण:** कविता का सबसे ताकतवर बंध यही है।

गद्दारी सिर्फ दुश्मन नहीं करता, कभी-कभी देश के अंदर से भी होती है। कवयित्री उन्हें चेतावनी देती हैं - देश से गद्दारी करके क्या तुम जिंदा बच पाओगे?

प्रताप और गोविंद यहां सिर्फ दो नाम नहीं हैं। महाराणा प्रताप और गुरु गोविंद सिंह - वीरता, त्याग और बलिदान के प्रतीक। कवयित्री कहती हैं, वे इस देश के कण-कण में बसते हैं।

जब तक इस मिट्टी में प्रताप और गोविंद का संस्कार है, तब तक देश का बाल भी बांका नहीं हो सकता।

**संदेश:** गद्दारों के लिए इस मिट्टी में कोई जगह नहीं है।

4. कविता की भाषा और शैली - क्यों दिल को छूती है?

- सरल भाषा: कोई कठिन शब्द नहीं, सीधी बात दिल तक पहुंचती है
- लय और प्रवाह: हर पंक्ति में जोश है, पढ़ते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं
- तीन भावों का संगम: कायरता पर क्रोध, जवानों पर गर्व, गद्दारों को चेतावनी
- इतिहास से जुड़ाव: प्रताप-गोविंद का नाम लेकर कविता को इतिहास की ताकत मिलती है

यह कविता मंच पर, स्कूल में, देशभक्ति कार्यक्रम में, सोशल मीडिया पर - हर जगह पढ़ी जाने योग्य है।

**संपादकीय निष्कर्ष** अनामिका गुप्ता की यह कविता हमें याद दिलाती है -

> दुश्मन कायर हो सकता है, लेकिन हमारा सैनिक नहीं।
> गद्दार छिप सकता है, लेकिन देश की मिट्टी उसे पहचान लेती है।

गद्दारी कर देश से मेरे.... - यह सिर्फ एक कविता का शीर्षक नहीं है, यह एक सवाल है, एक चेतावनी है, और एक संकल्प है।

**संपादकीय विभाग** की ओर से कवयित्री अनामिका गुप्ता को साधुवाद - ऐसी ही रचनाएं देश की आत्मा को जगाती रहें।

**परिवहन विशेष समाचार पत्र दैनिक | प्रधान संपादक संजय कुमार बाठला | सह संपादक पिंकी कुंडू**

# डॉलर की ताकत सोने से शुरू हुई, तेल से बची - Bretton Woods से Nixon Shock तक की सत्यापित कहानी

## 35 डॉलर सोना, SWIFT अमेरिका का नहीं, UPI और SWIFT अलग-अलग, सद्दाम वाला कारण सिद्ध नहीं

**लेखक : संजय कुमार बाठला**

**> संपादकीय स्पष्टीकरण:** यह लेख केवल सत्यापित तथ्यों पर आधारित है। जो दावा सत्यापित नहीं हुआ, उसे इसमें शामिल नहीं किया गया है। अनुमान को अनुमान और सहसंबंध को सहसंबंध ही लिखा गया है।

**मुख्य तथ्य - एक नज़र में**

- जुलाई 1944, Bretton Woods: 44 देशों ने तय किया - डॉलर सोने से जुड़ा, बाकी मुद्राएं डॉलर से
- दर: 1 औंस सोना = 35 डॉलर, डॉलर ही सोने में बदलने योग्य
- अमेरिका का सोना: 1949 में शिखर पर लगभग 21,900 टन, दुनिया के आधिकारिक सोने का लगभग तीन-चौथाई
- 15 अगस्त 1971: निक्सन ने डॉलर की सोने में परिवर्तनीयता समाप्त की - Nixon Shock
- 1974: अमेरिका-सऊदी अनौपचारिक व्यवस्था - तेल डॉलर में, कमाई अमेरिकी बॉन्ड में, कोई औपचारिक संधि का मेमो नहीं मिला
- 1961-1968: लंदन गोल्ड पूल, 8 केंद्रीय बैंक, मार्च 1968 में टूटा, दो-स्तरीय बाजार बना
- 1973: SWIFT बेल्जियम में बना, 15 देशों के 239 बैंकों की को-ऑपरेटिव
- 2000-2003: इराक ने तेल यूरो में करने की घोषणा की, 2003 में युद्ध हुआ, बाद में तेल फिर डॉलर में - कारण सिद्ध नहीं
- UPI बनाम SWIFT: UPI रिटेल पेमेंट, SWIFT बैंकों के बीच बड़े ट्रांसफर का मैसेजिंग सिस्टम - दोनों अलग

1. 1944 - Bretton Woods में दुनिया ने डॉलर को क्यों चुना? जुलाई 1944 में, जब दूसरा विश्वयुद्ध चल ही रहा था, 44 देशों के प्रतिनिधि अमेरिका के Bretton Woods में मिले।

उन्हें युद्ध के बाद की दुनिया के लिए एक नई मुद्रा व्यवस्था बनानी थी।

**फैसला यही हुआ:**

- हर देश की मुद्रा डॉलर से जुड़ेगी, एक निश्चित दर पर
- डॉलर सोने से जुड़ेगा - 1 औंस सोना = 35 डॉलर
- विदेशी केंद्रीय बैंक अपने डॉलर को अमेरिका से सोने में बदल सकते थे

**मतलब:** डॉलर दुनिया की मुद्राओं का केंद्र बन गया। डॉलर पर भरोसा इसलिए था क्योंकि अमेरिका के पास सबसे ज्यादा सोना था।

इसी सम्मेलन में IMF और विश्व बैंक जैसी संस्थाएं भी बनीं।

यह सत्यापित है - इसमें कोई विवाद नहीं।

2. अमेरिका के पास कितना सोना था? - 20,000 टन वाला सच अक्सर कहा जाता है - अमेरिका के पास तब 20,000 टन सोना था।

**सत्यापित तथ्य यह है:**

- अमेरिका का सोना 1949 में शिखर पर लगभग 21,900 टन था
- यह दुनिया के आधिकारिक सोने का लगभग तीन-चौथाई था
- 1930-40 के दशक में यूरोप से सोना अमेरिका आया, युद्ध के सामान और हथियारों के भुगतान में

इसलिए लेख में हम 1944 में ठीक 20,000 टन नहीं लिख रहे। सही लिखना होगा - 1949 में शिखर पर लगभग 21,900 टन।

यही सोना Bretton Woods की ताकत था। लेकिन यही सोना बाद में कमजोरी भी बना, क्योंकि दुनिया के पास डॉलर बढ़ते गए, सोना घटता गया।

3. 15 अगस्त 1971 - Nixon Shock, जब डॉलर सोने से अलग हुआ 15 अगस्त 1971 को राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने एक बड़ा फैसला लिया।

उन्होंने डॉलर की सोने में सीधी परिवर्तनीयता को निलंबित कर दिया। इसे ही Nixon Shock कहते हैं।

क्यों?

- अमेरिका पर महंगाई का दबाव था
- विदेशी सरकारें तेजी से अपने डॉलर को सोने में बदल रही थीं
- 35 डॉलर वाला भाव अब बाजार से मेल नहीं खा रहा था

निक्सन ने कहा था कि यह अस्थायी है, लेकिन यह कभी वापस नहीं आया। 1973 तक दुनिया की बड़ी मुद्राएं तैरने वाली दर (Floating Rate) पर आ गईं।

अब डॉलर सोने से नहीं, अमेरिका की अर्थव्यवस्था, भरोसे और ताकत से चलता है।

**4. 1961-1968 - लंदन गोल्ड पूल, जब 35 डॉलर को बचाने की कोशिश हुई 1960 वाला दावा अक्सर गलत तिथि के साथ बताया जाता है।**

**सत्यापित तथ्य:**

- 1 नवंबर 1961 को लंदन गोल्ड पूल बना
- 8 केंद्रीय बैंक - अमेरिका समेत अमेरिका, ब्रिटेन, पश्चिम जर्मनी, फ्रांस, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड
- काम था - लंदन के बाजार में सोना बेचकर भाव को 35 डॉलर प्रति औंस पर रोकना
- अमेरिका ने इसके लिए 50% सोना दिया
- 1968 में पूल टूट गया।
- मार्च 1968 में सोने पर भारी दबाव आया, फ्रांस पूल से अलग हुआ
- लंदन का बाजार बंद करना पड़ा
- इसके बाद दो-स्तरीय बाजार बना - सरकारी लेनदेन में 35 डॉलर, बाजार में अलग भाव

**मतलब:** सरकारें सोने का भाव अब बाजार से नहीं रोक सकती थीं। Nixon Shock की जमीन यहीं तैयार हुई।

5. पेट्रो-डॉलर - 1974 की व्यवस्था, संधि नहीं निक्सन के बाद सवाल था - अब डॉलर की मांग कैसे बनी रहेगी? जवाब तेल में मिला।

**सत्यापित तथ्य:**

- 1973 में योम किप्पुर युद्ध और तेल प्रतिबंध के बाद अमेरिका-सऊदी संबंध टूटने के कगार पर थे
- 1974 में अमेरिकी वित्त मंत्री बिल साइमन और विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर ने सऊदी से बात की
- जून 1974 में अमेरिका-सऊदी के बीच व्यापक सैन्य-आर्थिक सहयोग समझौता हुआ
- व्यवस्था यह बनी - सऊदी तेल डॉलर में बेचेंगे, कमाई को अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड जैसे सुरक्षित साधनों में लगाएंगे, अमेरिका आर्थिक-सैन्य सहयोग देगा

**महत्वपूर्ण सुधार:** इसे औपचारिक पेट्रो-डॉलर संधि कहना सही नहीं है। इस वादे का कोई आधिकारिक मेमो नहीं मिला है। इसे अनौपचारिक व्यवस्था कहना ज्यादा सही है।

**लेकिन प्रभाव सच था:**

- दुनिया को तेल चाहिए, तेल के लिए डॉलर चाहिए, इसलिए डॉलर की मांग बनी रही
- तेल बेचने वाले देशों का पैसा फिर अमेरिकी बॉन्ड में आया, अमेरिका की उधारी सस्ती रही

6. SWIFT - अमेरिका का नहीं, बेल्जियम का है सबसे ज्यादा फैलाया गया भ्रम यही है - SWIFT को अमेरिका ने बनाया।

**सत्यापित तथ्य:**

- SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication
- 1973 में बेल्जियम में बना, 15 देशों के 239 बैंकों ने बनाया
- यह सदस्य-स्वामित्व वाली को-ऑपरेटिव है, मुख्यालय बेल्जियम में है
- 200 से ज्यादा देशों में 11,000 से ज्यादा वित्तीय संस्थाएं इससे जुड़ी हैं

**SWIFT क्या करता है?**

- यह पैसा नहीं भेजता, यह संदेश भेजता है
- एक बैंक दूसरे बैंक को बताता है - पैसा भेजना है
- पैसा बैंकों के खातों से जाता है, SWIFT से नहीं

**अमेरिका का दबदबा क्यों है?**

- डॉलर की वजह से, SWIFT के मालिक होने की वजह से नहीं
- दुनिया का बड़ा व्यापार डॉलर में होता है, इसलिए डॉलर वाले संदेश ज्यादा होते हैं

**7. सद्दाम और यूरो - घटना सही, कारण सिद्ध नहीं - सत्यापित घटना:**

- 2000 में इराक ने UN Oil-for-Food कार्यक्रम के तहत तेल डॉलर से यूरो में करने की घोषणा की
- 2003 में अमेरिका के नेतृत्व में इराक पर आक्रमण हुआ, सद्दाम की सत्ता गई
- बाद में इराक का तेल फिर डॉलर में होने लगा

**सत्यापित नहीं - कारण:**

- क्या यूरो वाला फैसला ही युद्ध का कारण था? इसका कोई ठोस सबूत प्राप्त नहीं है
- इतिहासकारों के अनुसार युद्ध के पीछे कई कारण बताए जाते हैं - WMD का आरोप, कुवैत, क्षेत्रीय राजनीति, सुरक्षा

**संपादकीय नियम:** सहसंबंध को कारण नहीं कह सकते। दो घटनाएं एक के बाद हुईं, इसका मतलब यह नहीं कि पहली ने दूसरी को पैदा किया इसलिए हम लिख रहे हैं - सहसंबंध है, कारण सिद्ध नहीं है।

**8. UPI बनाम SWIFT - साइकिल और हवाई जहाज की तुलना मत कीजिए - सत्यापित तथ्य:**

**UPI -**

- भारत की रिटेल पेमेंट प्रणाली, NPCI द्वारा संचालित, 2016 में शुरू
- व्यक्ति से दुकानदार तक, सेकंड में, रुपये में, बैंक खाते से बैंक खाते में
- अब कई देशों में विस्तार हो रहा है, ले

# किंजरकेला में फल-फूल रही गांजे की अवैध खेती, आबकारी विभाग की खामोशी पर उठे गंभीर सवाल





विभाग की नाक के नीचे चल रहा कथित अवैध कारोबार, वर्षों से कार्रवाई का इंतजार; आखिर किसके संरक्षण में पनप रहा है नशे का यह कारोबार?

रिपोर्ट डा राजकुमार यादव परिवहन विशेष समाचार पत्र दैनिक सुंदरगढ़

जिले के किंजरकेला क्षेत्र में कथित तौर पर गांजे की अवैध खेती का मामला एक बार फिर सरकारी निगरानी व्यवस्था और आबकारी विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। क्षेत्र में बड़े पैमाने पर गांजे की खेती होने की खबरें सामने आने के बावजूद संबंधित विभाग की निष्क्रियता समझ से परे है। आखिर विभाग की नजरों के सामने इस तरह की गतिविधियां कैसे संचालित हो रही हैं और अब तक इन पर प्रभावी कार्रवाई क्यों नहीं हुई?

सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि गांजे की खेती कोई रातोंरात होने वाली गतिविधि नहीं है। इसके लिए जमीन तैयार करने, पौधों की देखभाल करने और फसल को विकसित करने में लंबा समय लगता है। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि नियमित निगरानी और क्षेत्रीय सूचना तंत्र होने के बावजूद आबकारी विभाग को इसकी भनक क्यों नहीं लगी? यदि जानकारी थी तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई और यदि जानकारी नहीं थी तो विभाग की निगरानी व्यवस्था किस काम की है?

नशे का अवैध कारोबार केवल कानून व्यवस्था का विषय नहीं, बल्कि समाज की युवा पीढ़ी के भविष्य से जुड़ा गंभीर संकट है। गांजे की खेती से लेकर उसकी आपूर्ति और संभावित बिक्री तक एक पूरा नेटवर्क सक्रिय होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में केवल छोटे स्तर पर कार्रवाई या औपचारिक छापेमारी पर्याप्त नहीं होगी।

अफसोसजनक स्थिति यह है कि लंबे समय से इस तरह की गतिविधियों पर आबकारी विभाग की ओर से कोई ऐसी निर्णायक और प्रभावी कार्रवाई सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आई है, जो अवैध कारोबारियों में कानून का भय पैदा कर सके। विभाग की यह चुप्पी कई सवालों को जन्म देती है। क्या क्षेत्र में नियमित निरीक्षण होता है? क्या जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की गई है? क्या खेती के वास्तविक संचालकों और इसके पीछे सक्रिय नेटवर्क की पहचान की गई है?

अब जिला प्रशासन, पुलिस और आबकारी विभाग को संयुक्त अभियान चलाकर खेती वाले स्थानों की पहचान, फसल की जब्ती, कानूनी कार्रवाई तथा पूरे नेटवर्क की जांच करनी चाहिए। साथ ही संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए।

आखिर सवाल यही है कि जब नशे की खेती जमीन पर दिखाई दे रही है, तो आबकारी विभाग की कार्रवाई फाइलों तक ही क्यों सीमित है?

# गरीबों के आशियानों पर चला प्रशासन का बुलडोजर, बड़े अतिक्रमणों पर खामोशी क्यों?

## जेएसडब्ल्यू चौक में मकान तोड़े जाने से कोईड़ा अंचल में आक्रोश; ठंड के मौसम में बेघर हुए परिवारों के पुनर्वास की व्यवस्था नहीं होने पर उठे सवाल

रिपोर्ट डा राजकुमार यादव परिवहन विशेष समाचार पत्र में कोईड़ा

अतिक्रमण हटाने की प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर एक बार फिर गरीबों और प्रभावशाली लोगों के बीच कानून के कथित दोहरे मापदंड पर सवाल उठने लगे हैं। जेएसडब्ल्यू चौक क्षेत्र में कुछ मकानों को तोड़ने के लिए प्रशासन का दल-बल के साथ पहुंचना और बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के गरीब परिवारों के आशियाने उजाड़ देना स्थानीय स्तर पर नाराजगी का कारण बन गया है। इस कार्रवाई के बाद पूरे कोईड़ा अंचल में असंतोष का माहौल देखा जा रहा है।

स्थानीय लोगों के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि सड़क और सार्वजनिक जमीन से अतिक्रमण हटाना प्रशासन की प्राथमिकता है, तो यह नियम सभी पर समान रूप से लागू क्यों नहीं होता? क्षेत्र में ऐसे बड़े-बड़े भवन भी मौजूद होने के आरोप हैं, जिनका निर्माण सड़क की निर्धारित सीमा तक पहुंच चुका है अथवा जिन्होंने सड़क पर अतिक्रमण कर रखा है। कई ऊंची इमारतों के स्वीकृत नक्शे, भवन निर्माण की अनुमति और निर्धारित मानकों के अनुपालन की निष्पक्ष जांच की मांग भी उठ रही है।

विडंबना यह है कि गरीब परिवारों के छोटे-छोटे घरों पर कार्रवाई करने में प्रशासनिक तत्परता दिखाई देती है, लेकिन प्रभावशाली भवन मालिकों के कथित अतिक्रमणों पर वैसी ही सक्रियता नजर नहीं आती।



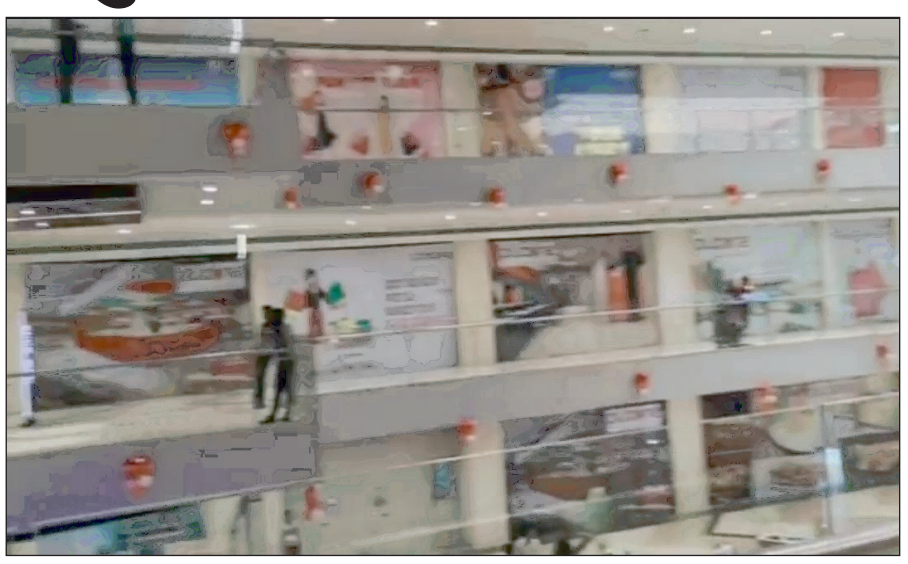

हालांकि, प्रशासन की कार्रवाई के पीछे वैधानिक आधार और संबंधित भूमि की स्थिति की जांच भी आवश्यक है।

सबसे संवेदनशील पहलू यह है कि ठंड के मौसम में जिन परिवारों के सिर से छत छीन ली गई, उनके रहने, खाने और पुनर्वास की कोई वैकल्पिक व्यवस्था किए जाने की जानकारी सामने नहीं आई है। अतिक्रमण हटाना प्रशासनिक दायित्व हो सकता है, लेकिन मानवीय संवेदनशीलता और प्रभावित परिवारों के प्रति जिम्मेदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है।

सरकार और प्रशासन से अपेक्षा है कि अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई निष्पक्ष, पारदर्शी और समान हो। गरीबों के घर तोड़ने से पहले पुनर्वास और मानवीय सुरक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। विकास और व्यवस्था के नाम पर किसी गरीब का आशियाना उजाड़ना आसान है, लेकिन न्यायपूर्ण प्रशासन वही है जो कानून के साथ इंसानियत का भी सम्मान करे।

## प्लूटो प्लाजा पर ईडी का शिकंजा, 24.60 करोड़ की संपत्ति कुर्क

# पीएसयू के ऋण में कथित हेराफेरी से मॉल तक पहुंची जांच की आंच, हनुमान खेदारिया से जुड़ी कंपनियां जांच के घेरे में



रिपोर्ट डा राजकुमार यादव परिवहन विशेष समाचार पत्र राउरकेला

औद्योगिक नगरी राउरकेला के प्रमुख व्यावसायिक केंद्रों में शुमार प्लूटो प्लाजा (प्लूटोन मॉल) अब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की बड़ी कार्रवाई को लेकर सुर्खियों में है। करोड़ों के कारोबार और व्यावसायिक गतिविधियों के बीच इस प्रतिष्ठान के एक बड़े हिस्से पर केंद्रीय जांच एजेंसी का शिकंजा कसना शहर के कारोबारी जगत में चर्चा का विषय बन गया है। ईडी के भुवनेश्वर जोनल कार्यालय ने धनशोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत लगभग 24.60 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क की है।

ईडी की आधिकारिक जानकारी के अनुसार, छेंड स्थित प्लूटो प्लाजा के ग्राउंड फ्लोर, प्रथम तल और द्वितीय तल के एक हिस्से को इस कार्रवाई में शामिल किया गया है। संबंधित संपत्ति प्लूटो प्लाजा प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर है, जिसे हनुमान खेदारिया नियंत्रित करते हैं।

सरकारी उपक्रम के ऋण से शुरू हुई जांच इस पूरे मामले की जड़ में भारत सरकार के उपक्रम पीईसी लिमिटेड (PEC) से जुड़ा कथित ऋण घोटाला है। ईडी के मुताबिक, कलुंगा स्थित मां तारिणी इंडस्ट्रीज लिमिटेड (MTIL) ने लौह अयस्क खरीद के नाम पर कथित तौर पर 19.40 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता हासिल की। आरोप है कि कंपनी ने अपनी वास्तविक वित्तीय स्थिति और संपत्तियों पर पहले से मौजूद देनदारियों को छिपाया। वहीं, संबंधित कंपनी तथागत एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने भी 16 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्राप्त की थी।

दोनों कंपनियों पर ब्याज सहित लगभग 56.89 करोड़ रुपये की देनदारी एनपीए (NPA) में तब्दील हो गई। ईडी की जांच में कथित तौर पर सामने आया कि ऋण की राशि को कंपनियों के बैंक खातों के माध्यम से दूसरे उद्देश्यों में स्थानांतरित किया गया और मां तारिणी इंडस्ट्रीज के पूर्व शेयरधारकों को भुगतान किया गया। इनमें हनुमान खेदारिया भी शामिल बताए गए हैं।

15.31 करोड़ का लेनदेन, मूल्यांकन 24.60 करोड़ जांच एजेंसी के अनुसार, खेदारिया और उनसे जुड़ी संस्थाओं तक करीब 15.31 करोड़ रुपये पहुंचे, जिसका आनुपातिक ब्याज जोड़कर मूल्य 24.60 करोड़ रुपये आंका गया। इसी राशि के बराबर संपत्ति को अपराध से अर्जित आय के समतुल्य मानते हुए कुर्क किया गया है।

मामले की शुरुआत सीबीआई की भुवनेश्वर एसीबी शाखा द्वारा दर्ज प्राथमिकी से हुई, जिसके आधार पर ईडी ने धनशोधन की जांच आगे बढ़ाई।

अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम से निकली ऋण राशि का वास्तविक उपयोग कहां हुआ और इस पूरे वित्तीय नेटवर्क में किन-किन लोगों तथा संस्थाओं की भूमिका रही? फिलहाल जांच जारी है। यह अनंतिम कुर्की है, दोषसिद्धि नहीं; अंतिम कानूनी निष्कर्ष जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही सामने आएगा।

राउरकेला के लिए यह मामला केवल एक मॉल की संपत्ति कुर्क होने की खबर नहीं, बल्कि सार्वजनिक धन, वित्तीय जवाबदेही और कारोबारी पारदर्शिता से जुड़े गंभीर सवालों की दस्तक भी है।

# संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ लोगों को उकसा तो आप रहे हैं, मोदी जी !

(आलेख : राजेंद्र शर्मा)

"एक और बात याद रखना, नक्सली खत्म हुए हैं, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। जंगलों में हथियारी नक्सली तो मिट गए, लेकिन दिमागी नक्सलियों ने कई संगठनों पर कब्जा कर रखा है। वे आज भी देश के संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ लोगों को उकसा रहे हैं। कई राजनीतिक दलों में, अलग-अलग संगठनों में भी इन दिमागी नक्सलियों ने अपनी घुसपैठ कर ली है। हमें इन्हें पहचानना है। इन्हें परास्त करना है। और देश को सुरक्षित करना है।"

ये शब्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हैं, इस पर शायद ही किसी को हैरानी होगी। लेकिन, इस पर बहुतों को हैरानी हो सकती है, हालांकि पिछले कई साल के अनुभव को देखते हुए इस पर भी हैरानी होनी नहीं चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी, कथित दिमागी नक्सलियों को पहचानने और परास्त करने का यह आह्वान, दीपावली के जश्न के दौरान कर रहे थे। इस पर शायद और भी ज्यादा लोगों को हैरानी होगी कि प्रधानमंत्री मोदी यह आह्वान, अपनी पार्टी की किसी राजनीतिक सभा में जुटे कार्यकर्ताओं से नहीं, बल्कि केंद्रीय सुरक्षा बलों (सीआरपीएफ) की कतारों से कर रहे थे, जिनके साथ खासतौर पर दिवाली मनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे।

सरकारी और गैर-सरकारी, हर साधन से अति-प्रचार के जरिए यह तो अब तक करीब-करीब सभी को बताया ही जा चुका है कि प्रधानमंत्री मोदी, दिवाली का त्यौहार सामान्य लोगों की तरह घर पर या संबंधियों-मित्रों के साथ न मनाकर, किसी न किसी मोर्चे पर जाकर वहां तैनात सैनिकों तथा अफसरों के साथ मनाते हैं, जिससे उनकी त्यौहार पर घर से दूर होने की पीड़ा को कम कर सकें। यह भी अब तक सभी जान ही चुके हैं कि अपने से पहले के सभी प्रधानमंत्रियों से भिन्न, नरेंद्र मोदी ऐसे हरेक मौके पर सैन्य अधिकारियों की पोशाक में सज कर पहुंचते हैं, ताकि वर्दी में तैनात जवानों को उनके बीच से ही होने का एहसास करा सकें।

यह दूसरी बात है कि पोशाक की समानता का यह शाही दिखावा भी तुरंत ही तभी खुल जाता है, जब प्रधानमंत्री मोदी अपने हिसाब से इन फौजियों का त्यौहार मनवाने के लिए, अपने हैलीकोप्टर से उतरते हैं। हां! इस दिवाली पर जो हुआ, वह खुद मोदी के अब तक के शाही शान-शौकत के प्रदर्शनों से भी, बहुत आगे का मामला था। इस बार, अपने साथ दिवाली मनाने पहुंचे मोदी के स्वागत-सत्कार के लिए, सीआरपीएफ को अपने महिलाकर्मियों की एक पूरी नर्तक पलटन तैयार करनी पड़ी थी, जिसने प्रधानमंत्री के गिर्द घेरा बनाकर, समूह नृत्य के जरिए प्रधानमंत्री का स्वागत किया था। बहुतों को पूरा दृश्य ही राजशाही की याद दिलाने वाला लगा, तो इसमें अचरज की बात नहीं होनी चाहिए।

फिर भी, प्रधानमंत्री मोदी के त्यौहार मनाने के लिए सीमाओं पर तैनात जवानों के बीच पहुंचने की उदारता के बखान के तूमार से अक्सर यह दबा ही दिया जाता है कि त्यौहार मनाने के नाम पर, देश की सीमाओं के रक्षकों के बीच पहुंचकर, प्रधानमंत्री मोदी वास्तव में करते और करते क्या हैं? उन्हें अपना भक्त बनाने के अलावा क्या करने के लिए उत्प्रेरित और उत्साहित करते हैं? बेशक, ऐसे मौके पर कोई भी प्रमुख नेता, वर्दीधारी जवानों के त्याग तथा बलिदान की सराहना कर, उनका मनोबल बढ़ाने का काम करेगा। और देश के सामने उपस्थित चुनौतियों को रेखांकित करते हुए, उनका मुकाबला करने के लिए प्रयासों को केंद्रित करने का आह्वान भी करेगा। लेकिन, इस सबसे भिन्न रूप से सरकारी और दलगत आयोजनों के अंतर को एक प्रकार से मिटा ही देने वाले प्रधानमंत्री मोदी ने, रक्षाबलों से अपने संबोधनों में अपने शासन की महत्ता के बखान को, अपने से पहले की सरकारों तथा अपने राजनीतिक विरोधियों पर हमले करने का, बार-बार मौका बनाया है।

लेकिन, इस बार मोदी ने बस्तर में सीआरपीएफ/ कोबरा बलों से अपने संबोधन में, अपनी शुद्ध राजनीतिक मैसेजिंग को जिस खतरनाक स्तर पर पहुंचा दिया है, वह खुद नरेंद्र मोदी के पैमाने से अभूतपूर्व है।

बेशक, कोई कह सकता है कि इस बार दिवाली पर प्रधानमंत्री मोदी चूंकि छत्तीसगढ़ में बस्तर में तैनात रक्षा बलों के बीच पहुंचे थे और बस्तर में इन रक्षा बलों का मुख्य काम माओवाद की चुनौती का सामना करना करना रहा था, इसलिए उनके दिवाली संबोधन का फोकस माओवाद का मुकाबला करने में इन बलों की सफलता पर उन्हें शाबाशी देने पर होना स्वाभाविक था। लेकिन, प्रधानमंत्री के संबोधन का जो हिस्सा हमने शुरू में ही उद्धृत किया है, उस पर एक नजर डालने से ही स्पष्ट हो जाता है कि यह माओवाद का मुकाबला करने पर फोकस होने का मामला तो है ही नहीं। उल्टे हाथ की सफाई दिखाते हुए प्रधानमंत्री मोदी, सोचे-समझे तरीके से माओवाद को विपक्ष मात्र के साथ मिला देते हैं, ताकि विपक्ष के खिलाफ अपने दमनकारी तौर-तरीकों का सहारा लेने को सही ठहरा सकें। ऐसा नरेंद्र मोदी, माओवाद और नक्सलवाद को जबरन




समानार्थी बनाने के अलावा, दो-तीन चरणों में करते हैं।

पहले वह, 'हथियारी नक्सल' और कथित "दिमागी नक्सल" से मिला देते हैं, जो इस अर्थ में एक लंबी छलांग है कि कथित हथियारी नक्सलों के हथियारों से राज्य की सत्ता को चुनौती देने से भिन्न, अगर कोई कथित दिमागी नक्सल वर्तमान सत्ता को वैचारिक चुनौती देता भी है, भारत का संविधान उसे ऐसा करने की पूरी स्वतंत्रता देता है। मूलत: इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने पुरानी राजद्रोह की धारा को एक प्रकार से अवैधानिक करार देते हुए, उसके तहत हर प्रकार के मामलों पर रोक भी लगा दी थी। यह दूसरी बात है कि मोदी की हुकूमत के नये फौजदारी कानूनों में, नाम बदलकर और पहले से भी ज्यादा स्वतंत्रताहारी तरीके से, उक्त राजद्रोह कानून को वापस ले आया गया है और संवैधानिक अदालत इसकी समीक्षा करने के लिए समय ही नहीं निकाल पायी है।

दूसरी बड़ी छलांग में नरेंद्र मोदी, यह दावा करने के जरिए कि "दिमागी नक्सलियों ने कई संगठनों पर कब्जा कर रखा है... कई राजनीतिक दलों में, अलग-अलग संगठनों में भी इन दिमागी नक्सलियों ने अपनी घुसपैठ कर ली है" आदि, अपने राजनीतिक विरोधियों से लेकर, तरह-तरह के सामाजिक व अन्य संगठनों तक, अपने शासन के सभी आलोचकों को "दिमागी नक्सली" करार दे देते हैं।

और तीसरी छलांग में प्रधानमंत्री मोदी यह दावा करने के जरिए कि "वे" यानी कथित 'दिमागी नक्सल' "आज भी देश के संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ लोगों को उकसा रहे हैं", अपने निजाम के खिलाफ जनता के विभिन्न हिस्सों के बढ़ते आंदोलनों को और खासतौर पर चुनावी व्यवस्था की विश्वसनीयता के ही सवाल पर, चुनाव आयोग की एसआइआर की प्रक्रिया को रद्द करने तथा मतदाता सूचियों के शुद्धीकरण के नाम पर हुई सरासर सत्तापक्ष-समर्थक मनमानी के लिए जिम्मेदार, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर, देश भर में बढ़ते जन-आंदोलन को ही, माओवादी का लेबल लगाकर बदनाम करने की कोशिश करते हैं।

लेकिन, प्रधानमंत्री मोदी यह सब कम से कम इस 15 अगस्त से तो करते ही आ रहे हैं, जब लाल किले से अपने स्वतंत्रता दिवस संबोधन में उन्होंने कथित "दिमागी नक्सलों" का मुकाबला करने का आह्वान किया था। जून-जुलाई में पेपर लीक के मुद्दे से शुरू कर के उठे खासतौर पर छात्रों व अन्य युवाओं के अभूतपूर्व आंदोलन की पृष्ठभूमि में प्रधानमंत्री द्वारा उक्त जुमला गढ़े जाने से यह स्वत:स्पष्ट था कि यह पूरी कसरत, मोदी राज की विफलताओं पर जनता के बढ़ते असंतोष को नक्सलवाद का नाम देकर, उसे कुचलने का रास्ता आसान बनाने की है। स्वाभाविक रूप से अब उसी हथियार को इस समय जारी चुनाव प्रक्रिया की शुचिता सुनिश्चित करने के लिए जारी व्यापक आंदोलन तक फैला दिया गया है, जिसमें भी युवा पीढ़ी की अत्यंत महत्वपूर्ण उपस्थिति देखी जा सकती है।

जाहिर है कि मोदीशाही से इस विडंबना को देखने की उम्मीद तो कोई नहीं कर सकता है कि कथित "हथियारी नक्सलों" के नाम से जोड़कर, ऐसे जन-आंदोलनों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, जिनकी एक महत्वपूर्ण पहचान इनका पूरी तरह से शांतिपूर्ण तथा संविधान के दायरे में होना है। लेकिन, मोदी राज को तो जैसे जनता के शांतिपूर्ण आंदोलनों को बदनाम कर के, उनके दमन का रास्ता सुगम बनाने में महारत ही हासिल है। पहले, सीएए-विरोधी आंदोलन को पूर्णत: शांतिपूर्ण तथा संवैधानिक होने के बावजूद, "इस्लामवादी" करार देकर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि की भाजपायी राज्य सरकारों द्वारा बर्बर दमन के जरिए कुचलने की कोशिश की गयी और अंतत: दिल्ली में सांप्रदायिक दंगा थोप कर दबा ही नहीं दिया गया, बल्कि इस आंदोलन से जुड़ी कई पुरअसर युवा आवाजों को दंगे के 'वृहत्तर षडयंत्र केस' के नाम पर, बरसों के लिए जेलों में ठूंस दिया गया। इससे पहले, यही खेल भीमा-कोरेगांव षडयंत्र केस के नाम पर खेला गया था। इसके बाद, किसानों के ऐतिहासिक आंदोलन पर अलगाववादी, खालिस्तानपरस्त आदि के लेबल लगाकर, उसे भी कुचलने की कोशिश की गयी। और अब विशेष रूप से युवा-संचालित जन-आंदोलनों के खिलाफ, इसी काम के लिए "दिमागी नक्सल" का जुमला लाया गया है।

इसके बावजूद, मोदी का दीवाली आह्वान इस माने में अब तक के इन सभी उदाहरणों से ज्यादा खतरनाक है कि कथित दिमागी नक्सलों को 'पहचानने, उन्हें परास्त करने और इस तरह देश को सुरक्षित करने' का तकाजा, उन सुरक्षा बलों से किया जा रहा था, जो वैसे भी शासन के दमनकारी बाजू का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। वास्तव में इसका भी इशारा तो नरेंद्र मोदी के 15 अगस्त के भाषण में ही कर दिया गया था, जब प्रधानमंत्री ने आंतरिक चुनौतियों के संदर्भ में होम गाइर्स बल के, आमूल पुनर्गठन का एलान किया था। अब सीधे रक्षा बलों से विपक्ष के खिलाफ मैदान में उतरने का तकाजा किया जा रहा है। पर अपने विरोधियों के खिलाफ अपने गुंडाबलों के साथ-साथ, शासन के दमन तंत्र का अंधाधुंध इस्तेमाल करना तो, फासीवाद की एक प्रमुख विशेषता ही है, जिसकी एक झलक देश की राजधानी में अक्टूबर के जन-प्रदर्शनों में देखने को मिली भी है। और फासीवाद की ऐसी ही महत्वपूर्ण विशेषता है, इस तरह खुद "संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ लोगों को उकसाने" को उकसाते हुए भी, अपने विरोधियों पर ठीक यही करने का आरोप लगाना।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार और 'लोकलहर' के संपादक हैं।)

टेंपल आफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर अलाइड ट्रस्ट पंजीकृत
https://tolwa.com/about.html I
tolwaindia@gmail.com,
tolwadelhi@gmail.com



पिंकी कुंडू

# आज का साइबर सुरक्षा विचार: डिजिटल अरेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट सख्त: व्हाट्सएप, बैंकों और साइबर प्लेटफॉर्मों की जवाबदेही तय करने के निर्देश

भारत में तेजी से बढ़ रहे डिजिटल अरेस्ट घोटालों और साइबर वित्तीय अपराधों पर चिंता व्यक्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप तथा अन्य डिजिटल इंटरमीडियरी प्लेटफॉर्मों को ऐसे अपराधों की रोकथाम के लिए प्रस्तावित सुरक्षा उपायों का विस्तृत ब्योरा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि सभी प्रस्ताव भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) को भी उपलब्ध कराए जाएं ताकि साइबर धोखाधड़ी के विरुद्ध एक समन्वित एवं प्रभावी तंत्र विकसित किया जा सके।

यह निर्देश मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची एवं न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ द्वारा डिजिटल अरेस्ट मामलों से संबंधित स्वतः संज्ञान याचिका की सुनवाई के दौरान जारी किया गया। मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर को निर्धारित की गई है।

**डिजिटल अरेस्ट: एक उभरता हुआ साइबर खतरा**

डिजिटल अरेस्ट साइबर अपराध का ऐसा स्वरूप है जिसमें अपराधी स्वयं को पुलिस, सीबीआई, ईडी, कस्टम विभाग अथवा अन्य सरकारी एजेंसियों का अधिकारी बताकर व्यक्तियों को वीडियो कॉल या ऑनलाइन माध्यम से डराते-धमकाते हैं। फर्जी गिरफ्तारी वारंट, जांच नोटिस या अन्य जाली दस्तावेज दिखाकर पीड़ितों को विश्वास दिलाया जाता है कि वे किसी गंभीर अपराध में संलिप्त हैं। इसके बाद उन्हें जांच या सत्यापन के नाम पर बड़ी धनराशि विभिन्न बैंक खातों में स्थानांतरित करने के लिए मजबूर किया जाता है।

हाल के वर्षों में इस प्रकार की घटनाओं में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिससे लाखों रुपये की ठगी के अनेक मामले सामने आए हैं। इसी पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न संस्थाओं की जवाबदेही तय करने की प्रक्रिया शुरू की है।

**डिजिटल प्लेटफॉर्मों की भूमिका पर न्यायालय का जोर**

न्यायालय ने कहा कि व्हाट्सएप सहित डिजिटल मंचों को केवल शिकायत प्राप्त होने के बाद कार्रवाई करने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उन्हें अपनी तकनीकी क्षमताओं का उपयोग करते हुए ऐसे खातों और गतिविधियों की पहचान करने के लिए सक्रिय उपाय करने होंगे जो साइबर ठगी में प्रयुक्त हो रहे हैं।

सुनवाई के दौरान यह जानकारी दी गई कि व्हाट्सएप ने डिजिटल अरेस्ट और कानून प्रवर्तन एजेंसियों का प्रतिरूपण करने वाले लगभग 9,400 खातों के विरुद्ध कार्रवाई की है। कंपनी ने यह भी बताया कि वह ऐसे सॉफ़्टवेयर विकसित कर रही है जो संदिग्ध खातों की पहचान कर उपयोगकर्ताओं को समय रहते चेतावनी दे सके।

**बैंकों और वित्तीय संस्थानों की जवाबदेही**

सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट ठगी की रोकथाम में बैंकों और वित्तीय संस्थानों की भूमिका को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया। न्यायालय ने कहा कि यदि यह सिद्ध होता है कि किसी साइबर ठगी की घटना बैंक या वित्तीय संस्था द्वारा आवश्यक सावधानी न बरतने अथवा संदिग्ध लेन-देन पर समय रहते कार्रवाई न करने के कारण हुई है, तो पीड़ित को हुए नुकसान की भरपाई संबंधित संस्था द्वारा की जानी चाहिए।

पीठ ने जोर देकर कहा कि वित्तीय संस्थानों को ऐसे लेन-देन की पहचान करने में सक्षम होना चाहिए जो ग्राहक की




सामान्य बैंकिंग गतिविधियों से असामान्य रूप से भिन्न हों। यदि किसी ग्राहक के खाते से अचानक बड़ी राशि या संदिग्ध भुगतान किया जाता है, तो बैंक को चेतावनी, सत्यापन अथवा अस्थायी रोक जैसे उपाय करने चाहिए।

**आरबीआई से मजबूत नियामकीय व्यवस्था की अपेक्षा**

न्यायालय ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रस्तावित नियामकीय सुधारों पर भी विशेष ध्यान दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डिजिटल अरेस्ट और अन्य साइबर वित्तीय अपराधों से निपटने के लिए केवल स्वैच्छिक दिशा-निर्देश पर्याप्त नहीं होंगे, बल्कि बाध्यकारी और दंडात्मक प्रावधान आवश्यक हैं।

न्यायालय ने अपेक्षा व्यक्त की कि आगामी नियमों में बैंकिंग संस्थानों के लिए स्पष्ट जवाबदेही, संदिग्ध लेन-देन की निगरानी, समयबद्ध रिपोर्टिंग तथा पीड़ितों को मुआवजा प्रदान करने संबंधी प्रावधान शामिल किए जाएंगे।

**राज्यों और पुलिस एजेंसियों को भी निर्देश**

सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों को निर्देश दिया है कि वे डिजिटल अरेस्ट मामलों में दर्ज एफआईआर, जांच की वर्तमान स्थिति तथा अपराध की रोकथाम और प्रभावी अभियोजन के लिए सुझाए जाने वाले उपायों की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करें। इसके साथ ही यह जानकारी भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) को भी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है ताकि राष्ट्रीय स्तर पर साइबर अपराध के विरुद्ध रणनीति को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके।

सुप्रीम कोर्ट की यह पहल भारत में साइबर अपराधों के विरुद्ध एक व्यापक और संस्थागत ढांचे की स्थापना की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। न्यायालय ने स्पष्ट संकेत दिया है कि डिजिटल अरेस्ट जैसे अपराधों की रोकथाम केवल पुलिस या जांच एजेंसियों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्मों, बैंकों, नियामक संस्थाओं तथा कानून प्रवर्तन एजेंसियों को साझा उत्तरदायित्व निभाना होगा। न्यायालय की यह कार्यवाही भविष्य में अधिक सुदृढ़ साइबर सुरक्षा तंत्र, त्वरित पीड़ित सहायता और डिजिटल वित्तीय अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।

# 12 नवंबर 2026 - देशव्यापी स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन
## अखिल भारतीय वाहन चालक महासंघ का ऐलान




12 नवंबर 2026 - देशव्यापी स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन

अखिल भारतीय वाहन चालक महासंघ का ऐलान

देश के 22 करोड़ सारथी चालक भाइयों के सम्मान, सुरक्षा और हक के लिए अब आर-पार की लड़ाई!

जब तक मांगे पूरी नहीं, तब तक स्टीयरिंग नहीं!

**हमारी 5 मुख्य मांगे:**

1. ड्राइवर आयोग का गठन - चालकों के अधिकारों के लिए स्वतंत्र आयोग बने

2. ड्राइवर कल्याण बोर्ड - सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के लिए बोर्ड बने

3. 20 लाख दुर्घटना बीमा और 60 साल बाद पेंशन - हर चालक को सुरक्षा

4. ड्राइवर सुरक्षा कानून - दुर्घटना में अपराधी नहीं, निष्पक्ष जांच हो, मारपीट और अवैध वसूली पर रोक

5. 1 सितंबर को राष्ट्रीय चालक दिवस घोषित कर सरकारी अवकाश

**नोट:** यह आंदोलन शांतिपूर्ण, अहिंसक और लोकतांत्रिक रहेगा। एम्बुलेंस, फायर, पुलिस जैसी आपातकालीन सेवाएं जारी रहेंगी।

अबकी बार आर-पार, ड्राइवर एकता जिंदाबाद!

> सभी सारथी भाइयों से अपील

> दिनांक 12 नवंबर 2026 को सुबह से अपने सभी वाहन खड़े कर दें।

> अखिल भारतीय वाहन चालक महासंघ के द्वारा स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन शुरू हो रहा है।

> ये लड़ाई हमारे बच्चों के भविष्य की है, हमारे सम्मान की है।

> सरकार ने कई बार आश्वासन दिया पर वेलफेयर बोर्ड नहीं बना।

> अब बिना लिखित आश्वासन के स्टीयरिंग नहीं उठाएंगे।

**3. नारे (Slogans)**

- ड्राइवर एकता जिंदाबाद!
- अबकी बार आर-पार, नहीं तो कभी नहीं!
- सड़क का सिपाही हूं, भिखारी नहीं - सम्मान दो!
- 20 लाख बीमा हमारा हक है, भीख नहीं!
- चालक नहीं तो चक्का जाम, चक्का जाम तो भारत बंद!

- निवेदक- अखिल भारतीय वाहन चालक महासंघ भारत के समस्त सारथी गण

# झारखंड वन विभाग में बड़े पैमाने पर फेरबदल

**कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड -झारखंड**

**रांची** झारखंड सरकार ने वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है. सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के तहत भारतीय वन सेवा के 39 अधिकारियों का तबादला पदस्थापन हुआ है. साथ ही कई अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार भी दिए गए हैं. 1994 बैच के राजकुमार वाजपेयी को अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, रांची के पद पर पदस्थापित किया गया है. इसके अलावा उन्हें पलामू, हजारीबाग, रांची और दुमका के निदेशक, प्रसार वानिकी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है.95 बैच के जब्बर सिंह को स्थानांतरित करते हुए अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैंपा, रांची के पद पर पदस्थापित किया गया है. इसके पहले जब्बर सिंह बिरसा जैविक उद्यान, रांची के निदेशक थे. वहीं कर्मा जिंपा भुटिया को अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास, रांची की जिम्मेदारी दी गई है. वहीं 1999 बैच के सिद्धार्थ त्रिपाठी को झारखंड राज्य वन विकास निगम लिमिटेड का प्रबंध निदेशक बनाया गया है. उनको अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, एफडीए रांची का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है. वहीं एसआर नटेश को मुख्य वन संरक्षक, सतर्कता, रांची का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है.

वर्तमान में उनके पास मुख्य वन संरक्षक, वन प्राणी, रांची की जिम्मेदारी है. साथ ही एसआर नटेश पीटीआर के भी निदेश हैं. इसके अलावा आर थंगा पांडेयन को महाप्रबंधक लघु वन विकास निगम, हजारीबाग का अतिरिक्त प्रभार मिला है. वहीं पीआर नायडु को प्रोन्नति देते हुए क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, रांची की जिम्मेदारी दी गई है.

साथ ही डॉ. वी बासकरन, ममता प्रियदर्शी, सबा आलम अंसारी, अभिषेक कुमार, प्रवेश अग्रवाल, कुमार आशीष, विजय शंकर दुबे, सौरभ चंद्रा, विनय कांत मिश्रा, विकास कुमार उज्जवल, सत्यम कुमार, अविरुप सिन्हा, आदित्य नारायण, मुकेश कुमार, नीतीश कुमार, सौमित्र शुक्ला, विकास पालीवाल, राहुल कुमार, बनकर अजिंक्य देवीदास, सात्विक, अहमद बेलाल अनवर, राहुल मीणा, अशुंमान, एबिन बेनी अब्राहम, शिंदे संदीप कारभारी, पुष्कर काले, आदर्श शरण, अनुराधा मिश्रा, मोहित कुमार बंसल, नवनीत बीआर और श्वेताब सुमन के नाम शामिल है।

# झामुमो प्रवक्ता पर टोटों थाना प्रभारी का दुर्व्यवहार, गीता ने सरकार पर उठाए सवाल

आदिवासी विरोधी अधिकारियों पर जबाबदेही सुनिश्चित करे सरकार :गीता बालमुचू ,जिलाध्यक्ष प0सिंहभूम

**कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड -झारखंड**



**रांची** : टोंटो थाना प्रभारी पर झामुमो के जिला प्रवक्ता एवं झारखंड आंदोलनकारी बुधराम लागुरी के साथ कथित दुर्व्यवहार का आरोप लगने के बाद भाजपा जिलाध्यक्ष गीता बालमुचू ने राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जब जिले के सांसद, विधायक और मंत्री सत्ताधारी गठबंधन से हैं और राज्य में भी झामुमो की सरकार है, तब सत्ताधारी दल के पदाधिकारियों को ही पुलिस के कथित दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ रहा है। गीता बालमुचू ने कहा कि भाजपा जिले में बिगड़ती कानून-व्यवस्था, पुलिस की ज्यादती, बढ़ते अपराध, अवैध खनन और नशाखोरी के मुद्दे लगातार उठाती रही है। उन्होंने नो-एंट्री के विरोध में धरना दे रहे ग्रामीणों पर हुए लाठीचार्ज का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय झामुमो नेताओं की चुप्पी भी चर्चा का विषय रही थी। अब अपने ही संगठन के नेताओं के साथ कथित दुर्व्यवहार के बाद झामुमो को प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाने पड़ रहे हैं। उन्होंने मंत्री दीपक बिरुवा, जिले के सांसदों-विधायकों और राज्य सरकार से पूछा कि जिले में पुलिस प्रशासन किसके नियंत्रण में है? जब सत्ताधारी दल के नेताओं की आवाज भी थाने में नहीं सुनी जा रही है, तो आम गरीब और आदिवासी जनता न्याय की उम्मीद किससे करे? उन्होंने सरकार से पुलिस प्रशासन की जवाबदेही सुनिश्चित करने की मांग की।

# हजारीबाग नगर आयुक्त द्वारा प्रेस क्लब के अध्यक्ष के साथ दुरव्यवहार

टेंडर में गड़बड़ी की खबर छापने पर आयुक्त कागजात मांग कर हड़काने पहुंचे थे क्लब, अब चहुंओर निंदा

**कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड - झारखंड**

**रांची,** हजारीबाग के नगर आयुक्त ओमप्रकाश गुप्ता और प्रेस क्लब के बीच दस्तावेजों की जांच को लेकर तीखा विवाद हुआ था। जिसका अब चहुंओर विरोध हो रहा है ।

पत्रकारों ने नगर निगम द्वारा 9 लाख रुपये का काम पहले ही करवा लेने और उसके बाद टेंडर जारी करने से जुड़ी एक खबर प्रकाशित की थी। इस खबर से नाराज होकर नगर आयुक्त ओमप्रकाश गुप्ता अपनी टीम के साथ हजारीबाग प्रेस क्लब पहुंचे।

नगर आयुक्त ने प्रेस क्लब भवन से संबंधित कागजात और दस्तावेजों की जांच की मांग की ।प्रेस क्लब के अध्यक्ष मुरारी सिंह और वहां मौजूद पत्रकारों के साथ नगर आयुक्त की तीखी बहस हुई। पत्रकारों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों (जैसे हजारीबाग के मेयर अरविंद कुमार राणा और सांसद मनीष जायसवाल )फिर विधायक ने इस कार्रवाई का विरोध किया और इसे पत्रकारों पर दबाव बनाने का प्रयास की बड़े शब्दों निंदा की ।

इसके बाद पत्रकारों ने नगर आयुक्त की कार्यशैली के विरोध में प्रदर्शन किया और उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा।

देखा जाय तो हजारीबाग में नगर निगम और पत्रकारों के बीच सामने आया घटनाक्रम अत्यंत चिंताजनक एवं दुर्भाग्यपूर्ण है गणतंत्र के लिए ।

लोकतंत्र में पत्रकारिता केवल समाचार प्रकाशित करने का माध्यम नहीं, बल्कि सत्ता और प्रशासन को जवाबदेह बनाने का सशक्त स्तंभ है। छठ जैसे महापर्व से ठीक पहले घाटों पर स्टोन डस्ट बिछाने के लिए लगभग 9.5 लाख रुपये का टेंडर निकाला गया, तो इसकी समयबद्धता, औचित्य और जनहित को लेकर पत्रकारों का सवाल उठाना पूरी तरह स्वाभाविक है।



देखा जाय तो किसी प्रशासनिक निर्णय पर पत्रकार सवाल पूछते हैं, तो उसका उत्तर तथ्यों और पारदर्शिता के साथ दिया जाना चाहिए। लेकिन सवालों का जवाब देने के बजाय नगर आयुक्त का पूरी टीम के साथ प्रेस क्लब पहुंचना और पत्रकारों से संस्था के कागजात मांगना अनेक सवाल खड़े करता है।

पत्रकारिता को प्रशासन की अनुमति या कृपा की आवश्यकता नहीं है। पत्रकारों का काम सत्ता की प्रशंसा करना नहीं, बल्कि जनहित में उसकी नीतियों, निर्णयों और कार्यप्रणाली की समीक्षा करना भी है।

प्रशासनिक पद की गरिमा जवाबदेही से बढ़ती है, दबाव बनाने से नहीं। पत्रकारों की कलम को दबाने का कोई भी प्रयास लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप नहीं हो सकता।



स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023